न्याय एक तरह से हमारे जीवन का बीमा है और उसका पालन करना उसकी किस्त, जिसे हम चुकाते हैं। -विलियम पेन

एशियाई देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग जारी करने वाली प्रतिष्ठित संस्था क्यूएस की ताजा रैंकिंग में लगातार दूसरे वर्ष चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों को जगह मिलना वाकई सुखद है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है।

उपलब्धि और चुनौती

प्रतिष्ठित क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग-2025 में भारत के सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों को जगह मिलना वाकई सुखद है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियों की ओर इशारा करता है। इससे पहले 2023 में आईआईटी बॉम्बे ने भारत में अपनी शीर्ष रेटिंग बनाए रखते हुए एशिया में चालीसवां स्थान प्राप्त किया था। लेकिन इस बार वह खिसक कर 48वें स्थान पर आ गया है, जबकि आईआईटी दिल्ली ने 44वां स्थान हासिल किया है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अकादमिक प्रतिष्ठा, शिक्षक-छात्र अनुपात, नियोक्ता की प्रतिष्ठा, शोध का स्तर और अंतरराष्ट्रीय छात्र व शिक्षक अनुपात जैसे पैमानों पर एशिया के उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग करने वाली ब्रिटेन स्थित इस संस्था ने एशिया के उच्च शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन कर 983 शीर्ष संस्थानों की सूची जारी की है। बेशक इसमें पिछले साल के 148 संस्थानों की तुलना में इस बार 163 भारतीय शिक्षण संस्थानों ने जगह बनाई है, यहां तक कि क्यूएस-रैंकिंग के संचालकों ने शोध की उत्पादकता को लेकर भारतीय संस्थानों की प्रशंसा भी की है, इसके बावजूद समग्रता में देखें, तो चुनौतियां भी दिखती हैं। शीर्ष सौ संस्थानों में भारत के केवल सात संस्थानों को ही जगह मिल सकी है। यह तो एशिया के संस्थानों की सूची है, क्यूएस की वैश्विक सूची में, जिसकी रैंकिंग अलग से जारी की जाती है, तो भारत की स्थिति और भी खराब है। अलबत्ता आईआईटी दिल्ली, जेएनयू और गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय ने जिस तरह से अपनी रैंकिंग में सुधार किया है, वह इन संस्थानों में पढ़ने वाले हजारों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का काम कर सकता है। हम इस बात से भी खुश हो सकते हैं कि रैंकिंग में प्रतिनिधित्व करने के लिहाज से भारत लगातार दूसरे वर्ष चीन से आगे बना हुआ है। यह दीगर बात है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी शीर्ष पर

बनी हुई है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः हांगकांग व सिंगापुर के संस्थान हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, विशिष्ट संस्थान योजना और इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन व टेक्नोलॉजी जैसी पहलों ने निस्संदेह भारत में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा दी है, लेकिन हमारे संस्थानों को अनुसंधान के क्षेत्र में अधिक निवेश की आवश्यकता तो है ही, विद्यार्थियों के लिए अधिक समावेशी, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ते रहने की भी जरूरत है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने जिस पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है, उम्मीद है कि वह मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता देकर देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति साबित होगी।

बात दूर तलक जाएगी

निजी संपत्ति के सार्वजनिक हित में सरकार के अधिग्रहण करने के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला एक मिसाल है। नए फैसले और स्पष्टीकरण से महाराष्ट्र के अलावा, दूसरे राज्यों के कानून पर भी असर पड़ेगा और यह तय होगा कि सरकार कब और किस हद तक निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

ऋग्वेद में कहा गया है, 'एकं सत विप्रा बहुधा वदन्ति'। यानी एक ही सत्य को बुद्धिमान लोग अलग-अलग तरीके से बताते हैं। निजी संपत्ति के सार्वजनिक हित में सरकार के अधिग्रहण करने के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों का नया फैसला वैसी ही एक मिसाल है। फैसले का महत्व समझने से पहले 40 साल से चल रहे विवाद को समझना जरूरी है। मुंबई में पुराने जीर्ण शीर्ण भवनों से लोगों को खतरे से बचाने और आवास की समस्या के समाधान के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 1986 के म्हाडा कानून में बदलाव किए। साठ साल पुरानी 15,000 से ज्यादा इमारतों के कई मालिकों ने नए कानून को हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील

सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों ने बहुमत से उनके हक में फैसला दिया है, पर चार दशक की मुकदमेबाजी के बाद आए इस फैसले से मकानमालिकों को कितनी राहत मिलेगी? अभी तक 17 मामलों में नौ जजों की संविधान पीठ बनी है। संविधान पीठ के फैसले के अनुसार, दो या तीन जजों की पीठ मुख्य मामलों में फैसला सुनाती है। इसलिए इस फैसले के बाद भी लोगों को न्याय मिलने में और समय लग सकता है। दादा मुकदमा दायर करे, बेटा लड़े और पोते के समय फैसला आए, लेकिन न्याय नहीं मिले। न्यायिक विलंब के इस देशव्यापी वायरस से मुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के आगामी चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

इस मामले में संविधान पीठ के सामने दो अहम सवाल थे। पहला संसद से संविधान संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के बाद संपत्ति के मौलिक अधिकारों से जुड़े अनुच्छेद 31-सी की सांविधानिक स्थिति क्या है? दूसरा लोगों की भलाई और समानता के लिए संसाधनों के न्यायसंगत वितरण के बारे में अनुच्छेद 39 के दायरे में क्या सभी निजी संपत्तियों को शामिल किया जा सकता है? सेवानिवृत्त हो रहे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने सात अन्य जजों के साथ बहुमत के फैसले में कहा कि हर निजी संपत्ति को समुदाय के भौतिक संसाधन मानकर सरकार उनका अधिग्रहण नहीं कर सकती, जबकि

असहमति के फैसले में जस्टिस धूलिया ने कहा कि भौतिक संसाधनों को नियंत्रित और वितरित करने के बारे में कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है और उसमें न्यायिक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

मुख्य फैसले से सहमत होने वाली जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए 130 पन्नों का अलग फैसला लिखा है। सनद रहे कि जस्टिस नागरत्ना कुछ साल बाद देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। वर्ष 1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर के अल्पमत के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संस्था व्यक्तिगत जजों के व्यक्तिगत धारणाओं से ज्यादा बड़ी है। जस्टिस धूलिया के अनुसार, कृष्णा अय्यर के सिद्धांतों ने अंधकार भरे समय में देश का मार्गदर्शन दिया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस नागरत्ना ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की जिस टिप्पणी से असहमति जताई, वह मुख्य फैसले में शामिल नहीं थी। लगता है कि ड्राफ्ट फैसले में बदलाव करके चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी टिप्पणी वाले अंश को हटा दिया था। यदि यह बात फैसला सुनाने से पहले जस्टिस नागरत्ना को बता दी जाती, तो असहमति के लंबे फैसले और न्यायिक जगत में चल रहे विवाद से बचा जा सकता था।

भारत सरकार अधिनियम 1935 और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के अनुसार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19 (1) (एफ) के माध्यम से मान्यता मिली थी, लेकिन निजी संपत्ति पर लोगों के अधिकार और उसके अधिग्रहण के बारे में सरकार की सीमाओं पर आजादी के बाद से ही संसद और अदालत में विवाद चल रहे हैं। जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों जैसे विषयों को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के समय पहला संविधान संशोधन हुआ था। उसमे अनुच्छेद 31 में संशोधन करने के साथ नवमी अनुसूची शामिल की गई, जिसमें भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानूनों को न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान था। भूमि सुधारों को लागू करने के लिए साल 1964 में 17वां संविधान संशोधन किया गया। बैंकों के राष्ट्रीयकरण और समाजवादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इंदिरा सरकार ने संविधान में 25वां और 42वां संशोधन किया। जनता पार्टी की सरकार ने साल 1978 में 44वें संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300-ए के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया, लेकिन इस पूरी कवायद से सिर्फ यह फर्क पड़ा कि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाईकोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है।

कई संविधान संशोधन व अदालत के फैसलों के बाद कुछ बातें साफ हो गईं। पहला, संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन संपत्ति का अधिकार सांविधानिक अधिकार है। अधिग्रहण की प्रक्रिया को सिर्फ कानून के शासन के दायरे में निर्धारित किया जा सकता है। इसलिए संपत्ति का अधिकार अप्रत्यक्ष तौर पर संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। दूसरा लोकहित में सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, पर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन कर मुआवजा देना जरूरी है। नोटिस, सुनवाई और लिखित आदेश के बगैर चल या अचल संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक और नया फैसला उल्लेखनीय है। उसके अनुसार अवैध निर्माण हटाने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। तीसरा अनुच्छेद 39-बी के मुताबिक, सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के संसाधनों को इस तरह से बांटे कि वे सभी की भलाई के काम आएं, लेकिन इसके लिए सभी निजी संपत्ति के अधिग्रहण और नियंत्रण का सरकार को अधिकार नहीं है। अब निजी संपति को समुदाय के भौतिक संसाधन के योग्य मानने के पहले अनेक परीक्षण करने के साथ कानून से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं का पूरा पालन जरूरी होगा। आर्थिक संसाधनों के समान वितरण के लक्ष्य को पाने के लिए संपत्ति पर जनता के सांविधानिक अधिकारों के साथ संतुलन बनाना जरूरी है।

इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान 42वें संशोधन से संविधान में समाजवाद शब्द जोड़ा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में अभी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नजीर माना जाए, तो आर्थिक उदारवाद और बाजारवाद को न्यायिक मान्यता मिलने से उस मामले की सुनवाई भी नौ या ज्यादा संख्या जजों की पीठ द्वारा होनी चाहिए। यूपीए और एनडीए, दोनों सरकारों को भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानून बनाने और लागू करने में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले और स्पष्टीकरण से महाराष्ट्र के अलावा, दूसरे राज्यों के कानून पर भी असर पड़ेगा और यह तय होगा कि सरकार कब और किस हद तक निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

मोपासां

सपने यात्रा की तरह हैं, जो वास्तविक दुनिया से परे हमें ऐसी दुनिया की ओर ले जाते हैं, जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। सपने नए विचारों की ओर ले जाते हैं, जो निश्चित ही दुनिया का सबसे मधुर अनुभव हैं।

आज का सपना कल की हकीकत

पांच पुराने दोस्त, एक लेखक, एक डॉक्टर और तीन अमीर अविवाहित, जो कुछ खास नहीं कर रहे थे, साथ में खाना खा रहे थे। उन्होंने हर बात पर चर्चा की, और फिर उन पर एक सुस्ती की भावना छा गई। उनमें से एक, जो पिछले पांच मिनट से सड़क पर लगे गैस-लैंप को चुपचाप देख रहा था, अचानक बोला, 'जब कोई काम नहीं होता, तो दिन और रात लंबे लगते हैं।' उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने इस बात पर सहमति जताई। वह बोला, 'मैं बहुत कम सोता हूं, हमेशा थकावट महसूस करता हूं और बातचीत नीरस लगती है।' तीसरे व्यक्ति ने टिप्पणी की, 'मैं किसी ऐसी चीज के लिए बहुत अधिक खर्च करने के लिए भी तैयार हूं, जो मुझे हर दिन केवल दो घंटे शांति से बिताने में मदद करे।' एक मिनट विराम के बाद वह फिर बोला, 'अगर हम बगैर सपनों वाली अच्छी नींद लें, उस पूर्ण बेहोशी के साथ सोएं, जो हम रात में अनुभव करते हैं, जब हम पूरी तरह से थके हुए होते हैं, तो शांति मिल सकती है।' 'सपनों के बिना क्यों?' उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने पूछा। दूसरे ने उत्तर दिया, 'क्योंकि सपने हमेशा सुखद नहीं होते हैं। वे हमेशा शानदार, असंभव और बेमेल होते हैं। चूंकि जब हम सो रहे होते हैं, तो हम सिर्फ उस तरह के सपने नहीं देख सकते, जो हमें पसंद हैं। इसलिए हमें जागते हुए सपने देखने चाहिए।'

सारी बातों को सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए डॉक्टर ने कहा कि मेरे प्यारे मित्रो, जागते हुए सपने देखने के लिए हमें बहुत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, और तुम ऐसा दबाव में आकर करने की कोशिश करते हो, तो परिणाम बहुत थकावट भरा हो सकता है। हालांकि यह निश्चित रूप से यह दुनिया का सबसे मधुर अनुभव है, लेकिन यह स्वाभाविक तरीके से आना चाहिए, इसे दबाव या ऊपरी मन से उकसाया नहीं जाना चाहिए। सपने यात्रा की तरह हैं, जो वास्तविक दुनिया से परे हमें ऐसी दुनिया की ओर ले जाते हैं, जिसे अभी खोजा जाना बाकी है। वहां मौजूद सभी ने इन बातों पर सहमति जताई। लेखक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एक इन्सान क्या है? सब कुछ और कुछ भी नहीं। हम सभी अपने विचार की शक्ति के माध्यम से अपने सभी अनुभवों को जीवन के दर्पण में देख सकते हैं। हमारी स्मृति और ज्ञान के माध्यम से यह एक सूक्ष्म जगत बन जाता है। यानी प्रत्येक मनुष्य ब्रह्मांड के भीतर एक छोटा ब्रह्मांड बन जाता है। यहां हम सभी जीवन के रंगमंच पर अभिनेता हैं, जो अपनी क्षमता के अनुसार अपना किरदार निभाते हैं। मैंने कल रात्रि एक सपना देखा, जिसमें मैंने खाना खाया, काम किया और फिर मर गया। बीते हुए कल का यह सपना आने वाले कल की हकीकत है, क्योंकि जीवन का अंत मृत्यु ही है। आखिरकार सभी मित्रों ने एक साथ सहमति जताई और एक नए जीवन की शुरुआत करने की ठानी।

कंफर्ट जोन त्यागें

सूत्र

हकीकत में जिएं। अपना प्यार जताएं। अपना उत्साह बांटें। अपने सपनों की दिशा में कदम उठाएं। अपनी बात पर अमल करें। संगीत पर नाचें और गाएं। ध्यान रहे कि कंफर्ट जोन, एक ऐसा क्षेत्र है, जहां महान सपने मारे जाते हैं, दफना दिए जाते हैं और भुला दिए जाते हैं। इस क्षेत्र से बाहर निकलें।

हिंदी के लोकप्रिय साहित्य जगत के अनमोल सितारे वेद प्रकाश कांबोज बुलंदियों पर पहुंचकर भी खुद को पाठक ही मानते थे।

स्मृति-शेष

लोकप्रिय लेखन का प्रयोगधर्मी सितारा

हिंदी के लोकप्रिय साहित्य जगत ने अपने अनमोल सितारे वेद प्रकाश कांबोज को खो दिया। आजीवन खुद को पाठक मानने वाले इस दिग्गज लेखक ने उपन्यासों के जरिये अपने पाठों विजय-रघुनाथ, अलफांसे व सिंगही को अमर बना दिया। 18 साल की उम्र में पहला जासूसी उपन्यास कंगूरा लिखने वाले वेद प्रकाश कांबोज ने 400 से अधिक उपन्यास लिखे और क्या खूब लिखे कि उनकी धड़ाधड़ नकल भी होने लगी। यहां तक कि जब उन्होंने अपने एक पात्र को मारा, तो जनता की मांग पर उसे फिर जिंदा करना पड़ा। वह इन्हें सभी से प्रभावित थे और उनके पात्र विजय और रघुनाथ सफी से ही प्रेरित थे। हिंदी साहित्य के इस अप्रतिम जासूसी और अपराध कथा लेखक का जन्म एक दिसंबर, 1939 को शाहदरा, दिल्ली में एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। 1960-90 के दशक में अपार सफलता पाने वाले वेद प्रकाश कांबोज की रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। जब नई सदी के साथ उन्होंने जासूसी लेखन से गंभीर साहित्य की ओर रुख किया, तो वहां भी सफल हुए। उनकी पौराणिक और ऐतिहासिक रचनाओं में बाबा फरीद, विवेकानंद, महावीर जैन, गौतम बुद्ध, चाणक्य, चंद्रगुप्त, अशोक और दयानंद सरस्वती जैसे महान व्यक्तित्वों पर आधारित कृतियां शामिल हैं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और इतिहास से पाठकों को परिचित कराया है।

वेद प्रकाश कांबोज
1-12-1939 से 6-11-2024

1960-90 के दशक में अपार सफलता पाने वाले कांबोज की रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। जब उन्होंने जासूसी लेखन से गंभीर साहित्य की ओर रुख किया, तो वहां भी खूब सफल हुए।

साहिर के गीत *मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया* को अपने जीवन का फलसफा मानने वाले कांबोज ने कभी किसी बीती बात पर अफसोस नहीं किया। 'बीती ताहि बिसार दे आगे की सुध ले' ही उनकी लंबी पारी का आधार था। अंतिम वर्षों में वे नए और उदीयमान लेखकों के लिए एक गुरु और मार्गदर्शक की तरह अपना फर्ज निभाते रहे। कहते थे, जो अपने गुरुजनों पन्नालाल पाठक, जवाहर चौधरी और ओमप्रकाश शर्मा से ग्रहण किया, उसे आगे देने में कैसा संकोच! उन्होंने कभी भी प्रकाशकों के दबाव में अपने कथानकों और लेखन के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनके अनुसार, जैसे एक रसोइया अपने व्यंजन को अपने खास अंदाज से तैयार करता है, और फिर उसी खास तरीके से सजाता और परोसता है, वैसे ही लेखक भी करता है और उसे करना भी चाहिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन ही महत्वपूर्ण होता है। उनकी कृतियां *फिरऔण्या उग्र-गाथा* और नवीनतम रचना *खलिक बदनाम* अपने अनूठे विषयों और प्रस्तुति के कारण विशेष चर्चा में रहीं। अपने लेखन से हिंदी पल्प फिक्शन को एक नई दिशा देने वाले वेद प्रकाश कांबोज का प्रयोगधर्मी लेखन और साहित्य में उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा।

-राम पुजारी (*'कांबोजनामा' के लेखक*)

आंकड़े

विदेशी विद्यार्थी

भारत आदिकाल से शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी दुनिया भर के देशों के विद्यार्थी भारत में शिक्षा हासिल करने के लिए आते हैं।

नेपाल	28.25%
अफगानिस्तान	8.4%
बांग्लादेश	5.3%
अमेरिका	5.1%
यूएई	4.8%

आंकड़े भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के, प्रतिशत में | स्रोत : UGC

भक्त विप्रनारायण की भक्ति को और मजबूत करने के लिए भगवान ने लीला रचकर पहले तो देवदेवी के मोह में फंसाया और फिर उससे बाहर भी निकाला।

विप्रनारायण की भक्ति

अंतर्यात्रा
संकलित

विप्रनारायण श्रीरंगजी के मंदिर के बगीचे से फूल लाकर भगवान को अर्पण किया करते थे। वहां देवदेवी नाम की रूपवती रहती थी। एक दिन वह अपनी बहन के साथ बगीचे में आई। उन्होंने देखा कि विप्रनारायण भगवान का नाम लेते हुए तुलसी के पौधों को सींच रहे थे। वह भगवान की भक्ति में इतने लीन थे कि उनकी नजर देवदेवी की ओर नहीं गई। देवदेवी की बहन बोली-जो भगवान की भक्ति में लीन हो। वह एक नारी के रूप को देखकर आसक्त कैसे हो सकता है? देवदेवी ने कहा, 'वह मेरे रूप के आगे आसक्त हो जाएगा।'

विप्रनारायण धीरे-धीरे देवदेवी के मोहजाल में फंस गए और उनका भगवान के प्रति ध्यान कम हो गया। प्रेम के मोह में वह सबकुछ भूल गए। एक रात्रि को देवदेवी के द्वार पर एक व्यक्ति ने कहा कि मैं विप्रनारायण का सेवक हूं और यह सोने का थाल आपके लिए है। दूसरे दिन पता चला कि मंदिर से सोने का थाल गायब है। राजा ने पड़ताल कराई, तो थाल देवदेवी के घर से मिला। देवदेवी ने कहा कि विप्रनारायण के सेवक ने मुझे दिया, विप्रनारायण कहा कि मैं तो दीन-हीन हूं। राजा ने दोनों को हिरासत में रखा। उस रात राजा को स्वप्न में रंगनाथ जी ने दर्शन दिए और बोले कि यह सब मेरी ही लीला है, विप्रनारायण निर्दोष है। अगली सुबह राजा ने विप्रनारायण को मुक्त कर दिया। अंत में विप्रनारायण और देवदेवी, दोनों ही भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 07 जनवरी, 1962

विदेशी ताकत की मदद से सत्ता हथियाने का प्रयास

विदेशी ताकत की मदद से नेपाल में सत्ता हथियाने का प्रयास

नेपाल सम्राट महेंद्र ने पंचायत दिवस पर भाषण देते हुए अपने राजनीतिक विरोधियों पर आरोप लगाया कि वे एक विदेशी ताकत की मदद से नेपाल में सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हैं।

होनहारों को उच्च शिक्षा का वरदान

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के जरिये सर्व समाज के विद्यार्थियों को बिना गारंटी ऋण मिलने से उत्कृष्ट संस्थानों में पढ़ने का उनका सपना पूरा होगा।

बद्री नारायण — **शिक्षा**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार भारत में शिक्षा को सर्वांगीण विकास के एक महत्वपूर्ण उपादान के रूप में तब्दील करने में लगी है। इसके लिए जरूरी है कि देश में शिक्षा का अवसर सबको सहज ढंग से सुलभ कराया जाए। इसके लिए सबसे पहल नई शिक्षा नीति-2020 में भारत में शिक्षा को 'अपनी शिक्षा' और 'जनता के लिए शिक्षा' के रूप में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

नई शिक्षा नीति के तहत अंग्रेजी के आधिपत्य को कम कर भारतीय भाषाओं में शोध को महत्व देने की दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनेक कदम उठाने जा रहा है। मातृभाषा में ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया विकसित होने से इस प्रक्रिया में सभी के शामिल होने का रास्ता खुलेगा और यहा प्रक्रिया ज्यादा जनतांत्रिक भी हो सकेगी। भारत जैसे देश में शिक्षा के दरवाजे तक पहुंचने में एक बड़ी समस्या आती है धन की। अनेक बार होनहार युवाओं के समक्ष आने वाला आर्थिक

संकट उन्हें उत्कृष्ट शिक्षा लेने से वंचित कर देता है। आर्थिक अक्षमता युवाओं के शिक्षा तक पहुंचने के रास्ते में अनेक बाधाएं खड़ी करती है। इस समस्या को महसूस करते हुए सरकार द्वारा विद्यार्थियों के शिक्षा-ऋण लेने की प्रक्रिया को सहज एवं सुलभ बनाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। देश की बैंक व्यवस्था भी उसमें सहयोगी हो रही है।

हाल ही में भारत सरकार ने पीएम-विद्यालक्ष्मी नाम से एक उत्कृष्ट मेधा वाले प्रतिभावान छात्रों के लिए एक विशिष्ट शिक्षा ऋण की नई योजना को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत संभावनाशील योग्य युवाओं के लिए देश के उत्कृष्ट रैंकिंग वाले 860 शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने के लिए बिना किसी गारंटी के ऑनलाइन प्रक्रियाओं के तहत सहज और शीघ्र शिक्षा ऋण दिया जाएगा। भारत सरकार की इस नीति के तहत प्रतिवर्ष देश के 20 लाख से ज्यादा प्रतिभावान विद्यार्थियों को यह विशिष्ट ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें एक प्रकार से सरकार ही गारंटर की भूमिका निभाएगी। यह ऋण मामूली ब्याज पर छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की व्यापक परियोजना और विजन का हिस्सा है। प्रतीकात्मक अर्थों में देखें, तो इस योजना में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इस सरकार और जनतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में ऐसे उत्कृष्ट मेधा वाले युवाओं को उत्कृष्ट शिक्षा के लिए आर्थिक साधन उपलब्ध कराने के लिए गारंटर बनकर उभरते दिखते हैं।

ऋण लेने के लिए गारंटर की जरूरत खत्म करने और सहज ढंग से घर बैठे डिजिटली ऋण लेने की सुविधा होने से छात्र स्वतः उत्कृष्ट संस्थानों से शिक्षा ले पाएंगे। फलतः आज शिक्षा ऋण लेकर शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या, जो अभी तीन लाख के आसपास है, उसमें काफी वृद्धि होगी। इस संदर्भ में ऋण मात्र ऋण न होकर युवाओं में उत्कृष्ट कोटि के शिक्षा संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता के विकास के एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। यूं भी अगर भारत में जनतंत्र और विकास के इतिहास को देखें, तो बैंक ऋण सुलभ करा के सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाओं द्वारा विकास की गति को विभिन्न सरकारों ने विभिन्न काल खंडों में बढ़ाया है। अगर सरकारी सहयोग के रूप में यह ऋण उपलब्ध न होते, तो ऐसे समुदाय अभी भी जनतंत्र के दरवाजे से काफी दूर होते।

मैं जब यह कर रहा हूं, तो भारतीय समाज में उन मध्य, पिछड़े एवं दलित समुदायों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक बैंक ऋण से अपने विकास की गति तेज की है। इस पर कुछ महत्वपूर्ण शोधों से आए आंकड़ों से इस तथ्य की पुष्टि भी होती है। इस संदर्भ में मैं राजनीति विज्ञानी प्रो. आशीष बनर्जी का जिक्र करना चाहता हूं, जिन्होंने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम में फेलो रहते इस विषय पर एक महत्वपूर्ण शोध किया था। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के रूप में ऐसे आर्थिक सहयोगों ने समूहों, समुदायों एवं लोगो के विकास एवं गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नियोजन के इस पक्ष पर गहन शोध होना अभी बाकी है।

बाबा साहेब आंबेडकर ने शिक्षा को दलित और पिछड़ों की मुक्ति का महत्वपूर्ण हथियार माना था। भारतीय जनतंत्र के फ्रेम में कार्यरत किसी भी सरकार का दायित्व है कि आर्थिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए सरकारी समर्थन के रूप में अनेक योजनाएं लाकर उन्हें शिक्षा के परिसर से जोड़ें। उम्मीद है कि पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना का लाभ सर्व समाज के प्रतिभावान विद्यार्थियों को मिलेगा। उनके लिए देश के उत्कृष्ट शिक्षा संस्थानों में जाकर शिक्षा लेने का सपना पूरा हो पाएगा।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 8 नवम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

ज्ञानी जन विवेक से सीखते हैं, साधारण मनुष्य अनुभव से, अज्ञानी पुरुष आवश्यकता से और पशु स्वभाव से
-कौटिल्य

ट्रंप के आने के मायने

रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने बहुमत के जादुई आंकड़ों से अधिक मत हासिल किए हैं जो अमेरिकी समाज में उनकी लोकप्रियता के दर्शाता है। वह 2016 में भी चुनाव जीते थे। उनकी यह दूसरी जीत इसलिए भी विशेष मायने रखती है कि इस बार उनकी पार्टी को सीनेट में भी बहुमत मिल गया है। चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना ने अमेरिकी समाज को गहरे तक झकझोर दिया था। हमले के समय ट्रंप ने जैसी हिम्मत और दिलेरी दिखाई थी उसे अमेरिकी मतदाता बहुत प्रभावित हुआ था। आम लोगों में या धारणा बनी कि आज की अस्थिर और संघर्ष से जूझ रही

दुनिया में ट्रंप जैसे दृढ़ संकल्प वाले नेता की जरूरत है। उनकी ऐतिहासिक जीत में ट्रंप के व्यक्तित्व के इस करिश्माई पहलू की बड़ी भूमिका रही है। चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में डेमोक्रेटिक पार्टी के दो बड़े नेताओं ने ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा करके हलचल मचा दी। कमिंडी परिवार के सदस्य रॉबर्ट एस कैनेडी ट्रंप के समर्थन में आ गए। जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक वह पांच फीसद मतदाताओं की पसंद थे। उनके पहले बदलने से कड़ी टक्कर वाले 'स्विंग स्टेट' ट्रंप को भारी सफलता मिली। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी की एक और पूर्व नेता तुलसी गबार्ड ने भी ट्रंप को समर्थन देने की घोषणा की। सैनिक होने के बावजूद तुलसी युद्ध विरोधी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत का असर अमेरिका की घरेलू राजनीति के साथ वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। घरेलू स्तर पर अमेरिकी समाज और राजनीति में ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। विदेश मोर्चे पर ट्रंप बाइडेन प्रशासन से अलग राह पकड़ सकते हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्होंने कहा कि 'मैं युद्ध शुरू नहीं करूंगा बल्कि रोकने की कोशिश करूंगा।' उनकी इस घोषणा से उम्मीद बनती है कि रूस-यूक्रेन युद्ध अब जल्द समाप्त होगा। ट्रंप भारत को ट्रंप से काफी अपेक्षाएं भी हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि बाइडेन प्रशासन की शह पर कनाडा जिस तरह से भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है उस पर रोक लगेगी। हालांकि ट्रंप मनमौजी की किस्म के व्यक्ति हैं। वह किसी मुद्दे पर क्या रुख अपनाएंगे यह कहना मुश्किल है। फिर भी ट्रंप की नीतियों से भारत के हित एक हद तक सधेंगे ऐसा कहा जा सकता है।

योगी सरकार को झटका

उत्तर प्रदेश के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई मायनों में ऐतिहासिक है। मदरसा कानून को निरस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा, मदरसा कानून अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रसार का प्रभावशाली जरिया है। इससे उनमें सुरक्षा व आत्मविश्वास पैदा होता है। अदालत ने कहा उप्र मदरसा अधिनियम 2004 के रोजमर्रा के कामकाज में हस्तक्षेप हैं करता बल्कि मदरसों के मानकीकरण में सहायक है। इस कानून को 2004 में मुलायम सरकार ने पास किया था। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया हाईकोर्ट ने इसी साल मार्च में मदरसा अधिनियम को

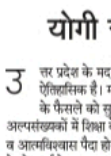

धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही उप्र सरकार को राज्य के अलग-अलग मदरसों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के भी निर्देश दिए थे। उप्र में तकरीबन पचीस हजार मदरसे चल रहे हैं। इनमें से सोलह हजार से ज्यादा को राज्य मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं। जबकि 560 को सरकार से अनुदान मिलता है। तकरीबन साढ़े आठ हजार मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। सबसे बड़ी अदालत के इस फैसले भाजपा सरकार को करारा झटका लगा है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी स्पष्ट किया कि हायर एजुकेशन को छोड़ कर मदरसा में चल रहे सभी कोई उच्च न्यायालय के फैसले से पूर्व वाले फैसले की तरह मान्य होंगे। सरकार का भेदभाव करना शोभा नहीं देता। जरूरी है कि इस शिक्षा प्रणाली को सुधारने के सकारात्मक प्रयास हों। ताकि मदरसों से निकलें छात्र उच्चतम शिक्षा पाने या बेहतर भविष्य का निर्माण करने में अपनी योग्यता का इस्तेमाल कर सकें। यूं भी शिक्षित व सम्पन्न मुसलमान परिवार अपने बच्चों को अंग्रेजी व प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं। वे मदरसों में शिक्षा दिलाने के प्रति तनिक इच्छुक नहीं होते। नई पौध को बेहतर शिक्षा मिले, जो उनके लिए उचित व ज्ञानवर्धक साबित हो, ऐसे प्रयास होने चाहिए। पूर्वाग्रहों से भरकर ऐसे कोई निर्णय जनता पर नहीं लादने चाहिए, जो उन्हें साम्प्रदायिक रूप से बांटने की बजाए सौहार्दपूर्ण माहौल प्रदान करने वाला हो।

कोटमराजू जयंती/के. विक्रम राव

पत्रकारिता की अनूठी शख्सियत

प्रख्यात सम्पादक, जाने-माने स्वाधीनता-सेनानी और प्रथम संसद (राज्य सभा) के सदस्य (1952), कोटमराजू रामा राव अपने दौर के अकेले ऐसे पत्रकार थे, जो 25 से अधिक समाचार-पत्रों में कार्यशील रहे। इन पत्र-पत्रिकाओं में अविभाजित भारत के लाहौर से प्रकाशित (लाला लाजपत राय का) दि पीपुल (1936), कराची का दैनिक दि सिंध आब्जर्वर (1921), मुम्बई का दि टाइम्स आफ इण्डिया (1924), चेन्नई का दि स्वराज्य (1935), कोलकाता का दि फ्री इण्डिया (1934), नई दिल्ली का दि हिन्दुस्तान टाइम्स (1938), इलाहाबाद के दि लीडर (1920) और दि पायोनियर (1928) तथा पटना का दि सर्चलाइट दैनिक (1950) थे। किंतु रामा राव जी को ऐतिहासिक ख्याति मिली जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के दैनिक दि नेशनल हेराल्ड (1938-1946) का लखनऊ में सम्पादन किया। देर सारे अखबार बदलने पर रामा राव के एक साथी ने टिप्पणी की : 'वे अपने एक जेब में संपादकीय की प्रति और दूसरे में त्यागपत्र रखते थे।'

चीराला (आंध्र प्रदेश) में 9 नवम्बर 1996 को जन्मे, तेलुगु-भाषी रामा राव ने मद्रास विश्वविद्यालय से 1917 में अंग्रेजी साहित्य से स्नातक परीक्षा पास की और वही अंग्रेजी भाषा का अध्यापन भी किया। पत्रकारिता में उनका प्रवेश चेन्नई में ब्रह्मसमाज की पत्रिका दि स्युमेनिटी से हुआ। फिर आचार्य टी. एल (साधु) वासवानी के दि न्यू टाइम्स (1919) में कराची में उन्होंने कार्य किया। अपने अग्रज, संपादक के. पुन्नय्या के दैनिक दि सिंध आब्जर्वर में सह-संपादक बने। चार दशक के अपने पत्रकारी जीवन में रामा राव ने दो विश्व युद्धों के दौर की घटनाएं, गांधी-नेहरू युग का स्वाधीनता-संघर्ष और स्वातंत्र्योत्तर भारत में आर्थिक नियोजन, निर्गुट विदेश नीति तथा मीडिया आधुनिकीकरण को देखा और उन पर लिखा। महात्मा गांधी के सान्निध्य में रहकर रामा राव ने दो दर्जन से ज्यादा भारतीय तथा अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के विशेष संवाददाता के रूप में राष्ट्रीय आंदोलनों की रपट भेजी। केंद्रीय विधान सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों तथा राजनीतिक मुकदमों और क्रिकेट टेस्ट मैचों की रिपोर्टिंग की। रामाराव के प्रशिष्य का नाम था श्री वालकृष्ण मेनन जो सन्यास लेकर स्वामी चिन्मानन्द सरस्वती कहलाए। 1942 में रामा राव को दि नेशनल हेराल्ड में 'जेल या जंगल' शीर्षक के संपादकीय लिखने पर ब्रिटिश हुकूमत ने छह माह का कारावास और जुर्माना की सजा दी थी।

ट्रंप की वापसी और भारत

अमेरिकी चुनाव

डॉ. सी.पी. राय

आखिर लंबी प्रक्रिया के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न हो गया और डोनाल्ड ट्रंप पिछला चुनाव हारने के बाद इस बार 132 साल बाद नया रिकार्ड बनाते हुए चुनाव जीत गए और सीनेट तथा हाउस में भी बहुमत पाने में सफल रहे। इनके पहले मिस्टर क्लीवलैंड ने 1884 के बाद 1892 में राष्ट्रपति का चुनाव इसी तरह जीता था। लोगों की निगाह इस बात पर भी थी की क्या अमेरिका अपने इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति का चुनाव करेगा और भारतीय तथा एशियाई लोगो की निगाह इस बात पर थी की क्या अमेरिका एक भारतीय मूल या एशियाई मूल की महिला का चयन अपने राष्ट्रपति के रूप में करेगा। पर ये दोनों उम्मीदें अब खत्म चुकी है।

पिछले कई महीनो से दुनिया की निगाहें अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव पर लगी थी। याद होगा की जब बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के बीच राष्ट्रपति पद की उम्मेदवारी का चुनाव था तो दोनों ने एक दूसरे पर खूब हमले किये थे लेकिन जब बराक ओबामा जीत गए तो पूरी पार्टी मिलकर उनके लिए काम करने लगी और बराक ओबामा के राष्ट्रपति बन जाने के बाद हिलेरी क्लिंटन उनके साथ विदेश मंत्री बन गयी।

इस बार का चुनाव कई मामलों में अलग था डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और वर्तमान राष्ट्रपति जॉय बिडेन को बीच चुनाव में मैदान छोड़ना पड़ा क्योकि पहली डिबेट में ही वो भूल जा रहे थे और उनपर उम्र का असर दिखने लगा तो उनकी पार्टी में ही उनपर सवाल उठने लगे और तब उन्होंने खुद पीछे हटते हुए अपनी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित कर दिया। इस मामले में कमला हैरिस को बो प्रचार तथा अवसर भी नहीं मिला जो प्राइमरी चुनाव के वक्त मिलता है और उन्हें प्रचार में उतरने का अवसर भी देर से मिला तथा कई कोनों से ये सवाल भी उठा की डेमोक्रेटिक उम्मेदवार होने का उनको बहुमत हासिल नहीं हैं, परंतु चुनाव शुरू हो चुका था तो विवाद के बजाय सभी चुनाव में लग गए। एक बात और देखने को मिली की कमला हैरिस के इस चुनाव में उनकी पार्टी के बराक ओबामा, मिसेस ओबामा, क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन सहित बड़ी संख्या में ट्रंप से नाराज कई रिपब्लिकन और काफी संख्या में सेलिब्रिटी गायकों, शेरो, शैरोइनों ने कमला हैरिस के पक्ष में प्रचार किया तथा नौजवानों का रुझान भी उनकी तरफ दिखा लेकिन फिर भी कड़ा मुकाबला करने के बावजूद वो चुनाव हार गईं। जहां कमला हैरिस के ऊपर देर से उम्मीदवार होने का असर दिखा वहीं उपराष्ट्रपति होने के नाते जो बाइडेन की असफलताओं और एंटी इनकम्बेंसी का असर

भी उनके चुनाव पर पड़ा क्योकि अमेरिका ने भी कोरोना की मार झेली थी और उसके बाद वहां का आम आदमी भी महंगाई की मार से त्रस्त है तथा पूर्व सरकार द्वारा यूक्रेन को भारी आर्थिक मदद से उसे दिक्कत है और इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया भी तथा ट्रंप ने जनता से ये सवाल भी पूछा कि उनकी सरकार में तो इतनी महंगाई नहीं थी।

ट्रंप ने ये भी प्रमुखता से कहा कि उनके समय में दुनिया में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ और वो युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप की नीति की अमेरिका की नौकरी और अवसरों पर पहला हक अमेरिकी लोगों का है तथा उनका अवैध इमिग्रेशन के खिलाफ सख्त रुख भी खासकर ग्रामीण लोगों और कस्बाई लोगों को आकर्षित करने में सफल रहा। ट्रंप ने अपनी और वर्तमान विदेश नीति को भी मुद्दा बनाया जो वोट के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। ऐसे प्रदेश जिन्हें स्विंग प्रदेश कहा जाता है जो कभी किसी को भी वोट देते रहे हैं, उनमें भी ट्रंप बढ़ाते बनाने में कामयाब रहे। क्लीवलैंड, जॉर्जिया, इंडियाना, केंटुकी, कैरोलिना, अलास्का, नेवादा और एरिजोना ने ट्रंप की जीत पर मुहर लगा दिया। कमला हैरिस आर्थिक मुद्दों पर कुछ खास बात नहीं कर पाईं जो उनके खिलाफ गया जबकि अभी हाल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गर्भपात पर रोक के आदेश पर जिसका भारी पैमाने पर विरोध हो रहा है। कमला हैरिस के रुख ने उनकी मदद की। क्योंकि हर अमेरिकी चुनाव में 'सिंगल मदर' एक बड़ा मुद्दा रहता है।

लैटिन और क्यूबन आबादी में ट्रंप बढ़त लेने में कामयाब रहे जो आश्चर्यजनक रहा। अमेरिकी श्वेत पुरुषों को ऐसा लगा की ट्रंप कमला के मुकाबले ज्यादा मजबूत राष्ट्रपति साबित होंगे और साथ ही बहुत वाद में कमला हैरिस समझ पाई कि उनकी सरकार की नीतियों से लोग खुश नहीं और अंतिम दौर में उन्होंने कहना शुरू किया कि उनकी नीतियां जो बाइडेन की नीतियों से अलग होगी। पर क्या होगी इस पर साफ कुछ नहीं बोल सकी और देर भी हो चुकी थी। परिणाम आ चुका है और ट्रंप राष्ट्रपति वन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन तथा इस्राइल के मामले में 20 जनवरी शपथ लेने के बाद वो क्या निर्णय लेते है। पाकिस्तान और इमरान खान पर उनका क्या रुख होता है। भारत से वहां जाकर काम करने के इच्छुक लोगो के एच 1 बी वीजा पर उनका क्या रुक होता है।

भारतीय सामानों के आयात पर पिछली बार टैक्स लगा दिया था, इस बार क्या करते हैं। चीन का सामान अमेरिका में भरा पड़ा है तो उसपर उनका क्या रुख होता है। चीन के खिलाफ भारत का वो इस्तेमाल करने का रुख रखते हैं या दोनों देशों से स्वतंत्र व्यवहार करते हैं और भारत के पक्ष में उनके पिटारे से क्या निकलता है; इत्यादि काफी सवाल हैं जिनका जवाब निकट भविष्य में मिलेगा। उनका अनिश्चित व्यवहार और निर्णय का तरीका सभी को चौंकाता रहा है। अभी भी लोग अनिश्चित है, उनके भविष्य के निर्णयों को लेकर। पर एक सवाल बड़ा है कि दो सौ साल से ज्यादा की लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज तक अमेरिका किसी महिला को अपना राष्ट्रपति नहीं चुन सका और ये सवाल कब तक अमेरिका का पीछा करेगा, यह भविष्य के गर्भ में है।

(लेख में विचार निजी हैं)

परिणाम आ चुका है और ट्रंप राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब देखना ये होगा कि यूक्रेन तथा इस्राइल के मामले में 20 जनवरी शपथ लेने के बाद वो क्या निर्णय लेते है। पाकिस्तान और इमरान खान पर उनका क्या रुख होता है। भारत से वहां जाकर काम करने के इच्छुक लोगो के एच 1 बी वीजा पर उनका क्या रुक होता है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा काजू बाजार

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा काजू आयातक और निर्यातक है। यहां जरूरत का करीब 50 फीसद काजू आयात किया जाता है
- लेकिन दिलचस्प यह भी है कि भारत काजू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक भी है
- उद्योग के जानकार बताते हैं कि करीब 60 फीसद काजू का उपयोग काजूकतली, स्नैक्स, बिस्किट और सब्जियों की करी बनाने में होता है
- ऑल इंडिया काजू असोसिएशन के मुताबिक, काजू की मांग को बादाम से पूरा करने की कोशिश की जाती है।

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

कुछ इस तरह के लेख जल्दी ही देखने को मिलेंगे, खासतौर से भारतीय मीडिया में- हार कर भी जीत गई कमला हैरिस, अमेरिका में कमला की नैतिक जीत, लोकतंत्र पड़ा खतरे में, अमेरिकी नागरिकों में बढ़ती कट्टरता, कमजोर पड़ती अमेरिका की ताकत, दुनिया के लिए घातक दक्षिणपंथी उभार, चीन के आगे झुका अमेरिका वगैरह-वगैरह!!

अखिलेश शर्मा, पत्रकार
@akhileshsharma1

धर्म — **श्रीराम शर्मा आचार्य**

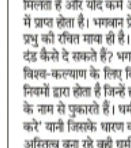

कुछ लोगों की धारणा है कि भगवान ही दंड दिया करते हैं, परंतु वास्तव में भगवान किसी को दंड नहीं देते। मनुष्य स्वयं ही कर्मवश अपने आपको दंड देता है। जब कभी यह कोई बुरा कार्य अपनी इंद्रियों के वशीभूत होकर बिना विचारे किया करता है तब उसे उसका फल मिला करता है। यदि कार्य बुरा होता है तो फल भी दंड रूप में मिलता है और यदि कर्म अच्छा होता है तो फल यश रूप में प्राप्त होता है। भगवान प्रेम स्वरूप है। सारा संसार उन प्रभु की रचित माया ही है। जब भगवान प्रेम स्वरूप हैं तब दंड कैसे दे सकते हैं? भगवान कदापि दंड नहीं देते। विश्व-कल्याण के लिए विश्व का शासन कुछ सनातन नियमों द्वारा होता है जिन्हें हम धर्म का रूप देते हैं तथा धर्म के नाम से पुकारते हैं। धर्म किसे कहो हैं?-'जो धारण करें' यानी जिसके धारण करने से किसी वस्तु का अस्तित्व बना रहे वही धर्म है। अग्नि का धर्म प्रकाश व उष्मता देना है, परंतु यदि वह प्रकाश व उष्मता नहीं दे तो वह तो राख अथवा कोयले का ढेर मात्र ही रह सकता है क्योंकि वह अपने को छोड़ चुकी है। ठीक यही दशा मानव की है। वह भी धर्म रजु द्वारा बंधा रहता है। जब कभी वह अपना धर्म त्यागता है उसे अवश्य ही हानि उठानी पड़ती है और वह दंड विधान वन कर उसे आगाह करती है। मनुष्य मार्ग की मानवता का आधार धर्म ही है। जब जानबूझकर अथवा असावधानी वश सनातन नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तब अवश्य ही दंड का भागी बनना पड़ता है। भगवान को व्यर्थ ही दोषी ठहराना अनुचित है। भगवान कल्याणमय हैं तथा उनके नियम भी कल्याणमय हैं। जब उन नियमों का उचित प्रकार पालन नहीं किया जाता तब ही दंड चेतावनी के रूप में मिला करते हैं, परंतु मूर्खता व अज्ञानवश मनुष्य इतने पर भी नहीं संभलता और एक के बाद दूसरा नियम भी खंडित करता जाता है। मनुष्य अपने आपको नहीं पहचान पाता है वास्तव में जो कुछ वह करता है उसी से कार्यानुसार दंड व यश का भागी बनता है। अब सब कुछ मनुष्य मात्र पर ही रह जाता है। यदि मनुष्य स्वतः को सुधार लेता है तो वह सबको सुधार सकता है परंतु जब वह स्वतः नहीं सुधरेगा तो दूसरों को कैसे सुधार सकता है? नियमों का विधान पालन करने के लिए ही बनाया जाता है।

रीडर्स मेल

बच्चों की खातिर

क्या सोशल मीडिया एवं इंटरनेट का बेतहाशा उपयोग से दुनिये भर के बच्चों पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है? इसका उत्तर है हां। ऐसा ही हो रहा है। पढ़ाई में मन नहीं लगना, अवसाद का शिकार होना, बच्चों में खराब शारीरिक छवि एवं अकेलेपन का शिकार बना सकता है। रात में शयन कक्ष में इसका इस्तेमाल से नींद की कमी के कारण अन्य शारीरिक एवं मानसिक विकार को जन्म दे सकता है। सामाजिक संपर्क में कमी आना, खेलकूद से दूर होना, ऑनलाइन शिकारियों के जाल में फंस कर कई बच्चे यौन शोषण का भी शिकार बन जाते हैं। सोशल मीडिया बच्चों को पक्षपातपूर्ण या गलत जानकारी के संपर्क में ला सकता है। बहुत अधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के वजह से वे आगे चलकर भयदोहन का शिकार हो सकते हैं। शायद इसी के कारण ऑस्ट्रेलिया दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित कानून को लेकर ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानिसि ने घोषणा की कि सरकार 2024 के अंत तक सोशल मीडिया से बच्चों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पेश करेगी।

जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

कुदरत से सामंजस्य बिठाना होगा

7 नवम्बर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दुनिया में ही नहीं, बल्कि हमारे देश में भी कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ी है। यह ऐसी बीमारी है जिसके बारे लोगों को तब पता चलता है जब यह व्यक्ति को मौत के करीब ले आती है। हालांकि आज के समय में हमने इस जानलेवा बीमारी पर काफी हद तक जीत हासिल की है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आयुर्वेदिक पद्धति, योग, खानपान, जीवनशैली, रसोई के मसाले दवाइयों का रूप के कारण कोरोना वैश्विक महामारी हमारे देश के लिए उतनी आफत नहीं बनी, जितनी की दूसरे देशों में। समय-समय पर मानवीय भूल के कारण महामारियों ने अस्तित्व में आकर इंसान को यह समझाने की कोशिश की इंसान का कुदरत की लक्ष्मण रेखा पार करना खुद इंसान की जान पर भी भारी पड़ सकता है और यह भी समझाया कि कुदरत के आगे इंसान अभी भी बौना है, इसलिए हमें भविष्य में कोरोना जैसी जानलेवा महामारियों, बीमारियों से बचना है तो हमें कुदरत को संभालने और इसके दायरे में खानपान और जीवनशैली अपनानी होगी।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भारत के लिए अहम ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित जीत भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अमेरिका-भारत संबंधों, विशेष रूप से व्यापार और रक्षा को कैसे प्रभावित करेगा? ट्रंप के 'अमेरिका फर्स्ट' पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, क्या भारत को उच्च टैरिफ या सैन्य साझाकरण भार की मांग का सामना करना पड़ेगा? इसी तरह उनकी नीति दक्षिण एशिया में स्थिरता को कैसे प्रभावित करेगी, विशेष रूप से चीन के संबंध में; अनिश्चितता का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। क्योंकि भारत संभावित रूप से परिवर्तनकारी वैश्विक व्यवस्था में अपने रणनीतिक लक्ष्यों पर बातचीत कर रहा है।

अंशु भारती, बेगूसराय
letter.editorsahara@gmail.com

भारत — **सुनिधि मिश्रा**

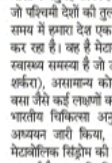

बढ़ता स्वास्थ्य संकट

हाल ही में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2045 तक मधुमेह के रोगियों की संख्या 134 मिलियन होने का अनुमान है। चिंता का विषय यह है कि भारत में मधुमेह का निदान औसतन 10 वर्ष पहले हो रहा है, जो पश्चिमी देशों की तुलना में काफी कम उम्र है। वर्तमान समय में हमारा देश एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहा है। यह है मेटाबोलिक सिंड्रोम। यह एक जटिल स्वास्थ्य समस्या है जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह (उच्च रक्त शर्करा), असामान्य कोलेस्ट्रॉल स्तर और अधिक शरीर वसा जैसे कई लक्षणों का संयोजन है। अक्टूबर 2023 में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक व्यापक अध्ययन जारी किया, जिसमें पाया गया कि भारत में मेटाबोलिक सिंड्रोम की दर पिछले पांच वर्षों में 15 फीसद बढ़ गई है। यह वृद्धि विशेष रूप से 30-45 वर्ष की आयु वर्ग में देखी गई है, जो चिंता का विषय है।

भारत में मेटाबोलिक सिंड्रोम की स्थिति चिंताजनक है। विशेष रूप से मधुमेह, हृदय रोग और मोटापे के संदर्भ में। इन तीनों स्थितियों का मेटाबोलिक सिंड्रोम से गहरा संबंध है और ये एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। भारत को 'मधुमेह की राजधानी' के रूप में जाना जाता है, और यह उपाधि बिना किसी कारण के नहीं दी गई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, भारत में लगभग 77 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। मेटाबोलिक सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में टाइप 2 मधुमेह विकसित होने का जोखिम 5 गुना अधिक होता है। भारतीय आबादी में इंसुलिन प्रतिरोध की उच्च दर पाई गई है, जो मेटाबोलिक सिंड्रोम का एक प्रमुख लक्षण है। मेटाबोलिक सिंड्रोम का दूसरा प्रमुख लक्षण हृदय रोग है जो कि भारत में मृत्यु का प्रमुख कारण है। भारत में हर साल लगभग 4.77 मिलियन लोगों की मृत्यु हृदय रोग के कारण होती है। एक अध्ययन के अनुसार, भारतीयों में हृदय रोग का खतरा पश्चिमी आबादी की तुलना में 3-4 गुना अधिक है। मेटाबोलिक सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में हृदय रोग का जोखिम 2 से 3 गुना अधिक होता है। भारत में हृदय रोग के मामले युवा आयु वर्ग (30-40 वर्ष) में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो मेटाबोलिक सिंड्रोम के बढ़ते प्रसार से जुड़ा हो सकता है।

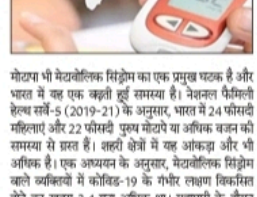

मोटापा भी मेटाबोलिक सिंड्रोम का एक प्रमुख घटक है और भारत में यह एक बढ़ती हुई समस्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (2019-21) के अनुसार, भारत में 24 फीसदी महिलाएं और 22 फीसदी पुरुष मोटापे या अधिक वजन की समस्या से ग्रस्त हैं। शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा और भी अधिक है। एक अध्ययन के अनुसार, मेटाबोलिक सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के गंभीर लक्षण विकसित होने का खतरा 3.4 गुना अधिक था। महामारी के दौरान लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के कारण लोगों की शारीरिक गतिविधियां कम हुईं और खान-पान की आदतें बिगड़ीं, जिससे मेटाबोलिक सिंड्रोम के जोखिम को और बढ़ा दिया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में महामारी के दौरान मोटापे के मामलों में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो मेटाबोलिक सिंड्रोम का एक प्रमुख कारक है। महामारी के दौरान से ही वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड कार्य मॉडल के चलते लोगों की दिनचर्या में बड़े बदलाव आए हैं। एक तात्र सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 68 फीसदी कर्मचारियों ने माना कि वर्क फ्रॉम होम के दौरान उनकी शारीरिक गतिविधियां कम हुई हैं और 42 फीसदी ने अस्वस्थ खाने की आदतों में वृद्धि की सूचना दी। ये दोनों कारक मेटाबोलिक सिंड्रोम के जोखिम को बढ़ाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में मेटाबोलिक सिंड्रोम से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर हर साल लगभग 30 बिलियन डॉलर खर्च होते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर, यह व्यय देश की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा बोझ है।

इस बढ़ती समस्या से निपटने के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले, जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। सरकार और स्वास्थ्य संगठनों को मेटाबोलिक सिंड्रोम के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाने चाहिए। लोगों को इसके लक्षणों, कारणों और परिणामों के बारे में शिक्षित करना महत्वपूर्ण है। स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करना दूसरा महत्वपूर्ण कदम है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार को बढ़ावा देना चाहिए। एक नए सर्वेक्षण के अनुसार, नियमित व्यायाम करने वाले लोगों में मेटाबोलिक सिंड्रोम का जोखिम 30 फीसद तक कम हो जाता है। आहार में सुधार भी अहम है। पारंपरिक भारतीय आहार, जो फलों, सब्जियों और साबुत अनाज से समृद्ध है, को बढ़ावा देना चाहिए। प्रोसेस्ड और जंक फूड पर कर बढ़ाने जैसे नीतिगत हस्तक्षेप भी मददगार हो सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि स्वस्थ समाज ही एक समृद्ध राष्ट्र का आधार है। मेटाबोलिक सिंड्रोम से लड़ना न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे देश के समग्र विकास के लिए भी आवश्यक है।

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, स्वर्ण धाम, नवरंग सराय, 21 के.बी. पार्क, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - राकेश सिंह* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 84
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी सलाहों के लिए उत्तरदायी

सम्पादकीय

ट्रंप का दूसरा कार्यकाल : विश्व अर्थव्यवस्था और भूराजनीति के लिए नई अनिश्चितताएं

डॉनल्ड ट्रंप चार साल के अंतराल के बाद दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत गए हैं। इस जीत ने सर्वेक्षणों को धता बता दिया है और डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव के पहले की आशंकाओं को रेखांकित किया है। यह भुकावला किसी भी लिहाज से करीबी नहीं था। ट्रंप न केवल रिपब्लिकन प्रभुत्व वाले राज्यों में जीते बल्कि उन्होंने स्विंग स्टेट्स (वे राज्य जिनका रुझान स्पष्ट नहीं) में भी जीत हासिल की। 2016 के उलट ट्रंप ने पॉपुलर वोट में भी जीत हासिल की। 2004 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दोबारा चुनाव जीतने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रिपब्लिकन ने पॉपुलर वोट में जीत हासिल की हो। कमला हैरिस ने चुनाव के 107 दिन पहले अपना प्रचार अभियान शुरू किया था जो विश्व युद्ध के बाद के दौर में किसी प्रतिभागी का सबसे छोटा चुनाव अभियान था लेकिन उन्होंने जो गति हासिल की थी, उसे देखते हुए भी ट्रंप की जीत उल्लेखनीय है। हैरिस ने ट्रंप से अधिक धन जुटाया और खर्च किया तथा पूर्व राष्ट्रपतियों और ट्रंप के पहले प्रशासन के दिग्गजों से लेकर नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री तथा टेलर स्विफ्ट एवं ओपरा विनफ्रे जैसे सांस्कृतिक रूप से प्रभावशाली लोग उनका समर्थन कर रहे थे। उनकी कमजोरी इस बात में निहित है कि उन्होंने खुद को बाइडनॉमिक्स से जोड़ा। सर्वेक्षणों ने लगातार बताया कि बाइडन की आर्थिक नीतियां न केवल अलोकप्रिय रहीं बल्कि उनका एजेंडा भी अच्छी तरह परिभाषित नहीं था और गर्भपात के अधिकारों तथा नए परिवारों के लिए कर राहत के सिवा उसमें कुछ खास नहीं था। ट्रंप की अलोकप्रियता को लेकर उनका आत्मविश्वास भारी पड़ गया और वह इतनी आश्वस्त हो गई कि उनके प्रचार अभियान की आर्थिक ऊर्जा बाद में नजर नहीं आई। इसके विपरीत उनके प्रतिद्वंद्वी ने अपने चिरपरिचित एजेंडे को नहीं छोड़ा: सख्त आव्रजन नियंत्रण, अमीरों तथा बड़े कारोबारी घरानों को कर राहत, दूसरे देशों के साथ विद्वेष, लैंगिक भेदभाव और संरक्षणवाद। हत्या के प्रयास के बाद उन्होंने जो अनुकरणीय साहस दिखाया उससे भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। सीनेट पर कब्जे के बाद कांग्रेस में रिपब्लिकन की संभावित पूर्ण विजय के बाद उन्हें पहले दो वर्षों में ही अपनी नीतियों को लागू करने का अवसर मिल जाएगा। अमेरिकी मतदाताओं को अपने चुनाव का परिणाम मिलेगा लेकिन ट्रंप के पहले कार्यकाल के अनुभव शेष विश्व को खुश होने की वजह नहीं देते। आर्थिक मोर्चे पर बाइडन ट्रंप की टैरिफ वाली नीतियों के आसपास ही दिखे। परंतु ट्रंप अपने चुनावी वादे को पूरा कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वह आक्रामक व्यापार नीतियों को बढ़ावा देंगे तथा चीन की वस्तुओं पर 60 फीसदी तथा अन्य देशों पर 10 फीसदी शुल्क लगाएंगे। करों में कटौती का भी वादा किया गया है और इससे बजट घाटा बढ़ सकता है। इससे मुद्रास्फीति का दबाव बनेगा और मांग तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर होगा। विश्व अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रहेगी। भारत और अमेरिका के रिश्ते बीते सालों में मजबूत हुए हैं।

विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव अंधेरों की आहट

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की धरती पर अनेक सकारात्मक स्थितियां उद्घाटित हुई है, विशेषतः लोकतंत्र को जीवंतता मिली है, वहां की अवाम ने चुनावों में बढ़-चढ़कर भाग लिया, शांति एवं विकास से इस प्रांत में एक नई इबारत लिखी जाने लगी है। जम्मू-कश्मीर हमारे देश का वो गहना है जिसे जब तक सम्पूर्ण भारत के साथ जोड़ा नहीं जाता, वहां शांति, आतंकमुक्ति एवं विकास की गंगा प्रवहमान नहीं होती, अधूरापन-सा नजर आता रहा है। इसलिए इसे शेष भारत के साथ हर दृष्टि से जोड़ा जाना महत्वपूर्ण है और यह कार्य मोदी एवं उनकी सरकार ने करके एक नये सूरज को उदित किया है, अब उस सूरज को अस्त नहीं होने दिया जायेगा। बड़ी जद्दोजहद से वहां एक नया दौर शुरू हुआ है, अब इस सुनहरे एवं उजले दौर को स्वार्थी एवं सत्ता की अलगाववादी एवं विघटनकारी राजनीति की भेंट नहीं चढ़ने देना चाहिए।

ललित गर्ग

नेशनल कॉन्फ्रेंस एवं उमर अब्दुला सरकार ने सदन में अपने बहुमत का लाभ उठाते हुए बुधवार को बिना अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली शब्द का इस्तेमाल कर, विशेष दर्जे की बहाली का प्रस्ताव तीखी झड़पों, हाथापाई, लात-घूंसे एवं शोरशराबे के बीच ध्वनिमत से पारित करा, साबित कर दिया है, वह पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इस होड़ में पीछे रहने के मूड में नहीं है। ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में अलगाववाद और तुष्टिकरण की राजनीति फिर से परवान चढ़ने लगी है, आम कश्मीरी अवाम को गुमराह कर उसे बर्बादी की तरफ धकेलने की कुचेष्टाएं प्रारंभ हो गयी है। इस पारित प्रस्ताव में केंद्र सरकार से कहा गया है कि वह विशेष दर्जा वापस देने के लिए राज्य के प्रतिनिधियों से बातचीत करे। बुधवार को नवगठित राज्य विधानसभा में जब यह प्रस्ताव उप-मुख्यमंत्री सुरिंदर सिंह चौधरी ने पेश किया, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि चौधरी का चयन ही इसलिए किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश न कर सके। लेकिन भाजपा ने एक विधान एक निशान और राष्ट्रवाद के प्रति अपनी संकल्पबद्धता को दोहराते हुए इस प्रस्ताव का विरोध कर बताया कि वह प्रत्यक्ष तो क्या परोक्ष तौर पर भी किसी को पद्दी की सुइयां पीछे मोड़ने की अनुमति नहीं देगी। जब तक केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार है, कोई भी अनुच्छेद 370 और 35ए को वापस नहीं ला सकता। अनुच्छेद 370 एक मरा हुआ सांप है, जिसे वह एक गले से दूसरे गले में डाल, जहर, आतंक एवं हिंसा फैलाने के षडयंत्र को सफल नहीं होने देगी। कश्मीर के नेताओं को समझना ही होगा कि पूरे भारत में अनुच्छेद 370 को लेकर जैसा जनमानस है, उसे देखते हुए अनुच्छेद 370 की वापसी असंभव है।

भारत की महानता उसकी विविधता में है। साम्प्रदायिकता एवं दलगत राजनीति का खेल, उसकी विविधता में एकता की पीठ में छुरा भोंकता रहा है, घाटी उसकी प्रतीक बनकर लहूलुहान रही है। जब हम नये भारत-सशक्त भारत बनने की ओर अग्रसर हैं, विश्व के बहुत बड़े आर्थिक बाजार बनने जा रहे हैं, विश्व की एक शक्ति बनने की भूमिका तैयार करने जा रहे हैं, तब हमारे मस्तक के ताज जम्मू-कश्मीर को जाति, धर्म व स्वार्थी राजनीति से बाहर रखना सबसे बड़ी जरूरत है। इसी दिशा में घाटी को अग्रसर करने में मोदी सरकार के प्रयत्न सराहनीय एवं स्वागतयोग्य रहे हैं। घाटी की कमजोर राजनीति एवं साम्प्रदायिक आग्रहों का फायदा पडोसी उठा रहे हैं, जिनके खुद के पांव जमीन पर नहीं वे आंख दिखाते रहे हैं। अब ऐसा न होना, केन्द्र की कठोरता एवं सशक्तीकरण का द्योतक है। कश्मीर के तथाकथित राजनीतिक कर्णधारों! अलगाववाद और तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ो। अगर तेवर ही दिखाने हैं तो देश के दुश्मनों को दिखाओ, पडोसी देश के मनसूबों को निस्तेज करों। अतीत की राजनीतिक भूलों को सुधारना और भविष्य के निर्माण में सावधानी से आगे कदमों को बढ़ाना, जम्मू-कश्मीर की चुनी हुई सरकार का संकल्प होना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा पाने के मसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां खड़ी है, पीडीपी उससे दो कदम आगे रहना चाहती है। ऐसे करके नेशनल कान्फ्रेंस और पीडीपी सरीखे दल यहां अलगाववाद और एक वर्ग विशेष की तुष्टिकरण की राजनीति को जारी रखना चाहते हैं, वह यहां फिर से अलगाववाद को पैदा करना चाहते हैं, आम कश्मीरी अवाम को गुमराह कर उसे बर्बादी की तरफ धकेलना चाहते हैं, तभी अनुच्छेद 370 की बहाली का प्रस्ताव लाये हैं। जबकि अनुच्छेद 370 के हटने से घाटी में एक उजाला अवतरित हुआ है, अब फिर से घाटी को अंधेरों से नहीं घिरने देना चाहिए। भले ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर का चुनाव ही इसी घोषणा के साथ लड़ा और जीता है कि वह भारतीय संविधान में राज्य को उसका विशेष दर्जा वापस दिलाएगी। इसीलिये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सत्ता में आते ही पहला काम यही किया और विधानसभा ने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। नेशनल कान्फ्रेंस को लगता है कि विशेष दर्जे के मुद्दे से कुछ लोगों के तार भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, इसलिए ज्यादा अतिवादी रूख अपनाकर इसका कुछ राजनीतिक फायदा उठाया जा सकता है। दोनों ही प्रमुख दल इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की होड़ लगाते हुए दिख रहे हैं। तभी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी थी कि यह पीडीपी का केवल प्रचार स्टंट है और उसके विधायक सिर्फ कैमरे के आगे आने के लिए यह सब कर रहे हैं। मगर उमर अब्दुल्ला जो बात पीडीपी के लिए कह रहे हैं, वही शायद उनके लिए भी कही जा सकती है, वरना वह भी यह जानते हैं कि 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के जिस अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था, उसकी वापसी अब इतनी आसान नहीं है। वैसे भी, इतना तो उन्हें पता ही होगा कि सिर्फ विधानसभा में प्रस्ताव पारित हो जाने भर से अनुच्छेद 370 वापस आने वाला नहीं है। फिर इस समय केंद्र में भाजपा सरकार है, जो किसी भी तरह से इस पर विचार करने के मूड में नहीं है। उसकी नजर में यह एक कागज का टुकड़ा है, जो बिना विचार के रद्दी की टोकड़ी में ही जाने वाला है। अनुच्छेद 370 को लेकर कश्मीर की जनता और राजनेताओं, दोनों को समझना ही होगा कि 70 साल तक विशेष दर्जा होने के बावजूद इससे राज्य का कोई बहुत भला नहीं हुआ। देश की मूल धारा से कटकर यह प्रांत अंधेरों से घिरा रहा है। हिंसा एवं आतंकवाद की त्रासदी को झेलते हुए विकास एवं शांति की बाट जोहता रहा है। अब विशेष दर्जा हटाने का राज्य को बहुत लाभ मिला है, वहां विकास एवं जनकल्याण के काम तेजी से हो रहे हैं, न केवल विकास योजनाएं आकार ले रही है, बल्कि वहां शांति एवं सौहार्द का वातावरण बना है, आतंकवादी घटनाओं पर भी नियंत्रण किया जा सका है। मोदी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर के विकास को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया है। देश के साथ दुनिया को यह संदेश दिया गया कि कश्मीर में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं, कश्मीर भारत का ताज है और हमेशा रहेगा। घाटी के राजनीतिक दलों को वहां के अवाम के हित में सोचना चाहिए। क्योंकि अनुच्छेद 370 के खत्म होने से राज्य का कोई नुकसान हुआ, ऐसा नहीं दिखता। इसलिए जम्मू-कश्मीर को अब ऐसी राजनीति की जरूरत है, जो विशेष दर्जे से इतर तरक्की का नया खाका खींचे। अनुच्छेद 370 का खत्म होना इसलिये ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वहां के लोगों ने साम्प्रदायिकता, राष्ट्रीय-विखण्डन, आतंकवाद तथा घोटालों के जंगल में एक लम्बा सफर तय करने के बाद अमन-शांति, सौहार्द एवं विकास को साकार होते हुए देखा है।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विधि लगाते जो पूरा करेंगे। कब आप पर सकता पाते है कि आपके जीवन के ऐसे दौर्रा बंद है, जब आपके जिंदगी कुछ होगे और दुखी रहता, आपको मित्र करी से सहायक लगता प्रतीत। एक ने दिनों हमारे साथ में और अंदित मुहों को सुनकर्ता तथा स्वास्थ्यता ऊर्जा को समझते होंगे, बंधित परेशानियों को हो, जहां एक सहायकता हमें लेकर और बाधाओं से मार्ग प्रदान करेगा

मेष
पुराना रोग परेशानी का कारण बन सकता है। जल्दबाजी न करें। आवश्यक वस्तुएं गुम हो सकती हैं। चिंता तथा तनाव रहेंगे। प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। भेंट व उपहार देना पड़ सकता है। प्रयास सफल रहेंगे। कार्य की बाधा दूर होगी।

वृष
प्रतिद्वंद्विता कम होगी। वाणी में हल्के शब्दों के प्रयोग से बचें। बात बिगड़ सकती है। शत्रुभय रहेगा। कोर्ट व कचहरी के काम मनोनुकूल रहेंगे। जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा।

मिथुन
खाद्य मनोरंजक रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग सफलता हासिल करेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति मार्गदर्शन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इंझेशों में न रखना। शत्रुओं का पराभव होगा। व्यवसाय ठीक चलेगा।

कर्क
विवाद से क्लेश होगा। वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। ऐश्वर्य के साधनों पर सोच-समझकर खर्च करें। कोई ऐसा कार्य न करें जिससे कि बाद में पछतावा पड़े। दूसरे अधिक अपेक्षा करेंगे। घर-बाहर प्रसन्नता रहेगी।

सिंह
दुहजन हानि पहुंचा सकते हैं। झंझटों में न पड़ें। व्यापार-व्यवसाय में वृद्धि होगी। नौकरी में मातहतों का सहयोग मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। शत्रुभय रहेगा। जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी।

कन्या
निवेश शुभ रहेगा। व्यापार में वृद्धि तथा सम्मान में वृद्धि होगी। किसी भी तरह के विवाद में पड़ने से बचें। जल्दबाजी से हानि होगी। राजभय रहेगा। दूर से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। घर में मेहमानों का आगमन होगा। व्यय होगा। लेन-देन में लापरवाही न करें।

तुला
स्त्री वर्ग से सहायता प्राप्त होगी। नौकरी व निवेश में इच्छा पूरी होने की संभावना है। भूमि व भवन संबंधी खरीद-फरोख्त की योजना बनेगी। रोजगार प्राप्ति के प्रयास सफल रहेंगे। आर्थिक उन्नति होगी। संचित कोष में वृद्धि होगी। देनदारी कम होगी।

वृश्चिक
आय में निश्चितता रहेगी। दुःखद समाचार मिल सकता है। व्यर्थ भागदौड़ रहेगी। काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। बेवजह किसी व्यक्ति से कहासुनी हो सकती है। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। दूसरों के बहकावे में न आएं।

धनु
व्यापार-व्यवसाय लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट आदि से बड़ा फायदा हो सकता है। परिवार की चिंता बनी रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है। लेन-देन में जल्दबाजी न करें। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का अवसर प्राप्त होगा।

मकर
मान-सम्मान मिलेगा। रुके कार्यों में गति आएगी। निवेश शुभ रहेगा। नौकरी में चैन बना रहेगा। धर्म-कर्म में रुचि रहेगी। कोर्ट व कचहरी के कार्य मनोनुकूल रहेंगे। लाभ के अवसर हाथ आएंगे। चोट व रोग से बचें। सेहत का ध्यान रखें।

कुंभ
सही काम का भी विरोध हो सकता है। जोखिम उठाने का साहस कर पाएंगे। निवेश शुभ रहेगा। सट्टे व लॉटरी के चक्कर में न पड़ें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर करें। किसी अनहोनी की आशंका रहेगी। शारीरिक कष्ट संभव है।

मीन
सही काम का भी विरोध होगा। कोई पुरानी व्याधि परेशानी का कारण बनेगी। कोई बड़ी समस्या बनी रहेगी। चिंता तथा तनाव रहेंगे। नई योजना बनेगी। कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सामाजिक कार्य करने के प्रति रुझान रहेगा। फालतू बातों पर ध्यान न दें।

शख्सियत

बढ़ता राजस्थान

नमस्कार मित्रों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आईएएस पुखराज सैन जी। 4 मई सन 1967 अजमेर में जन्में पुखराज सैन बहुत ही शानदार अधिकारी हैं। जमीन से जुड़ाव और लोगों की भावनाओं को समझने का अद्भुत जज्बा है इनमें। अपनी बी कॉम की पढ़ाई पूर्ण कर सिविल सेवा में आए और विभिन्न स्थानों पर रह कर जनसेवा की। फिलहाल जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना कुचामन पद को सुशोभित कर रहे हैं। अपनी सरकारी सेवाओं के माध्यम से अनेकों स्थानों पर बड़े पदों पर अपनी सेवाए दी हैं। शायद इसलिए अनुभव बहुत ही शानदार है सैन साब का। ये प्रबन्ध निदेशक जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, राजस्थान, जयपुर। आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर, आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण) खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय राजस्थान, जयपुर। कार्यकारी निदेशक राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज और इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड रूडसीको जयपुर, अतिरिक्त आयुक्त (वैट एण्ड आईटी) वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान, जयपुर, सलाहकार इन्फ्र रीको जयपुर, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर प्रथम, उप निदेशक क्षेत्रीय स्थानीय निकाय विभाग जयपुर, सचिव प्रशासन राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर, अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जयपुर दक्षिण,अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट शहरद्ध जयपुर दक्षिण, कार्यकारी निदेशक राजस्थान विद्युत निगम, जयपुर। उपायुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मंच एवं पदेन उप सचिव सरकार को, जयपुर.द्वितीय, अतिरिक्त आयुक्त जेडीए जयपुर, राजस्व अपीलीय प्राधिकारी, जयपुर, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा, डीवाई महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर। प्रबंधक प्रशासन कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर, अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, टोंक। अतिरिक्त कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, पाली। उपखण्ड अधिकारी, सोजत पाली, उपखण्ड अधिकारी, बूंदी। उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ भीलवाड़ा, उपखण्ड अधिकारी, खत्री झुंझुनू। एसीईएम सुजानगढ़ चूरू। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। सहायक कलेक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट यूटी राजसमंद, एसीईएमए यूटी अलवर जैसे अनेक बड़े पदों पर रहे। यही नहीं सरकार ने इनकी कार्यक्षमता व कुशलता को देख निदेशक, चिकित्सा आईईसी विभाग राजस्थान जयपुर व कार्यकारी निदेशक, राजस्थान वित्तीय निगम जयपुर का अतिरिक्त भार सौंपा जिसे बखूबी निभाया। दैनिक बढ़ता राजस्थान की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हैं जय हिन्द।

पुखराज सेन
(आई.ए.एस)

रूपक शर्मा

आज का इतिहास

8 नवंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- सिख धर्मगुरु हर राय का निधन 1661 में हुआ।
- भौतिक शास्त्री विल्हेम कोनार्ड रॉन्टजन ने 1895 में एक्स-रे की खोज।
- वाल्दमीर लेनिन, लियो ट्रोटस्की और जोसेफ स्टालिन को 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद पीपुल्स कमीसार अधिकृत किया।
- म्यूनिख में एडोल्फ हिटलर ने 1923 में जर्मन सरकार को अपदस्थ करने की नाजियों की एक कोशिश का नेतृत्व किया। सेनाओं ने नाजियों के इस प्रयास के असफल कर दिया।
- मंदी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलीन रूजवेल्ट ने 1933 में 40 लाख लोगों का रोजगार देने के लिए सिविल वर्क्स एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया।
- हांगकांग में 1945 में हुए नौका दुर्घटना में 1550 लोगों की मौत हुई।
- संयुक्त राष्ट्र (संरा) ने 1956 में तत्कालीन सोवियत संघ से यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की।
- ब्रिटेन ने 1957 में क्रिसमस द्वीप समूह के समीप परमाणु परीक्षण किया।
- जॉन एफ केनेडी 1960 में संघर्षपूर्ण मुकाबले में रिचर्ड निक्सन को बहुत कम अंतर से हरा कर अमेरिका के 35 वें राष्ट्रपति बने।
- अमेरिका ने 1967 में नेवादा में परमाणु परीक्षण किया।
- चीन में 1988 में आये विनाशकारी भूकंप से 900 लोगों की मौत हुई।
- आयरलैंड में 1990 में पहली महिला राष्ट्रपति बनी।
- जर्मनी की राजधानी बर्लिन में 1992 में नस्लवाद के खिलाफ हुए प्रदर्शन में तीन लाख लोगों ने हिस्सा लिया।
- बांग्लादेश में 1998 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री शेखमुजीबुर्रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्युदंड।
- राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 1999 में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया।
- बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने 2000 में न्यूयार्क सीट पर जीत दर्ज कर इतिहास रचा।
- अफगानिस्तान पर 2001 में पुनः जुबर्दस्त बमबारी।
- भारत ने 2005 में फिलिस्तीनि संगठनों की आतंकवादी कार्रवाई और इस्रायल की दमन की आलोचना की।
- भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चन्द्रयान -1 2008 में चन्द्रमा की कक्षा में पहुँचा।
- भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोटों का अवैध घोषित किया।

विशेष आलेख

डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद क्या अब बांग्लादेश में होगी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की वापसी?

अशोक भाटिया

डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के तुरंत बाद, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने उन्हें बधाई संदेश भेजा। इस संदेश में हसीना ने ट्रंप की नेतृत्व क्षमता और अमेरिकी जनता द्वारा उन पर दिखाए गए विशाल विश्वास की सराहना की। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रंप के नए कार्यकाल में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।शेख हसीना का यह कदम बांग्लादेश की राजनीतिक परिदृश्य में खेला की वापसी का संकेत माना जा रहा है। हसीना इस समय दिल्ली में हैं, माना जा रहा है कि वो ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद अमेरिका का दौरा कर सकती हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने की संभावना है।

शेख हसीना का ट्रंप को भेजा गया यह संदेश को साधारण या औपचारिक बधाई नहीं है। यह बांग्लादेश में उनकी सियासी वापसी की दिशा में एक रणनीतिक पहल भी माना जा रहा है। वहीं, बांग्लादेश सरकार के मौजूदा प्रमुख मोहम्मद यूनुस की क्लिंटन परिवार और डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं से नजदीकी रिश्तों के चलते हसीना को ट्रंप प्रशासन में और भी समर्थन मिल सकता है। यूनुस के अमेरिका में मजबूत संपर्क और बाइडेन प्रशासन में उनकी घनिष्ठता के बावजूद, हसीना का यह कदम कहीं न कहीं उन पर एक तरह का दबाव बना सकता है। अमेरिका के कूटनीतिक दबाव के कारण भारत के अलावा फिलहाल कोई अन्य देश शेख हसीना को मदद और वीजा देने में संकोच कर रहा है। ऐसे में, शेख हसीना के इस बधाई संदेश से साफ है कि वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में सक्रिय हो गई हैं।

मौजूदा समय में बांग्लादेश के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस को ट्रंप जरा भी पसंद नहीं करते। दरअसल यूनुस पर आरोप हैं कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने ट्रंप के खिलाफ फंडिंग की थी, तब से ट्रंप उनसे नाराज हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिवाली के मौके पर एक पोस्ट की थी। 2016 में ट्रंप जब पहली बार चुनाव जीते थे तब यूनुस ने कहा था कि उनकी जीत सोलर एक्लिप्स की तरह है। उजाला एक दिन जरूर आएगा। माना जा रहा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा करीबी हैं। बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, जो बाइडेन से उनकी ज्यादा बनती है। यूनुस कई बार ट्रंप की आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप ने हाल में बांग्लादेश के मौजूदा हालात पर कहा था कि वहां पर जो हो रहा है वो सही नहीं है। ट्रंप बांग्लादेशी हिंदू के लिए भी आवाज उठा चुके हैं। माना जा रहा है कि वो अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर दबाव डालेंगे। वो बोलेंगे कि शेख हसीना की पार्टी पर जो भी एक्शन हो रहा है उसे बंद किया जाए। देश में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और लोगों को ही फैसला लेने दिया जाए कि वो किसकी सरकार चाहते हैं।उसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और

उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। उन्होंने अमेरिका ही नहीं दुनियाभर के हिंदुओं की रक्षा का वादा किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों को लेकर मोहम्मद यूनुस को माफ करने के मूड में नही हैं। अवामी लीग के आधिकारिक फेसबुक पेज पर जारी बयान में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप के साथ उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान हुई मुलाकात को याद किया। साथ ही बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की द्विपक्षीय रिश्तों को आगे बढ़ाने की तरफ काम करने की इच्छा जताई। गौरतलब है कि बांग्लादेश को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की सोच उनके पहले राष्ट्रपति कार्यकाल में स्पष्ट हो गई थी। डोनाल्ड ट्रंप का बांग्लादेश के प्रति एक झुकाव है। वह बांग्लादेश का एक लोकतंत्र समर्थक देश के तौर पर देखते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी करके बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की थी और इस मामले को अमेरिकी हिंदुओं की दिल के बेहद करीब बताया था। उन्होंने अमेरिका समेत पूरे विश्व में हिंदू समुदाय की अधिकारों की सुरक्षा करने की बात कही थी। इसी कारण यह आशा जागी है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत का सबसे ज्यादा असर जिन देशों पर होने वाला है, उनमें बांग्लादेश भी है। यह साबित हो चुका है कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक खास रणनीति के तहत शेख हसीना सरकार का तख्तापलट करवाया। उन्हें अपना ही देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे भारत को झटका लगा। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि ट्रंप की जीत से पूरा खेल बदलने वाला है। एक बार फिर बांग्लादेश में भारत का दबदबा होगा। यह जीत शेख हसीना के लिए भी खुशखबरी लेकर आई है। एक और बात बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चला रहे मुहम्मद यूनुस डोनाल्ड ट्रंप के कटु आलोचक रहे हैं। कई बार उनके खिलाफ बयानबाजी भी की है। अब उनके भविष्य पर भी संकट खड़ा होगा। ढाका ट्रिब्यून में कूटनीतिक मामलों के जानकार शफकत रब्बी ने इस पर एक लेख लिखा है। उन्होंने बताया कि ट्रंप की जीत का बांग्लादेश पर क्या असर होने वाला है। भारत से रिश्ते कैसे बदल जाएंगे। उन्होंने लिखा है, ट्रंप की विदेश नीति अमेरिकी फर्स्ट रहने वाली है। लेकिन इसके बाद वे बाइडन युग के सभी विवादित मसलों को सुलझाएंगे। यूक्रेन संकट हो या अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर क्राइसिस या फिर मिडिल ईस्ट की स्थति बांग्लादेश के लिए उनका आना बेहद अहम है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इण्डस्ट्रियल सेड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतिक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-नन्दुजा पठान*। प्रधान संपादक-राव बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-पेहाल सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी सेल रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

चिंतन

ट्रंप काल में भू-राजनीतिक परिदृश्य में दिखेगा बदलाव

अमेरिका में व्यवसायी से राजनेता बने डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत को दुनिया अपने-अपने नजरिये से देख रही है। एक सदी में ट्रंप अमेरिका के पहले ऐसा नेता होंगे, जिन्होंने एक कार्यकाल के बाद हारने के बाद दुबारा से राष्ट्रपति कैंडिडेचर भी हासिल की और जीत कर इतिहास भी रचा। रिपब्लिकन पार्टी के इतिहास में यह विरल परिघटना है। डेमोक्रेट राष्ट्रपति जो बाइडन के कमजोर शासन, अमेरिकी अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति, बाइडन सरकार की उदार नीतियों की वजह से वैश्विक संघर्ष का अमेरिकी खजाने पर बढ़ता बोझ आदि अनेक कारक हैं, जिसके चलते डेमोक्रेट प्रत्याशी भावोति मूल की कमला हैरिस इतिहास नहीं रच सकीं। ट्रंप जब दूसरी बार 47वें राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका की कमान संभालेंगे, तो निश्चित ही अमेरिका के साथ-साथ दुनिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य भी बदलेगा। जनवरी 2025 में व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के अलावा अमेरिका के विरोधियों के लिए भी विशेष मायने हैं। अब वे पहले से अधिक अनुभवी हैं और वैश्विक स्तर पर कई वादे भी कर रखे हैं। अमेरिका फर्स्ट उनकी नीति के केंद्र में होगी। अर्थव्यवस्था सुधारना चुनौती होगा। उन्होंने रूस व यूक्रेन जंग खत्म कराने का वादा किया है, वे रूस व यूक्रेन जंग खत्म कराने की कोशिश करेंगे, ताकि अमेरिका पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। ट्रंप कीव और मॉस्को को युद्ध विराम के लिए मजबूर करने का प्रयास करेंगे। यह भी संभावना है कि ट्रंप भविष्य में यूक्रेन को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नेटो) का सदस्य बनने से रोकने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मांगों को स्वीकार कर लेंगे। इसी तरह वे इजराइल के हमास व हिज्बुल्ला से जारी जंग में भी इजराइल की मदद की समीक्षा कर सकते हैं। पश्चिम एशिया में ट्रंप पहले भी इजराइल और सऊदी अरब के कट्टर समर्थक रहे हैं। उनके, ईरान के खिलाफ और भी सख्त रुख अपनाने की संभावना है, जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदा प्राथमिकताओं के साथ मेल खाता है। ट्रंप का राष्ट्रपति चुना जाना नेतन्याहू को कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और यह बदले में पुतिन के प्रति ट्रंप की स्थिति को भी मजबूत करेगा, जो यूक्रेन में अपने युद्ध के लिए ईरानी समर्थन पर निर्भर हो गए हैं। ट्रंपकाल में चीन के साथ अमेरिका का संबंध बदलेगा। हालांकि, बाइडन प्रशासन ने ट्रंप द्वारा अपने पहले कार्यकाल में अपनाई गई कई नीतियों को जारी रखा है, तो अपने नए कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन चीन के प्रति पहले कार्यकाल से और कठोर रुख अपना सकता है। अमेरिकी गलती से ही रूस व चीन की इतनी नजदीकी बढ़ी है, ट्रंप इसे अलग तरीके से डील कर सकते हैं। ट्रंप के चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ व्यावहारिक, लेन-देन संबंधी सौदों के लिए खुले रहेंगे। क्लाइमेट करार पर ट्रंप पुराने रुख पर लौट सकते हैं, अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को अमेरिकी मदद में कटौती कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रति तेवर तीखे रह सकते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की मदद हो सकती है। भारत के साथ अमेरिकी संबंध और प्रगाढ़ होंगे व वैश्विक स्तर पर भारत की सक्रियता और बढ़ सकती है। भारत व अमेरिका ग्लोबल ऑर्डर में फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि भारत सरकार इस स्थिति का कितना सामारिक व व्यापारिक फायदा उठा पाती है। विश्व के छोटे देशों को अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के मामले में ट्रंप पहले कार्यकाल में उदासीन रहे, नए कार्यकाल में उनके रुख का इंतजार रहेगा।

आजीवन सेवा व सादगी की प्रतिमूर्ति रहे श्रीगोपाल व्यास जी

श्रद्धांजलि
डॉ. रमन सिंह

श्री गोपाल व्यास जी, एक ऐसा नाम है जिन्हें केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि सामाजिक और सेवा क्षेत्र से पूरा देश का हर व्यक्ति परिचित है। 15 फरवरी 1932 को श्री पूनमचंद व्यास और श्रीमती जेठाबाई व्यास के घर पुत्र रत्न के रूप मेंश्री गोपाल व्यास जी का जन्म हुआ। बचपन से ही प्रतिभावान श्री गोपाल व्यास जी के भीतरराष्ट्र के प्रति अद्भुत समर्पण था और वह लोकसेवा के लिए सदैव तत्पर रहते थे।

श्री गोपाल व्यास जी ने जबलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उनके मन में जितनी लगन इंजीनियरिंग के प्रति थी, उतनी ही प्रबल भावना मातृभूमि की सेवा के प्रति भी व्यास जी के भीतर समाहित थी। यह वही समय था जब गोपाल जी ने मां भारती की सेवा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मार्ग चुना और वह श्री के एस सुदर्शन जी के संपर्क में आए।

संघ के संस्कार और सुदर्शन जी का मार्गदर्शन मिलने से युवा अवस्था के श्री गोपाल व्यास जी के व्यक्तित्व में मातृभूमि के प्रति जो सेवा का भाव था, वह और प्रगाढ़ होता चला गया। सामाजिक कार्यों और शिक्षा अर्जन करते हुए जब कुछ समय बीता और इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हुई तब गोपाल व्यास जी ने भिलाई स्टील प्लांट में नौकरी की। जीवन की व्यस्तता बढ़नेके बाद भी उन्होंने राष्ट्र के प्रति सेवा और सामाजिक कल्याण की भावना कात्यागनहीं किया।

श्री गोपाल व्यास जी के भीतर मां भारती की सेवा और छत्तीसगढ़ के लोककल्याण की भावना इस प्रकार निहित थी कि जब उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनकी नौकरी की वजह से वह समाज को समय नहीं दे पा रहे हैं, तब उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट की नौकरी से त्यागपत्र देकर पूर्ण रूप से स्वयं को समाज के प्रति समर्पित कर दिया।

गोपाल व्यास जी निरंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में रहे और उन्होंने प्रचारक जीवन प्रारंभ किया क्षेत्र कार्यवाह और क्षेत्र प्रचारक (मध्य क्षेत्र) जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ निर्वाहन किया और विश्व हिंदू परिषद विदेश संपर्क का भी दायित्व उन्हें प्राप्त हुआ। जिसका श्री गोपाल व्यास जी ने सच्ची श्रद्धा और लगन केसाथ निर्वाहन किया। यह वही समय था जब आपातकाल की विरुद्ध संघर्ष करते हुए श्री गोपाल व्यास जी1975 से 1977 तक रायपुर की जेल में बंद रहे और यहीं से श्री गोपाल व्यास जी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच "शीरू भईया" बनकर लोकप्रिय हो गए।

मुझे भी हमारे शीरू भईया (श्री गोपाल व्यास जी) के साथ एक लंबा वक्त बिताने का अवसर मिला,वर्ष 2003 में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब मुझेमुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी मिली थी। उस दौर का मुझे शीरू भईया के साथ यात्रा का एक संस्मरण याद में आता है कि हम किसी अन्य राज्य से दौरा पूरा करके राजधानी रायपुर लौटे थे तब शीरू भईया भी हमारे साथ थे। हवाई जहाज से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए मैंने अचानक ही उनसे कह दिया कि "हम आपके घर चलेंगे उन्होंने बड़ी ही प्रसन्नता से कहा कि आप घर आइये मैं तैयारी करके रखता हूं"। मैंनेशीरू भईया से कहा कि तैयारी जैसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है हम साथ ही चले चलते हैं, इस पर उन्होंने कहा कि "आप मुख्यमंत्री हैं आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए मीडिया के सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें कुछ समय बीत जाएगा तब तक मैं घर पहुंचकर सारी व्यवस्था देख लूंगा" उन्होंने इतना कहा और एयरपोर्ट से ही आंटो में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए।

राजधानी में जब मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है तब पुलिस और प्रशासन को ट्रैफिक की एक व्यवस्था निर्मित करनी होती है और कुछ मार्गों पर आवागमन थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाता है। जब शीरू भईया एयरपोर्ट से निकले उसकी कुछ ही देर में मुझे भी निकलना था, संयोग ऐसा बना कि जिस मार्ग से वह अपने घर जा रहे थे, उसी मार्ग से मैं भी उनके घर जा रहा था और ट्रैफिक व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मियों ने उसे मार्ग पर आवागमन रोक दिया, जिस मार्ग में उनका आंटो था।

शीरू भईया इतने सरल और सादगी से भरे व्यक्तित्व थे कि उन्होंने केवल एक बार व्यवस्था में लगे पुलिसकर्मी से इतना ही कहा कि "मुख्यमंत्री मेरे ही घर जा रहे हैं, भाई मुझे तो जाने दो" लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी तब वह शांतिपूर्वक अपने आंटो में ही बैठे रहे और जब मैं उनके निवास पहुंचा तब यह पता चला कि वह तो अभी तक घर पहुंचे ही नहीं है तब वायरलेस के माध्यम से पुलिस को यह सूचना दी गई और उनका आंटो ट्रैफिक से निकलकर उनके घर पहुंचा।

यह संस्मरण में जब भी याद करता हूं तब मुझे शीरू भईया की सादगी और उनकी सरलता आंखों के सामने दिखाई पड़ जाती है, उन्होंने कभी भी सत्ता को शक्ति नहीं बल्कि सेवा का मार्ग समझा। उनका मानना था कि हमें अपना जीवन सीमित संसाधनों में व्यतीत करना चाहिए और कभी भी सत्ता या अधिकारों से प्राप्त ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।

वह एक लंबे अरसे तक स्कूटर पर ही चला करते थे, 2006 से 2012 तक जब वह राज्यसभा सदस्य भी बन गए और उन्हें महासमुंद लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई तब भी वह बस के माध्यम से महासमुंद पहुंच जाया करते जबकि प्रशासन द्वारा उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था की जा सकती थी। शीरू भईया राज्यसभा सदस्य रहते हुए न केवल अपनी सांसद निधि का लोककल्याण के लिए बेहतर उपयोग करते थे बल्कि जब भी आवश्यकता होती तब वह अपनी तनख्वाह को भी सामाजिक कार्यों में समर्पित कर देते थे।

हम सभी ने प्राचीन काल के ऋषि मुनियों और संतों की कहानी सुनी है जो दूर जंगल में निवास करते हुए लोक कल्याण के लिए कार्य करते थे और वापस अपने उस छोटे से आश्रम में लौट जाया करते थे। शीरू भईया के पास कोई आश्रम तो नहीं था लेकिन टाटीबंध में भारत माता स्कूल के निकट उनका एक पुराना और छोटा सा मकान जरूर था। उस मकान में शीरू भईया जिस पलंग पर सोते थे, उस आधे पलंग पर उनकी किताबें रखी रहती थी। उन्होंने आजीवन किताबों का साथ नहीं छोड़ा वह शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, उनका यह मानना था कि हमें सदैव सीखने पर जोर देना चाहिए, नए विचारों को सुनना चाहिए और यदि परमात्मा ने हमें सक्षम बनाया है तब हमें स्वयं को समाज की सेवा में समर्पित करना चाहिए।

उस छोटे से पुराने मकान में जब कार्यकर्ता उनसे मिलने आते तब सभी उनसे यही आग्रह करते कि आप नया मकान क्यों नहीं ले लेते हैं? इस सवाल पर शीरू भईया एक मुस्कुराहट के साथ जवाब देते थे कि जीवन व्यतीत करने के लिए जितनी जगह चाहिए वह इस घर में पर्याप्त है। इसके बाद सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी जिद के साथ उन्हें इस बात के लिए राजी किया कि वह पुराना मकान छोड़कर नये मकान में चलें।अंततः सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पुराने मकान को विक्रय किया और विधायक कॉलोनी स्थित शीरू भईया के निवास स्थान पर उन्हें गृहप्रवेश करवाया।

श्री गोपाल व्यास जी का भारतीय जनता पार्टी के विचारों के प्रति पूरा विश्वास था संगठन के लिए अपने अंतिम समय तक वह निरंतर सक्रिय रहे।बीते दिनों जब भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया तब स्वयं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे थे और गोपाल व्यास जी को बीजेपी का सदस्य बनाया था।वह केवल एक औपचारिक सदस्य नहीं थे बल्कि अस्वस्थ होने से पहले तक जब भी संगठन से जुड़ा कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचता तब हमारे शीरू भईया उनका मार्गदर्शन करते और संगठन के प्रति विश्वास रखकर निरंतर जन सेवा के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरित करते थे।

अपनी सादगी,अपनी सरलता, अपने विचार और आदर्शों पर अडिग रहे श्री गोपाल व्यास जी (शीरू भईया) एक ऐसे आदर्श पुरुष के समान है जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए सेवा और समर्पण का पर्याय है। ऐसे व्यक्तित्व का देहावसान सामाजिक क्षेत्र के लिए अपूरणीय क्षति है जोकि कभी भी पूरी नहीं की जा सकती। शीरू भईयाके साथ व्यतीत किये समय को जब मैं स्मरण करता हूं तब उनके विचार मुझे आज भी प्रेरित करते हैं, उनका इस प्रकार जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि वह हमारे शीरू भैया को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और उनके विचारों से प्रेरित होकर नई पीढ़ी सामाजिक सेवा, लोककल्याण के महत्व को समझकर बेहतर समाज और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ पाए।

-लेखक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा हैं।

स्मृति शेष

डॉ. रमेश ठाकुर

शारदा सिन्हा ने ठुकरा दिए थे तमाम सियासी ऑफर

पछिले-पहिले करेनी छठ, मईया बरस तोहार, करिह क्षमा हे छठी मईया भूलचूक हमार...। संपूर्ण मैथिली-भोजपुरी समाज के अलावा समूचे संसार के लिए शारदा सिन्हा का विसर्जन गहरा आघात है। उनके बगैर भविष्य में कैसे होगी 'छठ पूजा', ऐसी कल्पना मात्र से लोग अभी से परेशान हैं। पूर्वांचल की बगिया से कोयल के उड़ जाने जैसा है स्वर कोकिला शारदा सिन्हा का नश्वर दुनिया को अलविदा कह देना। दिल्ली से लेकर मुंबई, मॉरीशस, अमेरिका, लंदन और जहां-जहां पूर्वांचली समुदाय के लोग रहते हैं, उन छठ घाटों पर अगर शारदा सिन्हा के गाने न बजे, तो वह सूने लगते थे। बीच छठ में शारदा सिन्हा के चले जाना भी सभी को अखर रहा है। दरअसल उनकी आवाज इस महापर्व को सजीव किया करती थी। शारदा सिन्हा न सिर्फ भोजपुरी समाज में, बल्कि समूची संगीत बिरादरी की अमूल्य धरोहर थीं। जब लीन होकर पूरे मदक्षेश में वह गाती थी तो ऐसा लगता था कि उनके कंठ में स्वयं सरस्वती बैठी हुई हैं। जाते वक्त भी वे अपने भीतर दैवीय शक्ति होने का एहसास करा गईं। छठ में उनका जाना इस बात का सीधा-सीधा संकेत देता है? देशी और पारंपरिक लोक संस्कृति की मूर्ति शारदा सिन्हा सदैव लोगों के दिलों में रची-बसी रहेंगी। 5 नवंबर की देर रात जब भोजपुरी कोकिला शारदा सिन्हा के न रहने की खबर आई, तो संसार चलते-चलते अचानक से ठहर गया। संगीत की दुनिया में शारदा का न रहना, 'कोयल बिना ना सोहे बगिया', जैसा माना जाएगा।

शारदा सिन्हा बड़ा खुशहाल और बाइजन्त जीवन जीके गईं हैं। उनका इस धरती पर अवतरण होना भी दैवीय चमत्कार जैसा ही रहा। आठ भाईयों के बाद वह जन्मीं। घर में सबकी लाडली-दुलारी हुआ करती थीं। माता-पिता ने बड़ी मन्नतें की थी कि उनके घर में किसी लक्ष्मी का आगमन हो? शारदा सिन्हा के रूप में उनकी इच्छा पूरी हुई। जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुआ था। जन्म के दो वर्ष के भीतर ही उन्होंने गाना गुनगुनाना आरंभ कर दिया था। 15 वर्ष में उनकी खनकती आवाज के लोग दीवाने हो गए थे। जब उनकी शादी हुई, तो सास को कताई पसंद नहीं था कि उनकी बहू गाना गाए। भारी विरोध के बाद भी उन्होंने अपना गायन यथावत रखा। जब देश-विदेश से प्रशंसाएं मिलने लगी, तो सास ने भी कह दिया, बहू तुम अच्छा गाती हो, गाती रहो। शारदा के पति ब्रज किशोर सिन्हा का निधन भी इसी वर्ष हुआ। उनके जाने के बाद से वह पूरी तरह टूट गई थीं। नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में मंगलवार देर रात जब उनके न रहने की खबर टीवी के जरिए उनके असंख्य प्रशंसकों ने सुनी, तो उनकी आंखें नम हो गईं। निधन के एक दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे अंशुमान सिन्हा को फोन करके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। अब, न रहने को खबर ने उन्हें भी दुखी कर दिया है। राष्ट्रपति से लेकर विपक्षी नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे समेत देशभर के तमाम नेताओं ने दुख प्रकट किया है। दरअसल वो थी ही सभी की चहेती। अस्सी-नब्बे दशक का वह दौर, जब उनके भजन और फिल्मी गानों का बोलबाला था। सलमान खान और भाग्यश्री अभिनीत फिल्म 'मैंने प्यार किया' में गाया गाना ....'कहे तोसे ये तोहरी सजनिया' ....इतना फेमस हुआ कि उन्हें राताँरात बड़ा फिल्मी सिंगर बना दिया, उसके बाद तो फिल्मी गानों की डिमांड एकाएक बढ़ गई। शारदा सिन्हा को राजनीति के ऑफर भी बहुतेरे मिले। शायद ही कोई ऐसा छोटा-बड़ा सियासी दल हो, जिसने उनको अपने यहां आने का निमंत्रण न दिया हो? लेकिन शारदा सभी ऑफरों को सहज ठुकराती गईं। कई मर्तबा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा भी कि उन्हें राजनीति बिल्कुल पसंद नहीं? समाज ने उन्हें छठ कोकिला की उपाधि दे रखी थी जिसे वह सबसे बड़ा सम्मान ताउम्र मानती रहीं। छठ पर अपनी मीठी आवाज से संगीत प्रेमियों की जुबान पर ऐसे चढ़ीं, कि कभी उतर ही नहीं पाई। छठी के गानों के अलावा भी उन्होंने विभिन्न भाषाओं में एक से एक हिट गाने दिए। देश के सर्वोच्च सम्मान से भी उन्हें केंद्र सरकार ने नवाजा। शारदा का जन्म बिहार के सुपौल के हुलास गांव में हुआ था। विवाह बेगुसराय में हुआ। वह गायिका के साथ-साथ प्रोफेसर भी रहीं। बीएड की पढ़ाई के अलावा उन्होंने म्यूजिक स्ट्रीम में पीएचडी की और समस्तीपुर के एक कॉलेज में प्रोफेसर बनीं। पर, उनकी रुचि सदैव गायिकी में ही रही। कॉलेज से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने संगीत की मुफ्त शिक्षा देना जारी रखा। उनके न रहने से एक युग का अंत हुआ है। उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। उनकी मीठी, मधुर, सुरीली आवाज श्रोताओं के कानों में सदा गूंजेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

योगः कर्मसु कौशलम

संकलित
दर्शन

चित्तवृत्ति का भगवान में विलीन हो जाना योग है। यह महायोग बनता है भगवान की अहैतुकी कृपा से! श्रीरामचरितमानस में जहां भी योग है, वह केवल ईश्वर विषयक ही है। उसका सात्त्विक प्रयोजन और कोई नहीं है। भी भरत चित्रकूट में भगवान के हृदय से मिलकर शून्य स्थिति को प्राप्त हो गए। न बुद्धि की सत्ता रही, न मन की चंचलता। चित्त में कोई संस्कार शेष न रहा। यही स्थिति योगी की होती है। वह योग करते-करते ईश्वर से एकाकार होकर प्रेम रस से भर जाता है। उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है और मन रिक्त हो जाता है। भक्त का योग जब भगवान से होता है, मन, बुद्धि और चित्त के साथ साधन अहं शून्य हो जाता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहं की स्वीकृति केवल साधन काल में ही होती है, पर साध्य की परम प्राप्ति में इनकी विस्मृति ही योग है।

श्रीमद्भगवद्गीता के सभी 18 अध्याय योग हैं। अर्जुन विषाद योग से प्रारंभ होकर गीता की 18 योगी की नदियां मोक्ष संन्यास योग बनकर श्रीकृष्ण समुद्र में जाकर पूर्णता को प्राप्त हो जाती हैं। द्वापर में जितना भार श्रीकृष्ण ने उठाया, उतना त्रेता में श्रीराम को नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि श्रीराम के साथ के लोग अनुकूल थे। उनका काल उनके अनुकूल था, जबकि भगवान कृष्ण को तो सारी गीता सुना-समझाकर, अपनी योगस्थिति को बाजी पर लगाकर अर्जुन से कहना पड़ा कि जितने धर्म मैंने तुझे बताए हैं, तू उन सबको छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर तुझे भी मुक्त कर दूंगा।

दूसरों की जरूरतें पूरी करना ही दान

संकलित
प्रेरणा

महाभारत का एक प्रसंग है। एक दिन युधिष्ठिर ने वेद व्यास से पूछा कि दान बड़ा है या पूजा-पाठ और तपस्या? व्यास जी ने युधिष्ठिर को अपनी बात समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। व्यास जी ने कहा कि एक मुद्गल नाम के महर्षि थे, वे भिक्षा मांगकर जीवन चलाते थे। भिक्षा में उन्हें आटा, खाने-पीने की चीजें, हवन सामग्री मिल जाती थीं। दान में मिली चीजों से ही वे खाना बनाते और पूजा-पाठ करते थे। कभी-कभी ऐसे दिन भी आते थे, जब उन्हें भिक्षा नहीं मिल पाती थी। अधिकतर अमावस्या और पूर्णिमा पर ऐसा हुआ करता था। इन दोनों तिथियों पर ऋषि मुद्गल से मिलने दुर्वासा ऋषि आया करते थे। दुर्वासा मुनि को खाना खिलाने के बाद उनके लिए कुछ बचता नहीं था तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। एक दिन फिर ऐसा ही हुआ तो दुर्वासा मुनि ने मुद्गल ऋषि से पूछा कि आप मुझे खाना देकर खुद भूखे रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी आपके चेहरे पर भूख के लक्षण नहीं देखे हैं, क्या आपको भूख नहीं लगती है? मुद्गलजी ने कहा कि मेरे लिए दान का महत्व सबसे ज्यादा है। अन्न दान तो सर्वश्रेष्ठ होता है, जब आपकी भूख शांति होती है, तब मैं भी तृप्त हो जाता हूं। मैं दान पुण्य कमाने के लिए नहीं करता हूं, मैं सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहता हूं। व्यास जी ने युधिष्ठिर को आगे समझाया कि तपस्या स्वयं के लिए की जाती है, लेकिन दान हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है। इसलिए दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति करना ही दान है। इसलिए दान तप से भी श्रेष्ठ है।

अंतर्मन

आज की पाती

जनसंख्या वृद्धि के नुकसान समझें

हाल ही में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में आम जन को जनसंख्या बढ़ाने के लिए जो कहा है, इसकी कड़ा इन दोनों ने अलग-अलग बताई। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को अपने यहां जनसंख्या बढ़ाने के लिए ऐसी बात करनी चाहिए, क्योंकि लोग अब समझदार हो रहे हैं और छोटा परिवार, सुखी परिवार पर विश्वास कर रहे है। लोग जानते हैं कि ज्यादा बच्चे देश, समाज और खुद के लिए भी उचित नहीं है। कोई समय था जब हमारे देश में पांच-सात बच्चे भी लोगों के होते थे, क्योंकि उस समय लोग जनसंख्या के दुष्परिणामों से अवगत नहीं थे। हालांकि अभी भी ऐसे लोग भी हैं जो बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभावों से अनजान हैं। कुछ लोग भारत की बढ़ती जनसंख्या पर अपने तर्क देते हैं। लेकिन इसके दुष्प्रभावों को समझा जाना चाहिए। *- वीरेंद्र कश्यप, बिलासपुर*

टेंड

मिलकर चलना होगा

कोई भी एक देश या कोई भी एक लक्ष्यान, चाहे वह विज्ञान भी शक्तिशाली क्यों न हो, टेररिज्म को अकेला हरा नहीं सकता। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को लगातार इस जटिल और बॉर्डर लेस खतरे के खिलाफ काम से लगा मिलकर चलना होगा।

-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

मैं एकाधिकार विरोधी

मैं नौकरियों का, व्यवसाय, नक्शावलि और प्रतिस्पर्धा का भी लगातार हूं। मैं एकाधिकार विरोधी हूं। हमारी अर्थव्यवस्था तभी पनपेगी-फूलेगी, जब सभी व्यवसायों के लिए स्थान और निष्पक्ष स्थान होगा।

-राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद

खाद की कालाबाजारी

भाजपाइयों ने सारी खाद दबा रखी है और खाद की कालाबाजारी कर रहे हैं। किसान किसान खलान के नाम पर दिया जा रहा है उससे ज्यादा खाद की कालाबाजारी ने लिया जा रहा है। किसान कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा।

-अखिलेश यादव, सपा सांसद

विजेता को बधाई देना बेईमानी

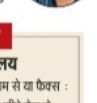

मुझे लगता है कि राजनीति में किसी हारे हुए व्यक्ति को विजेता को बधाई देना बहुत बेईमानी है। दशकों की परिणाम के बाद टूट वो बधाई देने के बजाय अमेरिकी लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए थी।

-रामगोपाल वर्मा, फिल्मकार

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

कनाडा में टिकटॉक का कारोबार होगा बंद

कनाडा ने टिकटॉक के कनाडाई कारोबार को बंद करने की घोषणा की। चीन की कंपनी की राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा के बाद कनाडा ने यह घोषणा करते हुए कहा कि वह इस ऐप तक पहुंच को ब्लॉक नहीं करेगा। उद्योग मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैम्पेन ने कहा कि इसका उद्देश्य टिकटॉक टेक्नोलॉजी कनाडा इंक द्वारा स्थापित बाइटडांस से संबंधित जोखिमों को दूर करना है। शैम्पेन ने कहा, 'सरकार कनाडाई लोगों की टिकटॉक एप्लिकेशन तक पहुंच या उनकी कंटेंट बनाने की क्षमता को ब्लॉक नहीं कर रही है। सोशल मीडिया एप्लिकेशन या मंच का उपयोग करने का निर्णय एक व्यक्तिगत पसंद है।' शैम्पेन ने कहा कि कनाडाई लोगों के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सहित अलग साइबर सुरक्षा कार्यप्रणाली को अपनाना महत्वपूर्ण है। टिकटॉक कनाडा ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। टिकटॉक युवा लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है, लेकिन इसके चीनी स्वामित्व की वजह से यह आशंका जताई गई है कि चीन इसका इस्तेमाल पश्चिमी उपयोगकर्ताओं का डेटा एकत्र करने या चीन समर्थक बयानों और गलत सूचनाओं को फैलाने के लिए कर सकता है। टिकटॉक का स्वामित्व बाइटडांस के पास है, जो एक चीनी कंपनी है।

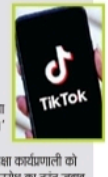

ऑफ बीट

सूर्य हमारे अस्तित्व के लिए क्या आवश्यक है

आज इस बात के बहुत ज्यादा सबूत नहीं हैं कि प्राचीन लोग मानते थे कि सूरज की रोशनी ही बीमारी को ठीक कर सकती है। इसके बजाय, इस बात के ज्यादा सबूत हैं कि वे ठीक होने के लिए सूरज की गर्मी का इस्तेमाल करते थे। एबर्स पेपीरस ईसा पूर्व 1500 साल के आसपास का प्राचीन मिस्र का चिकित्सा 'स्क्रॉल' है। इसमें 'नसों को लचीला बनाने' के लिए मरहम बनाने की विधि दी गई है। यह मरहम शराब, प्याज, कालिख, फल और पेड़ के अर्क लोबान और लोहबान से बनाया गया था। इसे लगाने के बाद, व्यक्ति को 'सूर्य के प्रकाश में रखा जाता था।' उदाहरण के लिए, खांसी के इलाज के लिए अन्य नुस्खों में विभिन्न सामग्री को एक बर्तन में डालकर धूप में रखना शामिल था। यही तकनीक चिकित्सा लेखन में भी है जिसका श्रेय यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स को दिया जाता है जिनका काल लगभग 450-380 ईसा पूर्व माना जाता है। लगभग 150 ई. में आधुनिक तुर्की में सक्रिय रहे चिकित्सक एरेटियस ने लिखा था कि सूर्य का प्रकाश सुस्ती सहित कई बीमारियों को ठीक कर सकता था। इसमें वह बीमारी भी है जिसे हम आज अवसाद के रूप में पहचानते हैं। सुस्ती मिटाने का अर्थ है प्रकाश में लेटना, सूर्य की किरणों के संपर्क में आना; तथा अपेक्षाकृत गर्म स्थान में रहना।

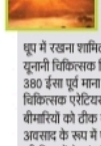

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 8 नवंबर 2024

रिश्तों पर आशा

भारत और अमेरिका के आपसी रिश्ते अब उस अवस्था में नहीं रह गए हैं कि उन्हें किसी खास पार्टी या नेता की अगुआई वाली सरकार की दरकार हो। लेकिन इसके बावजूद अगर अमेरिका में डॉनल्ड ट्रंप का फिर से राष्ट्रपति चुना जाना द्विपक्षीय रिश्तों के लिहाज से एक उत्साहपूर्ण घटना मानी जा रही है, तो यह बेवजह नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों के कई ऐसे पहलू हैं जहां वाइट हाउस में ट्रंप की मौजूदगी का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की उम्मीद की जा रही है।

ट्रंप और मोदी अच्छे दोस्त

संतुलन के लिए स्पेस | जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, भारत ने यह स्पष्ट नीति रखी है कि वह युद्ध के खिलाफ है, लेकिन रूस से अपनी पुरानी मित्रता पर कोई समझौता नहीं करने वाला। मोटे तौर पर सभी पक्षों ने भारत के इस रुख को स्वीकार भी किया है, लेकिन फिर भी वाइटन सरकार ने इस पर अपनी नाखुशी जताने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। ट्रंप के आने के बाद इस मोर्चे पर राहत की उम्मीद कई वजहों से है। ट्रंप कह चुके हैं कि वह रूसी राष्ट्रपति पूतिन को पसंद करते हैं। फिर, यूक्रेन युद्ध पर उनका चेहरा रुख भी बाइडन से अलग रहा है।

भारत की अहमियत | ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान चीन के साथ ट्रेड वॉर की पृष्ठभूमि में देखें तो यह संभावना निराधार नहीं है कि हिंद-प्रशांत में चीन की बढ़ी हुई आक्रामकता पर उनका रुख बाइडन सरकार के मुकाबले और कड़ा हो सकता है। दूसरे शब्दों में, उनकी नजर में भारत की अहमियत और ज्यादा होगी। हालांकि इसका नतीजा क्वॉड जैसे मंचों को सामरिक रूप देने पर जोर के रूप में भी आ सकता है, जिससे भारत इनकार करता रहा है।

बेहतर मौके | चीन के प्रति ट्रंप के संभावित कड़े रुख के साइड इफेक्ट के रूप में भारत को बेहतर मौके मिलें तो आश्चर्य की बात नहीं होगी। चीन से मुंह मोड़ने वाली कई कंपनियां भारत को विकल्प के रूप देख सकती हैं। वैसे भी ट्रंप के अगले कार्यकाल में अमेरिका और भारत के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है।

क्या हैं आशंकाएं | तमाम उम्मीदों के बीच ट्रंप के इस कार्यकाल को लेकर कुछ ठोस आशंकाएं भी हैं। सबसे बड़ा सवाल प्रवासियों पर उनके रुख को लेकर है। देखने वाली बात यह होगी कि उनकी सरकार अवैध प्रवासियों को ही निशाना बनाती है या वैध तौर पर आने वाले हाई स्किल्ड प्रफेशनल्स की राह को भी मुश्किल बनाती है।

नजरिया पॉजिटिव | बहरहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉनल्ड ट्रंप, पीएम मोदी और भारत को लेकर दोस्ती का भाव रखते हैं और नजरिया पॉजिटिव हो तो रिश्तों के दरम्यान आने वाले छोटी-मोटी बाधाएं यूं ही दूर होती रहती हैं।

बात बराबर की

एक सपना ऐसा भी

शैलेंद्र पांडेय

लैटिन में Nicolaigarden का मतलब है समानता। स्वीडन में इसी नाम से चल रहे पले स्कूल ने इस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से अपना लिया है। यहां लड़का और लड़की का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। यहां सब्बे बस बच्चे हैं और टीचर बस टीचर। न ड्रेस का अंतर होता है, न रंगों, खिलौनों और न भाषा का। स्वीडन दुनिया के उन चंद देशों में शामिल है, जहां लैंगिक समानता के लिए लंबे वक्त से प्रयास चल रहे हैं और इस तरह के प्ले स्कूल उसी प्रयास की एक कड़ी हैं। यहां कोशिश होती है कि बाहरी दुनिया में कदम रखने पर बच्चों को ऐसा माहौल मिले, जिसमें भेदभाव नाम की चीज न हो। बच्चा उस पहचान से जुड़े, जिसमें वह सहज महसूस करता है।

जेंडर न्यूट्रिलिटी होनी चाहिए, शायद ही कोई इससे इनकार करे, लेकिन असली सवाल है कि कैसे? किस तरह से लैंगिक समानता को अपनाया जाए? भेदभाव दूर करने वाला कोई इंजेक्शन तो होता नहीं कि उसे लगाया और बीमारी पर हमला शुरू। इसका जवाब मिलता है साझा संस्कृति वाले Nordic देशों यानी आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क में। महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के लिए ये देश सामूहिक तौर पर जो काम कर रहे हैं, वे दूसरों के लिए एक उदाहरण है। स्वीडन ने सबसे पहले 1974 में जेंडर न्यूट्रल पेड पैरेंटल लीव की शुरुआत की थी। फिर 1979 में Gender Equality Act लाया गया, जिसके जरिये महिलाओं और पुरुषों को बराबर हक और अधिकार मिले। भेदभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है काम के बंटवारे में। घर चलाने और घर के लिए कमाने की जिम्मेदारी पारंपरिक समाज में जिस तरह से बांटी गई है, उससे कहीं न कहीं पलड़ा पुरुषों की तरफ झुक जाता है। महिलाएं काम तो करती हैं, लेकिन उसकी कोई गिनती नहीं होती। नॉर्डिक देशों का सबसे बड़ा प्रयास यही रहा कि लिंग के आधार पर काम का फैसला न हो, सभी को सारे काम करने का बराबर मौका मिले। इसके लिए उन मजबूरियों को दूर करने की कोशिश हुई, जिनके चलते महिलाएं घर के बाहर कदम नहीं रख पातीं। महिलाओं और पुरुषों को बराबर वेतन, बराबर छुट्टियां और काम के फ्लेक्सिबल घंटे रखे गए। ज्यादा से ज्यादा किंडरगार्टन खोले गए, जिससे महिलाओं के सामने यह दुविधा न रहे कि उन्हें परिवार और ऑफिस में से किसी एक को चुनना होगा। इन प्रयासों ने आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य के आधार पर बनने वाले ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इन मुल्कों को टॉप पर पहुंचा दिया है। पिछले कुछ बरसों से इनमें आइस में ही होड़ मची है कि कौन नंबर वन पर रहता है।

Nordic देश ऐसा समाज बनाना चाहते हैं, जो आदर्श हो और जिसमें फिर जेंडर और सेक्स कोई मुद्दा ही न रह जाए। Nicolaigarden से वे अपना यही सपना भविष्य की पीढ़ी में रोप रहे हैं।

एकदा

संगीत की क़ीमत

मैहर घराने के प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खान के पास दूर-दूर से लोग संगीत सीखने और चर्चा करने आते थे। वह अमीर-गरीब, सभी को समान भाव से शिक्षा देते। एक बार वह अपने बगीचे में काम कर रहे थे। वह साधारण कपड़ों में थे और उनके हाथ-पांव मिट्टी से सने थे। उसी समय सूट-बूट पहने एक व्यक्ति आया और बोला, 'ए माली, उस्ताद कहां हैं? मुझे उनसे मिलना है।' खां साहब ने पूछा, 'क्या काम है?' उस व्यक्ति ने कहा, 'मुझे उनसे संगीत सीखना है।' खां साहब ने कहा, 'वह अभी आराम कर रहे हैं।' उस व्यक्ति ने कहा, 'जाकर उस्ताद से कहो, कोई बड़ा आदमी मिलने आया है।' खां साहब बोले, 'आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं हुजूर? अभी जाता हूं।' वह पिछले दरवाजे से घर में गए और थोड़ी देर में अगले दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। उसी समय एक कार खान साहब के पास आकर रुकी। उसमें रामपुर के राजा और कुछ अन्य लोग थे। राजा ने खां साहब के पैर छुए। उस व्यक्ति को समझते देर न लगी कि यही उस्ताद अलाउद्दीन खान हैं। अब वह परेशान हो गया। उसने खां साहब से कहा, 'हुजूर, मुझे आपको पहचानने में भूल हो गई। माफ कर दें।' खां साहब ने कहा, 'तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। यह तुम्हारी दौलत में छिपे अहंकार का दोष है। जहां तक रही बात संगीत सीखने की, तो याद रखो, जिसके पास अहंकार आ जाता है, उसके दिल में संगीत कभी जन्म नहीं ले सकता।' जब उस व्यक्ति ने खां साहब को धन का प्रलोभन दिया, तो खां साहब ने साफ शब्दों में कहा, 'संगीत रुपये-पैसे से नहीं खरीदा जाता। सिर्फ मेहनत से ही उसे हासिल किया जा सकता है।'

संकलन : दीनदयाल मुरारका

आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, उसमें सभी देश अपना भला सोच रहे हैं

क्या भारत की पकड़ में आएंगे डॉनल्ड

सचिन शर्मा

अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई सर्वे हुए। इनमें जिस सर्वे के एक सवाल के जवाब ने मुझे चौंकाया, उसमें हर 10 में से 7 ने कहा, 'इस देश को बड़े बदलाव की जरूरत है, नहीं तो इसके टुकड़े हो जाने चाहिए।' अब अमेरिकियों ने डॉनल्ड ट्रंप को अपना राष्ट्रपति चुन लिया है, जिन्हें वाइट हाउस में अब तक सबसे ज्यादा उथलपुथल मचाने वाला माना जाता है।

क्या वादा पूरा होगा | ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि वह शपथ लेने वाले दिन ही 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। दुनिया की नजरें इस पर होंगी कि इस वादे को लेकर वह क्या करते हैं। पहले ही दिन उन्होंने अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स और सहयोगी देशों से आने वाले सामान पर 20% शुल्क लगाने का भी वादा किया था।

मोलभाव का पैंतरा | ट्रंप ने यह भी कहा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ मुकदमा चलवाएंगे और संघीय नौकरशाहों के बदले राजनीतिक व्यक्तियों को नियुक्त करेंगे। वैसे, उनकी टीम ने इन मुद्दों के बारे में यही कहा कि ये सिर्फ बातें हैं, इन पर अमल नहीं किया जाएगा या इनमें से कुछ के आधार पर दूसरे देशों के साथ मोलभाव किया जाएगा।

लोग हैं बेहाल | आम अमेरिकियों ने बड़े बदलाव का वादा करने वाले प्रत्याशी को चुना। उनका मानना है कि अभी जो व्यवस्था है, उसमें आम लोगों की नहीं सुनी जा रही। दुनिया भले ही अमेरिकी कंस्यूमर्स की ताकत को मजबूत मानती हो, लेकिन यहां वेपरों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे लोग भी बढ़ रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का बकाया नहीं चुका पा रहे। अमेरिका में आय के लिहाज से निचले स्तर पर जो 40% लोग हैं, उनका देश में कुल खर्च में योगदान 20% है। दूसरी ओर, जो सबसे अमीर 20% हैं, उनका खर्च में 40% योगदान है। यह बहुत बड़ा अंतर है।

हैरिस की गलती | कोविड महामारी के दौर में ग्राहकों का भरोसा टूट गया था। उसके बाद इसमें रिकवरी तो आई है, लेकिन यह अमीर लोगों में जितनी ज्यादा दिख रही है, उतनी मध्यमवर्गीय और कम आय वर्ग में नहीं। कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार के दौरान बदलाव का वादा किया। शायद यह शब्द उतना प्रभावशाली नहीं था, जिसकी वोटरों की उम्मीद थी।

सही मुद्दे उठाए | ट्रंप ने प्रचार के दौरान कमरतोड़ महंगाई, हिंसक अपराध, अवैध प्रवासियों की घुसपैठ और अमेरिका को तबाह करने की कोशिश में जुटे 'डीप स्टेट' जैसे मुद्दे उठाए। लोगों में बाइडन राज के दौरान लालफीताशाही को लेकर गुस्सा था। ऐसे में उन्हें ट्रंप सही प्रत्याशी लगे।

खराब रेकॉर्ड | वैसे, कई मामलों में पहले कार्यकाल में ट्रंप पारंपरिक रिपब्लिकन राष्ट्रपति जैसे ही थे। उन्हें हर मर्ज का एक ही इलाज दिखा- टैक्स कटौती। 2017 में उन्होंने

टैक्स में जो कटौती की, वह बगैर किसी संकट के दिया गया सबसे बड़ा राहत पैकेज था। आखिर में उनकी आर्थिक नीतियां वैसी ही निकलीं, जैसी कि पिछली आधी सदी से दोनों पार्टियों की रही हैं। यानी बढ़ते सरकारी घाटे से बेपरवाह रहना।

सरकारी घाटा बढ़ेगा | बाइडन के आने के बाद इसमें और इजाफा हुआ। अब ट्रंप कह रहे हैं कि वह टैक्स में कटौती और बढ़ाएंगे। अभी घाटा GDP के 6% से अधिक है। कुछ अनुमान के मुताबिक, अगर टैक्स में कटौती का वादा ट्रंप पूरा करते हैं तो घाटा बढ़कर कुछ वर्षों में GDP के 7-8% तक चला जाएगा। इसके साथ पब्लिक डेट में भी बढ़ोतरी होगी, जो पहले ही GDP के 100% से अधिक है और यह एक रेकॉर्ड है।

नीति-निर्माताओं की सोच | अमेरिकी नीति-निर्माता अपने यहां की अर्थव्यवस्था पर फख्र करते हैं। उन्हें लगता है कि टेक्नॉलजी में बादशाहत की बदौलत उनका देश जापान, यूरोप और यहां तक कि चीन को भी धूल चटा चुका है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि अमेरिकी इकॉनमी के इस कमाल की वजह बढ़ता सरकारी घाटा है। उन्हें लगता है कि यह घाटा इसलिए मायने नहीं रखता क्योंकि दुनिया अमेरिकी बॉन्ड और दूसरे एसेट्स खरीदती रहेगी। जब इस घाटे की वजह से बॉन्ड मार्केट विद्रोह कर देगा और दूसरे देश अमेरिकी असेट्स खरीदना बंद या कम कर देंगे तो यह कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाएगा। लग रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में फिस्कल क्राइसिस हो सकता है।

बाजार के संकेत | लेकिन चुनावी नतीजे आने के बाद अमेरिका के शेयर बाजार और डॉलर में तेजी आई क्योंकि मार्केट को लग रहा है कि ट्रंप जो आयात शुल्क लगाएंगे, उससे दूसरे देशों को नुकसान होगा। लेकिन अगर बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी होती रही तो यह खयाल जल्द ही बदल सकता है। बॉन्ड यील्ड बढ़ने पर सरकारी घाटे की लागत और बढ़ेगी।

भारत को फायदा | जब भी डॉलर कमजोर होता है, भारत जैसे उभरते हुए देशों को लाभ होता है। यह भी सच है कि आज अमेरिका के अजेंडा में भारत बहुत ऊपर नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान शायद ही भारत का जिक्र हुआ हो। लेकिन यह अच्छी बात ही है। जिन देशों का जिक्र हुआ, उन्हें अमेरिका में आशंका की नजर से ही देखा जाता है। इनमें मेक्सिको, चीन, रूस और यूक्रेन शामिल हैं।

भारत का सम्मान | भारत का एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सम्मान है। उसे चीन के खिलाफ सहयोगी माना जाता है। लेकिन भारत को यह याद रखना होगा कि ट्रंप ऐसे दौर में अमेरिका का नेतृत्व करने जा रहे हैं, जब दुनिया का हरेक देश अपने हित में कदम उठाएगा। आज कोई भी देश दूसरे पर पूरी तरह आश्रित नहीं है और ट्रंप के अमेरिका से तो यह आशा भी नहीं करनी चाहिए।

(लेखक न्यूयॉर्क में रहते हैं)

निष्पक्षता से संतुलन, पक्ष चुना तो गिर जाएंगे

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं(न्), नित्यतृप्तो निराश्रयः।
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि, नैव किञ्चित्करोति सः॥

सुरक्षित गोस्वामी

महाभारत की युद्धभूमि में जब भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला मनुष्य ज्ञानी है, तो इसमें एक भाव निष्पक्षता का भी था। किसी बंधन में फंसे बिना सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना। ऐसे इंसान को न किसी की चिंता होती है और न वह निर्भर होता है किसी बाहरी परिस्थिति पर। वह कर्म करता है, लेकिन उसमें आसक्त नहीं रहता। उसके लिए कर्म और अकर्म एक समान हो जाते हैं। पत्रकारिता भी यही है, जिसमें कर्तव्य है, लेकिन कर्म के फल की चाह नहीं। इसमें निष्पक्षता है, कोई पक्ष या विपक्ष नहीं। इसमें लोकहित की चिंता है, किसी के प्रति आसक्ति नहीं।

खबरों का खेल | जर्नलिज्म की दुनिया बनी होती है खबरों से और कोई भी खबर खालिस अच्छी या बुरी नहीं होती। खबर बस एक खबर है, एक सूचना जो आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एक अखबार को न तो किसी खबर से खास प्यार होता है और न किसी से कोई दुश्मनी। परिस्थितियां तय करती हैं कि किसी को कितना महत्व मिलेगा। यही निष्पक्षता है। जर्नलिज्म अगर खबरों के मोह में फंस गई, तो सही मूल्यांकन करना ही भूल जाएगी। फिर वह भी पक्ष-विपक्ष चुनना शुरू कर देगी और जहां पाले चुने जाते हैं, वहां आमतौर पर लालच होता है। असल पत्रकारिता इस लालच से बाहर है।

संतुलन साधना | सर्कस में रस्सी पर चलने वाला करतब आप सभी ने जरूर देखा होगा। हाथों में लाठी थामे कलाकार डगमगाता जरूर है, लेकिन तुरंत ही संभल भी जाता है। वह कभी दाएं झुकता है, तो कभी बाएं, लेकिन कभी अपने द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास को इधर-उधर नहीं जाने देता। उसे पता है कि रस्सी को पार करने के लिए उसे इस संतुलन को साधना है। यही संतुलन होता है आदर्श पत्रकारिता में। मुश्किल वक्त में भी वह अपना रास्ता नहीं छोड़ती। उसे पता है कि किस तरह बैलेंस बनाकर चलना है। जब वह इस बैलेंस को छोड़ती है, तो नीचे गिर जाती है और तब उसके साथ उसकी साख भी गिरती है। मिट्टी उसकी प्रतिष्ठा पर लगती है और लोग मजाक उड़ाते हैं उसका।

निष्पक्षता सागर जैसी | समुद्र में हमारी पवित्र नदियों का जल मिलता है और सीवर का गंदा पानी भी। उनको अपनाने में सागर कभी भेद नहीं करता। निष्पक्षता भी इसी तरह विशाल है, जो अपने भीतर सब कुछ समा लेती है। अगर जर्नलिज्म ने पक्ष चुनना शुरू कर दिया, तो उसके सामने एक विपक्ष भी होगा। ऐसे निष्पक्षता के मायने नहीं रह जाएंगे। किसी विचारधारा का समर्थन कर एक वर्ग को खुश किया जा सकता है, लेकिन फिर दूसरे वर्ग की उतनी ही बड़ी नाराजगी मोल लेनी होगी। एक वर्ग जितना करीब आएगा, दूसरा उतना ही दूर जाएगा। समाज के एक तबके से दूरी क्या पत्रकारिता का पतन नहीं होगी?

विश्वास का रिश्ता | जर्नलिज्म की सबसे बड़ी पूंजी है भरोसा। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आज लोगों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है। इसके बावजूद अगर अगली सुबह लोग अखबार खोलकर उस खबर की पुष्टि करते हैं, तो उसकी वजह है भरोसा और इस भरोसे की बुनियाद है निष्पक्षता। इसने ही अखबार को उसके पाठकों से जोड़कर एक मजबूत रिश्ता बना दिया है। इसलिए यह निष्पक्षता कायम रहे। इस निष्पक्षता को छोड़ने का मतलब है भरोसे के रिश्ते पर कुल्हाड़ी मारना।

तथ्यों का आधार | निष्पक्ष पत्रकारिता में दोनों पक्षों को समान रूप से रखा जाता है और समाज की व्यवस्था, नैतिकता और संविधान के तहत खबरें पेश की जाती हैं। हां, विरोध या समर्थन वहां भी होता है, लेकिन तथ्यों के आधार पर। उसमें व्यक्तिगत लगाव या दुराव नहीं होता, अपने मतलब नहीं साधे जा रहे होते। यह याद रखना चाहिए, एक अखबार को पाठक अच्छी तरह से समझता है कि उसके सामने खबर किस मंशा से परोसी गई है।

THE SPEAKING TREE
और पढ़ने के लिए देखें
www.speakingtree.nbt.in

शब्द कभी मरते नहीं, ज़बान को संभालना सीखें

आशुतोष महाराज

एक गांव की बात है। एक बच्चा अपने विद्यालय की तरफ जा रहा था। रास्ते में घना जंगल पड़ता था। सहसा उसे कुछ सरसराहट सुनाई दी। वह चीखा, 'तू कौन है?' जवाब में वही गूंज सुनाई दी, 'तू कौन है?' लड़कपन में बच्चा फिर चिल्लाया, 'ओए! एक बार सामने तो आ।' फिर वही जवाब, वही स्वर, वही शैली! बालक घबराया। दौड़कर लौटा और मां के आंचल में पनाह ली। मां ने समझाया, 'बेटे, तू डरता क्यों है? वन तो तेरा मित्र है। अच्छा, कल तू उसे मित्रवत पुकारना। अगले दिन वन पहुंचकर बच्चा तेज आवाज में बोला, 'कैसे हो तुम मित्र?' प्रतिध्वनि हुई, 'कैसे हो तुम मित्र?'

यह वन एक छोटा-सा मॉडल है इस पूरी दुनिया का। आप जैसी ध्वनि का उच्चारण करेंगे, बदले में वैसी ही सुनेंगे। वायुमंडल आपके हर शब्द, उसकी सख्त-नरम, ऊंची-नीची शैली- हर चीज को बारीकी से सोख लेता है। फिर एक न एक दिन उसकी प्रतिध्वनि सूद समेत जरूर लौटाता है। यह बात दार्शनिक ही नहीं, वैज्ञानिक भी है। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं, तो उसका ब्लू प्रिंट ऊर्जा तरंगों के रूप में वायुमंडल में ठहर जाता है। दूसरा, ये शब्द तरंगें कभी नष्ट नहीं होतीं। जैसा कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, 'ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।' विज्ञान कहता है कि ये ऊर्जा तरंगें एक बंद घेरे (Closed loop) में घूमा करती हैं। आप एक विद्युत सर्किट की जांच करके देख लीजिए। उसमें विद्युत सिग्नल जिस बिंदु से शुरू होगा, घूमकर उसी पर रुकेगा। यही आदत हमारी शब्द या कर्म तरंगों की भी है। आइंस्टीन की Theory of relativity बताती है कि ब्रह्मांड भी एक बंद घेरा है। यदि हम ब्रह्मांड के एक बिंदु से यात्रा करना शुरू करें तो एक न एक दिन फिर उसी बिंदु पर ही पहुंचेंगे। जो तरंग हमसे निकली है, एक दिन हमारे पास वापस लौटकर आएंगी।

हम सभी शेशमहल में रहते हैं। चारों ओर शीशे ही शीशे हैं। इनके बीच रहते हुए अगर हम गुरांए और मुसकुराहट की आशा रखें, तो यह हमारी मूर्खता ही होगी। मुसकुराएंगे तो मुसकुराहट मिलेगी, गुरांएंगे तो गुर्राहट। हितैषियों ने इस सूक्ष्म विज्ञान को बड़े सरल ढंग से हमारे लिए पिरोया, 'चार वेद छह शास्त्र में, बात मिली है दोय। सुख दीने सुख होत है, दुःख दीने दुःख होय।'

यही कर्मवाद सिद्धांत है। अब सोच लीजिए, हम किसी दूसरे का दिल दुखा कर स्वयं के लिए दर्द का सामां जोड़ते हैं। यह नादानी क्यों करते हैं? यह एक महाप्रश्न है। हो सकता है कि इसके जवाब में आपकी बुद्धि शास्त्रार्थ करे, 'इमाल्लोकान्ज्ञान्त्वा न हिन्सिस्', शांत मन किसी प्राणी को कष्ट नहीं देता। मैं अशांत हूं, इसलिए दूसरों को भी अशांत करने की कोशिश कर डालता हूं। मैं क्या करूं? आदत से लाचार हूं।

लेकिन याद रखें, हम इस बहाने की पतली गली से बचकर नहीं निकल सकते। प्रकृति दंड बरसाने से पहले हमारी विवशता या अज्ञानता नहीं देखेगी। सलामती इसी में है कि हम जुबान को संभालना सीखें। मधु-घुली भाषा बोलें। यदि अशांत मन विघ्न डालता है, तो उसे ब्रह्मज्ञान आधारित ध्यान-साधना से शांत करें। यही शांत रहने और शांति बिखेरने की कुंजी है।

महाराष्ट्र में वोट ट्रांसफर है बड़ा सवाल

पूनम पाण्डे

महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। महायुति और महाविकास अघाड़ी, दोनों ही वोटरों को लुभाने में जुटे हैं। घोषणापत्र में लुभावने वादे किए गए हैं। इनके जरिए दोनों गठबंधन उम्मीद कर रहे हैं कि अगली सरकार उनकी ही बनेगी। BJP सबसे ज्यादा 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वह मान रही है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना का उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। जमीन पर भी इसका असर है। महिलाओं के अकाउंट में पैसे आए हैं और एक दिन पहले ही महायुति सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि को 1500 से बढ़ाकर 2100 करने का एलान किया है। BJP को उम्मीद है कि इस स्कीम की बदौलत उसे महिलाओं का समर्थन मिलेगा। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की स्कीम ने BJP के पक्ष में काम किया।

एक्टिव हो चुका है संघ

BJP के नेता अनौपचारिक बातचीत में बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बहुत सारे पार्टी समर्थक वोट देने पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे। वे छुट्टी मनाने निकल गए। वे इसे लेकर आत्मग्लानि में हैं कि उनके वोट देने न जाने से BJP की सीटें कम हुईं। इसलिए अब वे बढ़-चढ़कर काम कर रहे हैं और मोटिवेटेड हैं। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काफी मजबूत है। संघ ने वोटिंग से पहले छोटी-छोटी करीब 60 हजार बैठकें करने की योजना बनाई है। संघ लोकसभा चुनाव के वक्त एक्टिव नहीं था लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव में वह सक्रिय दिखा और महाराष्ट्र में भी काम कर रहा है। साथ ही BJP को काडर बेस पार्टी होने का भी फायदा होगा। BJP के अलग-अलग प्रदेशों के नेताओं ने महाराष्ट्र में डेरा डाला है और वे अलग-अलग रीजन में पूरा चुनाव मैनेजमेंट देख रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए एक बड़ा फैक्टर यह भी है।

वहीं NCP (SP) के प्रमुख शरद पवार की इमोशनल अपील कुछ इलाकों में BJP की दिक्कत बढ़ा सकती है। BJP नेता भी अनौपचारिक बातचीत में इसे मान रहे हैं। शरद पवार ने इसे अपना आखिरी चुनाव बताते हुए लोगों से साथ देने की अपील की है।

BJP को नुकसान

मराठा आरक्षण आंदोलन का चेहरा मनोज जरांगे ने भी अपने कैंडिडेट वापस ले लिए हैं। इसका BJP को नुकसान होगा। अगर जरांगे के कैंडिडेट रहते तो महाविकास अघाड़ी के वोट बंटते और BJP को फायदा होता। स्थानीय स्तर पर BJP नेता लगातार कह रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से महाराष्ट्र में OBC लीडरशिप खत्म हो गई है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भले ही OBC हों, लेकिन BJP के लोग भी मान रहे हैं कि OBC में BJP को बड़ा नुकसान हुआ है। BJP नेताओं को यह चिंता भी सता रही है कि अजीत पवार की NCP के वोट BJP को ट्रांसफर होंगे या नहीं। BJP के एक नेता ने कहा कि शिवसेना और BJP नैचरल पार्टनर हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वोट तो BJP को ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन NCP को लेकर हम पूरे भरोसे से यह बात नहीं कह सकते।

नाराजगी का नैरेटिव

मुंबई, पुणे सहित अर्बन एरिया में यह नैरेटिव भी दिख रहा है कि मिडल क्लास को कुछ नहीं मिला। जहां मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना से BJP महिलाओं के सपोर्ट की उम्मीद कर रही है वहीं मध्य वर्ग और टैक्सपेयर्स में इसे लेकर नाराजगी भी दिख रही है। यह नैरेटिव भी चल रहा है कि महाराष्ट्र से बिजनेस गुजरात जा रहा है। ऐसी बातें BJP के लिए चिंता का सबब हैं। इससे BJP को अर्बन एरिया में नुकसान का डर है। महाराष्ट्र में इसकी भी खूब चर्चा है और नाराजगी भी है कि BJP की वजह से राजनीति में गयाराम फैला है, दो शिवसेना, दो NCP मिलाकर सात पार्टियां हो गई हैं।

हरियाणा की जीत से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। BJP समर्थकों के बीच यह चर्चा का विषय है कि पार्टी कमजोर हुई तो हिंदुओं पर हमले शुरू हो गए। यूपी सीएम का बयान- 'बंटेंगे तो कटेंगे' भी अपना असर दिखा रहा है। BJP नेता मान रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक एकजुट हो रहा है, जिसका फायदा मिलेगा। ध्यान, सेहपाकीन और कपास किसानों की जो नाराजगी थी उसे लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र सरकार ने दूर करने की कोशिश की।

विशुद्ध राजनीति
कसौटी

BJP के एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस यह नैरेटिव चलाने में सफल रही थी कि संविधान बदलेगा और आरक्षण खत्म होगा। लेकिन अब यह नैरेटिव खत्म हो गया है।

टिकट बंटवारे और गठबंधन के साथियों के साथ सीट शेयरिंग के बाद BJP में बगावत के खुब सुर फूटे। कई ने इसीपल दिया, कई विदक गए। इसका असर भी नतीजों पर दिखेगा। हालांकि BJP नेताओं का कहना है कि महायुति से ज्यादा बगावत महाविकास अघाड़ी में है, इसलिए इसका कोई खास नुकसान BJP को नहीं होगा।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ भारतीयों का मिला साथ
7 नवंबर का संपादकीय 'निष्पक्षता का फायदा' पढ़ा। डॉनल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति होंगे और वह 20 जनवरी 2025 को इस पद के लिए शपथ लेंगे। उनके प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छे संबंध रहे हैं। उनमें समानताएं भी हैं। मोदी जी ने 'मेक इंडिया' को प्राथमिकता दी, तो ट्रंप ने भी 'मेक अमेरिका, ग्रेट अमेरिका' का नारा दिया। ट्रंप ने हिंदुत्व की तारीफ की और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का उन्होंने साथ भी मिला। इससे पता चलता है कि दोनों नेताओं की सोच मिलती है। लेकिन दोनों में अंतर भी है। ट्रंप गुस्सैल और बहुबोले हैं जबकि मोदी कम बोलने में यकीन रखते हैं।
चंद्र प्रकाश शर्मा, रानी बाग

■ अच्छे होंगे रिश्ते
यह पत्र 7 नवंबर के लेख 'ट्रंप की वापसी से कैसे बदलेगी दुनिया' से संबंधित है। भारत के लिए ट्रंप की जीत एक अच्छा संकेत है। हालांकि ट्रंप के पिछले प्रशासनिक काल 2016-2020 के दौरान भारत-अमेरिका के संबंधों में कई उतार-चढ़ाव देखने को मिले। पूरी दुनिया ट्रंप की जीत को इस रूप में देख रही है कि इस बार वह अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहराएं और बेहतर संबंध स्थापित करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, लोकतांत्रिक मूल्य और क्षेत्रीय सुरक्षा को ट्रंप प्रशासन की सहमति और समर्थन मिल सकता है।
संजय चौधरी, ईमेल से

■ याद रहेंगी शारदा
बिहार की मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा के आकस्मिक निधन से उनके करोड़ों प्रशंसक सदमे में हैं। छठ का त्योहार चल रहा है। उनके गाए गीत कानों में पड़ते हैं, तो वे सारे दृश्य नजर के सामने घूम जाते हैं, जो गांवों में छठ के मौके पर देखने को मिलते हैं। अब वह हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनकी आवाज उनके होने का अहसास कराती रहेगी। उन्होंने फिल्मों में भी कई लोकप्रिय गीत गाए हैं। उनकी गायकी में बिहार के ग्रामीण जीवन, महिलाओं के संघर्ष और पलायन के मुद्दे भी उभरते हैं।
विपीन राणा, ईमेल से

nbtedit@timesofindia.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र
बिना गारंटर मिलेगा 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन- एक खबर। – बैंकों पर भारी न पड़ जाए आज के युवाओं पर इतना भरोसा।
शिवानी गुप्ता

नवभारत टाइम्स, ISSN 2394-8159, रजिस्ट्रेशन नंबर एमएचएमयू/डीएनडी/डीएलडी/टीएनएल/2022-24, रजिस्ट्रेशन अनुसूची के लिए संपूर्ण पत्रकारिता सूचना, प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 110001 के अधी

कल्पमेधा

कभी-कभी आप दीवारें दूसरों को दूर रखने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि इसलिए खड़ी करते हैं कि आप ये देखना चाहते हैं कि इन्हें कौन तोड़ने की कोशिश करता है।

- सुकरात

महंगाई का दुश्चक्र

अर्थव्यवस्था के चमकते आंकड़ों की खबरें सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर इस चकाचौंध के बीच बहुत सारे लोगों को खाने-पीने के सामान में भी कटौती करनी पड़े, तब यह सोचने की जरूरत है कि आर्थिक विकास के दावों के दायरे में कौन है! अन्य जरूरी सामान के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की चढ़ी हुई कीमतों ने पहले ही आम लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को प्रभावित करना शुरू कर दिया था, लेकिन इस बीच पिछले कई महीनों से सब्जियों के दाम लगातार इस स्तर पर बने हुए हैं कि लोगों की थाली से सब्जियां भी गायब रहने लगी हैं। मुश्किल सिर्फ सब्जियों तक नहीं सिमटी है। इसका असर दूसरे खाद्य पदार्थों पर भी पड़ा है और अनाजों की खरीदारी के वक्त भी लोगों को अब थोड़ा रुक कर सोचना पड़ जाता है। गौरतलब है कि बुधवार को जारी एक एजंसी की ताजा रपट के मुताबिक शाकाहारी थाली की कीमत में एक वर्ष पहले की समान अवधि की तुलना में बीस फीसद तक की बढ़ोतरी हो गई है।

दरअसल, कम आय वर्ग के लोगों के लिए पिछले कई महीनों से खाने-पीने का सामान सहजता से खरीदना मुश्किल ही था। मगर अब स्थिति यह हो गई है कि ऐसे लोग अक्सर दिख जाते हैं, जो बाजार में सब्जियों की कीमतें पूछते हैं और बिना खरीदे मायूस मन के साथ आगे बढ़ जाते हैं। रपट के मुताबिक, अक्तूबर में प्याज की कीमतें सालाना आधार पर छियालीस फीसद बढ़ीं, जबकि आलू के दाम में इक्यावन फीसद का इजाफा हुआ। इसी तरह, टमाटर के भाव उनतीस रुपए प्रति किलोग्राम से आगे बढ़ते हुए एक वर्ष पहले की समान अवधि के मुकाबले चौंसठ रुपए प्रति किलोग्राम हो गए। टमाटर सौ रुपए प्रतिकिलो या इससे ज्यादा भाव पर भी बिका। अन्य कई हरी सब्जियां भी आमतौर पर अस्सी या सौ रुपए प्रति किलो बिक रही हैं। भोजन की थाली में सब्जियां एक तरह का संतुलन बनाती हैं। अब इनके लगातार महंगे बने रहने का असर दालों की कीमतों पर भी पड़ा है। सच यह है कि महंगाई एक दुश्चक्र की तरह लोगों के लिए एक गंभीर समस्या बनती जा रही है और एक समय तात्कालिक कारणों से बाजार में उतार-चढ़ाव के तौर पर देखी जाने वाली स्थितियां अब आम रहने लगी हैं।

एक समय कई बार लोग कुछ समय तक समझौता करके महंगाई की चुनौतियों का सामना कर लेते थे। लेकिन अब महंगाई में निरंतरता की वजह से संतुलित भोजन पहुंच से बाहर हो रहा है। एक ओर, रिजर्व बैंक महंगाई को काबू में रखने के लिए कुछ कदम उठाता रहता है, तो दूसरी ओर सरकार आए दिन लोगों को भरोसा देती रहती है। हकीकत यह है कि पिछले कुछ वर्षों से रोजी-रोजगार की फिक्र में लोग यह भी भूलते जा रहे हैं कि उनकी थाली में न्यूनतम चीजें क्या-क्या होनी चाहिए। ज्यादातर लोगों की आय में कमी होने या काम-धंधे में मंदी की स्थिति कायम रहने की वजह से उनकी क्रयशक्ति लगातार सिकुड़ती गई है। कई मामलों में सामान की खरीदारी में कटौती की आंच अब थाली तक भी पहुंच चुकी है। यह एक दुखद स्थिति है कि आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर कदम बढ़ाने का दावा करने के क्रम में इस पक्ष की अनदेखी की जा रही है कि लोग जीने के लिए जो भोजन कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें कितना सोचना पड़ रहा है। हालत यह है कि निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के लिए भी खाने-पीने के सामान की कीमतें पहुंच से बाहर हो रही हैं। ऐसे में देश की गरीब आबादी के सामने किस तरह की चुनौतियां खड़ी हैं, यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है।

मैली यमुना

दिल्ली की जीवनरेखा यमुना निरंतर मलिन हो रही है। राजधानी में बाईस किलोमीटर तक फैली इस नदी में प्रतिदिन छोटे-बड़े नालों का दूषित जल शोधित हुए बिना मिल जाता है। यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली सरकार गुजरे कई वर्षों में कई हजार करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। फिर भी यह मलिन दिखती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? सच्चाई यह है कि नदी को निर्मल करने के लिए कभी भी चरणबद्ध योजना बना कर काम नहीं किया गया। नतीजा यह कि यमुना में कभी अमोनिया का स्तर बढ़ जाता है, तो कभी सफेद झाग तैरने लगते हैं। इसे कम करने के तमाम उपाय असफल रहे। इस बार भी ऐसा ही हुआ। दरअसल, इसकी सबसे बड़ी वजह नालों में बिना शोधित डाला गया रसायन और दूषित पानी है। यमुना जब दिल्ली में प्रवेश करती है, तो यह उतनी प्रदूषित नहीं होती, लेकिन जैसे-जैसे वह आगे बढ़ती है, वह मैली होती जाती है। इस बार तो स्थिति इतनी भयावह हो गई कि छठ पर श्रद्धालुओं को पूजा की अनुमति देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया। अदालत को यहां तक कहना पड़ा कि श्रद्धालु इस समय डुबकी लगाएंगे तो वे बीमार हो सकते हैं।

उच्च न्यायालय की चिंता जायज है। यह समस्या कोई नई नहीं है। बावजूद इसके सरकार ने विभिन्न घाटों पर छठ व्रतियों के लिए तैयारी नहीं की। सभी जानते हैं कि यमुना एक-दो दिन में साफ नहीं हो सकती। मगर सवाल यह है कि सरकार ने पहले से ही इस दिशा में तैयारी क्यों नहीं की। हर वर्ष छठ से पहले यमुना में सफेद झाग की चादर फैल जाती है। कई बार इस तरह की तस्वीरें डरातीं और चिंता पैदा करती हैं, पर नदी की निर्मलता लौटाने का जिम्मा संभाले अधिकारी आंखें मूंदे रहते हैं। वर्ष 1993 में लाई गई यमुना कार्ययोजना का हासिल सबके सामने है। इस योजना मद में आबंटित की गई राशि से यमुना की सफाई कहां तक पहुंची, यह एक जगजाहिर हकीकत है। हर बार यह कह कर पल्ला झाड़ लिया जाता है कि अगले साल यह स्वच्छ हो जाएगी। अगर यमुना अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है, तो इस पर सभी को सोचना होगा कि इसके लिए किसकी जवाबदेही है और इसका भुक्तभोगी कौन!

बेलगाम फैलती मानव अंग तस्करी

कुछ वर्षों से देश में मानव अंगों की तस्करी सबसे मुनाफा देने वाले व्यवसाय का रूप ले रही है। इसका संजाल पूरे देश और विदेश में फैले होने की वजह से इसको खत्म करना किसी चुनौती से कम नहीं।

अखिलेश आर्येंदु

पिछले कुछ वर्षों में तस्करी का काला धंधा बहुत तेजी से बढ़ा है। इनमें घृणित और भयावह मानव अंग तस्करी की चर्चा सबसे ज्यादा हुई है। गौरतलब है कि देश में फूल-फल रहे काले धंधों में मानव अंग तस्करी भी एक है। कड़े कानून होने के बावजूद मानव अंग तस्करी को रोका नहीं जा सका है या यों कहें, रोकना असंभव जैसा हो गया है। यह धंधा अमूमन डाक्टरों, नर्स, दलालों, पुलिस और तस्कर गिरोहों की मिलीभगत से होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसे रोक पाना संभव होगा? सामाजिक मसले पर काम करने वाले विचारकों का मानना है कि मानव अंग तस्करी रोकने के लिए मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए।

कुछ वर्षों से देश में मानव अंगों की तस्करी सबसे मुनाफा देने वाला व्यवसाय का रूप ले रही है, इसका संजाल पूरे देश और विदेश में फैले होने की वजह से इसको खत्म करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। आए दिन राज्यों की पुलिस की अपराध शाखाएं अंतरराष्ट्रीय गिरोहों का भंडाफोड़ करती रहती हैं। देश में चोरी-छिपे, विश्वासघात कर और मजबूरी का फायदा उठा कर रोजाना पता नहीं कितनी घटनाएं होती हैं, जो पुलिस रेकार्ड में नहीं होतीं। ऐसी घटनाओं को रोकना शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। जानकारों के अनुसार भारत में मानव अंगों की तस्करी पिछले तीस वर्षों में ज्यादा तेजी से बढ़ी है।

सवाल है कि कड़े कानून के बावजूद क्या मानव अंगों की तस्करी की जा सकती है? अमेरिका की सरकारी 'कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस' के अनुसार, मानव अंगों की तस्करी, आमतौर पर ऐसी आपराधिक गतिविधियों को कहते हैं, जिनमें अवैध तरीके से किसी जिंदा या मृत व्यक्ति से अंग निकाल लिए जाते हैं और फिर उसकी अवैध बिक्री और प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। पिछली तमाम जहालत भरी घटनाओं पर गौर करें, तो मानव अंग को पाने के लिए किसी को बंदी बनाना या जबर्दस्ती उसके अंग निकाल लेना भी मानव अंग तस्करी के दायरे में आता है। अंतरराष्ट्रीय जानकारों के मुताबिक कानूनी दायरे से जब मानव अंगों की मांग पूरी नहीं होती, तब मानव अंगों की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, जिसमें आपराधिक तत्त्व भी शामिल हो जाते हैं।

आर्थिक रूप से कमजोर देशों में मानव अंगों की तस्करी करना विकसित देशों की अपेक्षा ज्यादा आसान है। इसकी वजह जागरूकता की कमी है। विकासशील देशों में जागरूकता की कमी तो है ही, गरीबी की वजह से धन के लालच में आकर गरीब लोग अंग तस्करों के झांसे में फंस जाते हैं। दूसरी बड़ी वजह, कई बार आइसीयू में भर्ती व्यक्ति के पास उसका कोई अपना नहीं होता है, ऐसे नाजुक हालत में भी बेईमान शल्य चिकित्सक यकृत, गुर्दे या कोई अंग चुपचाप निकाल कर बेच दें, तो पता नहीं चलता है। इसलिए हर स्तर पर जागरूकता बहुत जरूरी है।

मानव अंगों की तस्करी आमतौर पर भ्रष्ट अधिकारियों और आपराधिक समूहों की सांठगांठ से होती है। बिचौलियों की भूमिका इसमें खास होती है। मजबूर लोगों को लालच देकर या बीमार व्यक्ति के

इलाज के नाम पर शरीर के उस अंग को निकाल लिया जाता है, जिसके निकालने के तत्काल बाद मौत नहीं होती। इसके बाद बिचौलियों का खेल चलता है, जो एक अंग का बीस लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक की मांग करते हैं। भारत और पड़ोसी देशों में मानव अंगों की तस्करी

> **आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में आतंक या युद्ध के हालात रहे, वहां मानव तस्करी बड़े पैमाने पर हुई। आतंकवादी गिरोहों, अंतरराष्ट्रीय तस्करों और नए गिरोहों के जरिए भी मानव तस्करी तेजी से बढ़ी, खासकर 2005 से लेकर 2015 तक। आज भी ये गिरोह सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर मानव अंगों की तस्करी कर धन की उगाही करने में लगे हैं। दरअसल, मानव अंगों की तस्करी उन देशों में ज्यादा फूल-फल रही है जहां गरीबी बहुत है। इस मामले में पुलिस, डाक्टर, अधिकारी और दलालों का गठजोड़ आसानी से हो जाता है।**

वर्षों से चल रही है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे विकासशील देशों में मानव तस्करी का धंधा बड़े पैमाने पर चलता है। ये गिरोह हर महीने करोड़ों का वारा-न्यारा करते हैं।

ऐसे लोग कभी-कभार ही पुलिस की गिरफ्त में आते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में इन्हें लंबी सजा नहीं होती। जाहिर है, भारत सहित दुनिया के तमाम विकसित और विकासशील देशों में गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपित किए जाते हैं जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की जान चली जाती है। इंसान के जरिए किए जाने वाले काले धंधे में यह सबसे काला धंधा कहा जा सकता है, क्योंकि यह इंसान की मजबूरी, विश्वासघात, ठगी और धन के लालच में चोरी-छिपे चलाया जाता है। इस पर जब तक नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक इससे ताल्लुक रखने वाले धंधेबाजों में डर पैदा नहीं होगा।

अंग प्रत्यारोपण विशेषज्ञों का कहना है कि अंगदान की सत्यता की जांच करने वाली समिति अगर सही तरीके से जांच करे, तो धंधेबाजों के गैर-कानूनी दस्तावेजों को पकड़ा जा सकता है। अच्छी तरह 'एचएनए टाइपिंग' की जांच करने से गैर-कानूनी कागज को बाहर किया जा सकता है। मतलब साफ है, अगर जांच करने वाले अधिकारी और डाक्टर चाहें, तो मानव अंगों की तस्करी के धंधे को रोका जा सकता है। अमेरिका की 'क्रांग्रेसनल रिसर्च' रपट के मुताबिक चीन में अल्पसंख्यकों के अंगों की तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं। विवादित जगह विस्थापित हुए लोगों के बीच ये घटनाएं ज्यादा तेज हुई हैं। रपट बताती है कि वहां जातीय अल्पसंख्यकों को उनके अंगों की तस्करी के लिए मारा गया। भारत में मानव तस्करी के खिलाफ सख्त नियम बनाए गए हैं। बावजूद इसके, बड़े पैमाने पर चोरी-छिपे मानव अंगों की तस्करी होती है।

आंकड़े बताते हैं कि जिन देशों में आतंक या युद्ध के हालात रहे, वहां मानव तस्करी बड़े पैमाने पर हुई। आतंकवादी गिरोहों, अंतरराष्ट्रीय तस्करों और नए गिरोहों के जरिए भी मानव तस्करी तेजी से बढ़ी, खासकर 2005 से लेकर 2015 तक। आज भी ये गिरोह सक्रिय हैं और बड़े पैमाने पर मानव अंगों की तस्करी कर धन की उगाही करने में लगे हैं। दरअसल, मानव अंगों की तस्करी उन देशों में ज्यादा फूल-फल रही है जहां गरीबी बहुत है। इस मामले में पुलिस, डाक्टर, अधिकारी और दलालों का गठजोड़ आसानी से हो जाया करता है। मानवीय संवेदनाएं टूट रही हैं और धन बटोरने के फेर में लोगों को सभी तरह की विश्वसनीयता का गला घोंटने में कोई डर नहीं लगता। यानी कानून और समाज का डर खत्म होता जा रहा है। आंकड़े के मुताबिक पिछले बीस वर्षों में विकसित और विकासशील देशों में मानव तस्करी तेजी से बढ़ी है, विकसित देशों में भी बढ़ी है, लेकिन उतनी नहीं, जितनी विकासशील देशों में।

मानव अंग तस्करी का बाजार अरबों रुपए का है। सोशल मीडिया पर यह भी दावा किया जा रहा है कि हर वर्ष मानव अंग तस्करी के कम से कम दो हजार मामले चुपचाप चलते रहते हैं। गैर-सरकारी संगठन 'ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी' के आकलन के मुताबिक दुनिया में मानव तस्करी का बाजार 84 करोड़ डालर से 1.7 अरब डालर तक का है। जीएफआइ के मुताबिक हर साल दुनिया में बारह हजार से ज्यादा मानव अंगों का गैर-कानूनी प्रत्यारोपण होता है और इनमें से आठ हजार गुर्दे का होता है। इसके बाद हृदय, फेफड़े, यकृत, और आग्नाशय जैसे अति महत्त्वपूर्ण अंगों का गैरकानूनी ढंग से प्रत्यारोपण होता है।

अंतिम अरण्य में

रमेश चंद मीणा

परिवार तभी मुकम्मल माना जाता रहा है, जब उस परिवार का कोई एक अदद मुखिया उसे संचालित करता है। क्या आज परिवार के मुखिया के साथ ऐसा हो पा रहा है? यह सवाल आज एक तरह से सबसे उपेक्षित सवालों में से एक है। दरअसल, समाज का आम रवैया जैसा होता है, उसमें वृद्धों की दुनिया ही अलग होती है। बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि क्या वृद्धों को दूसरी दुनिया बना लेनी चाहिए! सच यह है कि वृद्धों की अपनी अलग दुनिया होती नहीं है, बल्कि उन्हें शेष जीवन का वक्त किसी तरह से काटना पड़ता है। उनकी दुनिया अपनों से अलग हो जाती है। युवा बढ़ता खून और वृद्ध सूखता, घटता और निचुड़ता खून है। युवा अपनी युवावस्था में बहुत-सी बातों पर गौर नहीं करते, इसलिए अपने बुजुर्गों की मान-मर्यादा नजरअंदाज कर दी जाती है। एक दिन जब शक्ति उनके हाथों से निकल चुकी होती है, तब उन्हें अपने ही घर में कहीं एक कोना भी मिल पाना मुश्किल हो जाता है। कई बार उन्हें वृद्धाश्रम में यों छोड़ दिया जाता है, जैसे वे कोई घर का फालतू सामान हों, जिसे बाहर कर दिया जाता है। कई बुजुर्गों को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो वृद्धाश्रम में शरण ले पाते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो सड़क पर लावारिस दम तोड़ने पर मजबूर होते हैं।

भारत में आज भी वृद्धाश्रम को भारतीय संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। उदारीकरण के बाद कई बातों को जोर देकर भारतीय संस्कृति का विरोधी कहा जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग व्यवहार में वैसा ही करते हैं। इसी तर्ज पर वृद्ध समाज के हाशिये पर चले जाने पर उनकी पीड़ा को कोई समझने को तैयार नहीं होता। जिन अपने कहे जाने वाले पुत्र-पुत्रियों को उनका वारिसाना हक मिलता है, वे सब कुछ हासिल करना अपना हक समझते हैं, पर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंग चुके हैं? हम औद्योगिक युग की भाग-दौड़ में जी रहे हैं।

वृद्धों का दूसरा संसार यों तो हमेशा से रहा है, पर वर्तमान में यह संसार अधिक दुखदायी, त्रासद और कष्टमय होता जा रहा है। इस कष्ट के पीछे बेशक अपनी परंपराओं से मुंह मोड़ना, भूलना और अपने सुख के पीछे अंधे होकर दौड़ लगाना रहा है। हम सभी जिंदगी भर घर का भार ढोने वाला मुखिया बनकर जीते हैं और बुढ़ापे में घर की चौखट से बाहर कर दिए जाते हैं। आज वैसे बुजुर्ग दिख जाएंगे, जो 'अंतिम अरण्य' में दिन काट रहे हैं या फिर कहीं किसी पुलिया पर समय काटने पर मजबूर हैं। कई घरों की बैठक में सबका हिस्सा होता है, पर वृद्ध घर के एक कोने में सिकुड़कर रहने पर मजबूर हैं या फिर उन्हें वृद्धाश्रम का रास्ता बता दिया जा रहा है। जो बुजुर्ग घर में बराबर का साथ पा रहे हैं, वे बड़े सौभाग्यशाली हैं और थोड़ा अच्छा वक्त बिताते हुए अच्छे से जी लेते हैं। यानी ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने घर की बुनियाद रखने वालों की कद्र करते हैं, उनका खयाल रखते हैं।

मगर नई पीढ़ी के ज्यादातर युवा क्यों रंग बदले रहे हैं? क्या इनका बदलना जरूरी है? चिंता इस बात की है कि अगर ये यों ही बदलते रहे तो भारतीयता का क्या होगा? वृद्धों का क्या होगा? उपभोक्तावाद,, बाजारवाद और उदारवाद में यह सब होना स्वाभाविक माना जाता है। भारत की पुरानी पीढ़ी यह सब देखकर भौचक है तो नई पीढ़ी जश्न के मूड में हैं। इसलिए फिलहाल वह इस विषय पर किसी तरह की चिंता करने की स्थिति में नहीं है। चिंता कर रहे हैं समाजशास्त्री, विद्वान लेखक और चिंतक कि क्या किया जाए, जिससे अंतिम समय में बुजुर्ग अपने परिवार में थोड़ा सुकून से रह कर गुजार सकें।

दुनिया मेरे आगे

> **वृद्धों का दूसरा संसार यों तो हमेशा से रहा है, पर वर्तमान में यह संसार अधिक दुखदायी, त्रासद और कष्टमय होता जा रहा है। इस कष्ट के पीछे बेशक अपनी परंपराओं से मुंह मोड़ना, भूलना और अपने सुख के पीछे अंधे होकर दौड़ लगाना रहा है। हम सभी जिंदगी भर घर का भार ढोने वाला मुखिया बनकर जीते हैं और बुढ़ापे में घर की चौखट से बाहर कर दिया जाता है।**

वृद्धावस्था के अपने कड़वे सच है। इसे जीने के लिए वृद्ध व्यक्ति को स्वयं ही भोगना होता है। अवस्था के अनुसार व्यवहार करना होता है। समय के बदलने के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। दूसरों से अपेक्षा जितनी कम रखी जाए, उतनी ही सही है। जीवन सुख-दुख का गुलदस्ता है। सुख-दुख आते-जाते रहते हैं। ये जीवन के ऐसे पहलू हैं, जिन्हें कहना आसान है, जीवन में उतारना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन दर्शन को समझ लेने वाले बुढ़ापे में निराश, हताश नहीं होते। बेटे-बेटियों से अत्यधिक अपेक्षा करने वाले भावुक बुजुर्ग अक्सर दुखी रहते हैं।

भारतीय दर्शन का एक शब्द है- 'वीतराग'। इस शब्द को जीवन में उतारे बिना वृद्ध व्यक्ति आधा-अधूरा ही रहेगा। पहली से दूसरी दुनिया में प्रवेश करते ही हर उस बात के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिसे दर्शन की भाषा में वीतरागी कहा गया है। बुद्ध उसे विपश्यना कहते हैं। संयम-संतोष रखना और इच्छाओं से परे रहना। कभी भी आ सकने वाली मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार रहना, मगर हर पल को जीते हुए। माना जाता है कि बुढ़ापे में मंदिर घूमने जाना, तीर्थ करना, संतों और आश्रम की शरण में जाना ही उचित या अंतिम माध्यम नहीं है। इन दिनों इस तरह की दुनिया पर भी विश्वास करना मुश्किल हो गया है। अपनों से अधिक मोह न करना, अपेक्षा न रखते हुए वृद्धावस्था को सुकून से गुजारा जा सकता है।

मेजबानी की पहल

सन् 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए भारत ने पहल की है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति को इस संबंध में एक आशय पत्र सौंप दिया है, जिसका परिणाम अगले वर्ष आने की उम्मीद है। यदि भारत का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो देश के कई क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। ओलंपिक के आयोजन के दौरान देश में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे होटलों, रेस्तरां और परिवहन में पर्यटक अधिक खर्च करेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। इसके अलावा, कई तरह के खेलों के आयोजन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास होगा। नए बुनियादी ढांचों का निर्माण भी किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत की पदक जीतने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी, क्योंकि प्रतिभागी अपने देश में खेलते हुए अधिक उत्साहित रहेंगे। यदि भारत को 2036 के ओलंपिक की मेजबानी मिलती है, तो योग, कबड्डी और खो-खो को भी ओलंपिक में शामिल करने का पूरा प्रयास किया जाएगा, जिससे हम अपने पारंपरिक खेलों से अन्य देशों के लोगों को परिचित करवा सकेंगे और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर ला सकेंगे। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।

- हिमांशी बोरा, जम्मू

अब स्मृतियों में

लोकगीतों और छठ गीतों को नया आयाम देने वालीं अविस्मरणीय गायिका शारदा सिन्हा हमारे बीच नहीं। वे बिहार कोकिला के रूप में मशहूर थीं। उन्होंने छठ गीतों को विशिष्ट पहचान दी। विदेश में भी उनके गीत सुने गए और खूब लोकप्रिय हुए। बिहार के सुपौल जिले में जन्मीं शारदा सिन्हा ने कुछ हिंदी फिल्मों के लिए भी सुपरहिट गीत गाए। मगर उनका जोर माटी और अपनी संस्कृति को समृद्ध करने पर ही रहा। उनका गाया छठ गीत तो मानो इस पर्व का पर्यायवाची ही बन गया। उन्होंने कभी भी फूहड़ और अश्लील गाने नहीं गाए। इनको पद्मश्री और पद्मभूषण पुरस्कार से अलंकृत किया गया। भोजपुरी के अलावा इन्होंने अन्य भाषाओं में भी सफलतापूर्वक गीत गाए। यह संयोग ही है कि छठ पूजा के लिए सुमधुर गीत गाने वाली शारदा सिन्हा का निधन भी इसी महापर्व के दौरान हुआ। उनके निधन को हम निश्चित रूप से बहुत बड़ी क्षति कह सकते हैं। उनके न रहने से लोक गायिकी में एक बड़ा शून्य पैदा हो गया है।

- अनित कुमार राय, धनबाद

अहम फैसला

किसी निजी संपत्ति के अधिग्रहण के अधिकार को सीमित करने वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्या महत्त्वपूर्ण है। 'संपत्ति के सृजन से अधिक अहमियत उसके पुनर्वितरण' को देने वाली अवधारणा गलत है। आजकल परिश्रम और बुद्धि द्वारा कोई चीज प्राप्त करने के बजाय बुद्धि का दुरुपयोग कर किसी अन्य की कोई संपत्ति प्राप्त करना आम हो गया है। इसमें फर्जीवाड़ा और अतिक्रमण जैसे गैरकानूनी तरीके और किसी दबाव समूह द्वारा किसी के परिश्रम से अर्जित संपत्ति को सरकार पर दबाव डाल कर कानूनी रूप से पुनर्वितरित करवा लेना, दोनों तरीके शामिल हैं। इस मामले में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार हर निजी संपत्ति को सार्वजनिक हित वाली घोषित कर उनका अधिग्रहण नहीं कर सकती। नौ न्यायाधीशों की पीठ ने शीर्ष अदालत का 1978 का फैसला पलट दिया जिसमें कहा गया था कि सार्वजनिक हित के लिए सरकार किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है।

- ललित दुबे, रतलाम

सियासत कब तक

सियासत करने के बजाय समाधान खोजना चाहिए। जम्मू-कश्मीर में तमाम प्रयास के बावजूद आतंकवाद की जड़ें खत्म नहीं हुई हैं। हालांकि पिछले दस वर्षों में आतंकवादी संगठनों का वित्त पोषण करने वाली संस्थाओं पर नकेल लगने, हजारों खाते बंद होने तथा अन्य पाबंदियां लगाने के बावजूद दहशतगर्द साजिश रचने में कामयाब हो रहे हैं।' आतंक और सियासत' (संपादकीय, 4 नवंबर) में सही कहा गया है कि घुसपैठियों और आतंक की समाप्ति के लिए इस मुद्दे पर सियासत नहीं हो, बल्कि समाधान के लिए सभी को एकजुट होना होगा। आतंकियों को पकड़वाने में सहयोग करना होगा। पाकिस्तान अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। समस्या से निपटने के लिए नई कारगर रणनीति बनाने में सभी दलों का सहयोग और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना होगा, तभी आतंकवाद पर काबू पाया जा सकेगा।

- बीएल शर्मा 'अकिंचन' उज्जैन

दैनिक जागरण
आंतरिक सौंदर्य ही वास्तविक सौंदर्य होता है

अनियंत्रित प्रदूषण

वायु प्रदूषण में पराली जलाने से निकलने वाले धुएं की भूमिका को देखते हुए केंद्र सरकार ने उसे जलाने पर दोगुना जुर्माना लगाने का जो आदेश जारी किया, वह तब कोई असर करेगा, जब राज्य सरकारें पराली जलाने से रोकने के लिए कमर कसेंगी। अभी तक राज्य सरकारें इस मोर्चे पर बहुत सफल नहीं हो सकी हैं और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल के दिनों में उन्हें कई बार फटकार लगाई है। निःसंदेह पराली को जलाने से रोका ही जाना चाहिए और इसलिए और भी, क्योंकि अब वह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ देश के अन्य हिस्सों में भी जलाई जाने लगी है, लेकिन इसी के साथ यह भी समझा जाना चाहिए कि वायु प्रदूषण का एकमात्र कारण पराली जलाया जाना नहीं है। वायु प्रदूषण में वाहनों के उत्सर्जन की भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन इसके लिए किसी भी सरकार की ओर से कोई ठोस प्रयत्न नहीं किए जा रहे हैं कि वाहनों के उत्सर्जन पर लगाम लगे। वाहनों के उत्सर्जन का एक बड़ा कारण है यातायात का सुगम न होना। छोटे-बड़े शहरों में यातायात जाम के कारण वाहन रेंग-रेंग कर चलते हैं। जब ऐसा होता है तो वाहनों से कहीं अधिक विषाक्त उत्सर्जन होता है। शहरों में ऐसे स्थान बढ़ते जा रहे हैं, जहां सड़कों पर अतिक्रमण और अव्यवस्थित यातायात के कारण वाहन बहुत ही धीमी गति से चलने को बाध्य होते हैं। अब तो स्थिति यह है कि शहरी इलाकों से गुजरने वाले राजमार्गों पर भी यातायात बुरी तरह बाधित होता रहता है। इससे सरकारें और उनकी एजेंसियां अनजान नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सुगम यातायात किसी के एजेंडे में ही नहीं।

एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण स्थानीय कारणों से भी बढ़ता है और इसमें एक बड़ा कारण वाहनों का उत्सर्जन है। आखिर वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर कब ध्यान दिया जाएगा? देश में ऐसे शहरों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिनकी गिनती दुनिया के प्रदूषित शहरों में होने लगी है। यदि सरकारें और उनकी एजेंसियां प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति से वास्तव में चिंतित हैं तो फिर उन्हें उन सभी कारणों का निवारण एक साथ करना चाहिए, जिनसे वायुमंडल जहरीला होता है। उन्हें पराली जलाने से रोकने और वाहनों के उत्सर्जन पर लगाम लगाने के ठोस उपाय करने के साथ ही इस पर भी ध्यान देना होगा कि सड़कों और निर्माण स्थलों से धूल न उड़ने पाए। अभी तो इसकी कोई परवाह ही नहीं की जा रही है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कूड़ा-करकट जलाने से रोकने के उपाय केवल कागजों तक सीमित रहते हैं। चूंकि लोगों को किसी तरह की कार्रवाई का कोई भय नहीं होता, इसलिए वे भी प्रदूषण रोधी उपायों का पालन नहीं करते। यह स्थिति तब है, जब हर कोई इससे परिचित है कि वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद घातक सिद्ध हो रहा है।

छठ पर्यटन से समृद्धि

पर्यटन के विकास पर बिहार सरकार गंभीरता से काम कर रही है। पर्यटन स्थलों का विकास करने के साथ वहां सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। इसका प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है। बिहार ही नहीं पूरे देश में उत्साह के साथ मनाए जाने वाले लोक आस्था के महापर्व छठ को पर्यटन का रूप देने का काम बहुत ही बढ़िया है। वैश्विक रूप ले चुके इस महापर्व को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने की जरूरत को सरकार ने महसूस करके पिछले दिनों जो घोषणा की थी, वह किस तरह से साकार ले रही इसे देखना होगा। देश-विदेश के पर्यटकों के लिए पर्यटन विभाग ने पहली बार छठ टूर पैकेज लांच किया था। नहाय खाय से लेकर पारण तक यानी छठ के चारों दिन की परंपरा, संस्कृति एवं खानपान से पर्यटक रूबरू हो सकें, इसके लिए छठ को पर्यटन उत्सव का रूप दिया गया है। इस पैकेज में पटना में होटल, भोजन, टूर गाइड, पूजा करने वाले परिवारों से मिलाने सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं। इसके साथ पर्यटकों को पटना के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराना भी शामिल है। छठ पर्यटन की इस योजना से क्या हासिल हुआ, पर्यटकों का किस तरह का अनुभव रहा और क्या कमी दिखी सहित अन्य पैडबैक पर हम काम कर अगली बार उसमें सुधार कर सकते हैं। फिर इसका विस्तार पूरे राज्य में किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन से रोजगार सृजन करने और आर्थिक समृद्धि हासिल करने में कई राज्य बढ़िया काम कर रहे हैं। इससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलता है। आने वाले वर्षों में छठ महापर्व से कुछ इसी तरह की उम्मीद है। इसके लिए जिम्मेदारों को केवल ईमानदारी से काम करना होगा। पर्यटकों के लिए अच्छी व्यवस्था करनी होगी।

छठ को पर्यटन उत्सव का रूप देने से आने वाले वर्षों में यह आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार का बड़ा माध्यम बनेगा

बेनकाब किया जाए कनाडा का दोहरा चरित्र

विवेक काटजू

कनाडा के भारत विरोधी रवैये पर केवल कड़ी बयानबाजी ही कारगर नहीं। उसके खिलाफ कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे

आवेश रावल

बीते दिनों कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने एक हिंदू मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला बोल दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़े शब्दों में इस घटना की निंदा की। इस घटना के पीड़ितों की सहायता के लिए कांउसलर स्टाफ के काम में बाधा डालने के प्रयासों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर उचित ही जोर दिया कि राजनयिकों और कांउसलर स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित करना कनाडा की जिम्मेदारी है। इससे पूर्व भी खालिस्तान समर्थकों की करतूतों को लेकर भारत ने बार-बार कनाडा को आगाह किया। वहीं, कनाडा अभिव्यक्ति के अधिकार की आड़ में ऐसे मामलों से अपना पल्ला झाड़ता रहा है। वैसे तो ब्रैम्पटन हिंसा की कनाडाई प्रधानमंत्री और अन्य नेताओं ने निंदा की है, मगर यह खानापूर्ति और औपचारिकता अधिक है, क्योंकि खालिस्तान समर्थकों पर कोई कड़ी कार्रवाई होने के दूर-दूर तक आसार नहीं दिखते।

भारत-कनाडा संबंध फिलहाल बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं और दोनों देशों के बीच रह-रहकर टकराव के नए मोर्चे खुलते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले कनाडा के उप विदेश मंत्री डेविड मौरिसन ने कनाडा में लोगों को निशाना बनाने के पीछे भारतीय एजेंटों और गृहमंत्री अमित शाह का नाम लेकर सनसनी मचा दी। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इन आरोपों को बेतुका और आधारहीन बताया। भारत के एक वरिष्ठतम मंत्री के प्रति कनाडा के ऐसे अप्रत्यक्षित आरोप देश की प्रतिष्ठा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। ऐसे में मौदी सरकार का यह रवैया बिल्कुल सही है कि वह न केवल अमित शाह से जुड़े आरोपों, बल्कि अन्य पहलुओं को लेकर भी कनाडा को करारा जवाब देने में लगी है। इसमें केवल कड़ी बयानबाजी ही कारगर नहीं होगी, बल्कि कनाडा के खिलाफ कुछ कड़े कदम भी उठाने होंगे। भले ही इससे भारतवंशियों की कुछ मुश्किलों का सामना करने के साथ-साथ व्यापार एवं वाणिज्य के मोर्चे पर भी देश को कुछ कीमत ही क्यों न चुकानी पड़े। सदियों से भारत में यही परंपरा चली आई है कि सम्मान की रक्षा सर्वोपरि है।

जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद दोनों देशों के संबंधों ने एक नई करवट ली है। कनाडा का दावा है कि इस हत्याकांड से जुड़ी जांच और अन्य जानकारियों के सिलसिले में अगस्त 2023 से 12 अक्टूबर, 2024 के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिल्ली समेत दुनिया के दूसरे कोनों में छह बार मिल चुके हैं। कनाडा ने यहां तक अतिरेकपूर्ण दावे किए कि भारतीय राजनयिकों ने कनाडा के उन नागरिकों की जानकारी भेजी, जिन्हें वे भारत विरोधी मानते हैं। इसी संदर्भ में गृह मंत्री का उल्लेख करते हुए उसने कहा कि उक्त जानकारी का उपयोग अपराधियों के माध्यम से कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया। इसी सिलसिले में भारतीय राजनयिकों से पूछताछ के लिए कनाडा ने उनको मिले विशेषाधिकार वापस लेने की बात कही, जिससे बात इतनी बिगड़ गई कि भारत ने 14 अक्टूबर को भारतीय उच्चायुक्त संजय वर्मा सहित छह राजनयिकों को कनाडा से वापस बुलाने का फैसला किया। इन राजनयिकों को 'पर्सस आफ इंट्रेस्ट' बताने के पीछे कनाडा का यही मंतव्य था कि उनकी अपराध में सहभागिता या जानकारियां साझा करने में संदिग्ध भूमिका हो सकती है। यह ऐसी उकसावे वाली बात थी कि भारत ने छह कनाडाई राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दे दिया।

कनाडा का दावा है कि उसने निज्जर हत्याकांड से लेकर राजनयिकों की संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े साक्ष्य भारत को उपलब्ध कराए हैं। वहीं, भारत इससे इन्कार करता आया है। निज्जर हत्याकांड में कनाडा ने चार भारतीय नागरिकों की हिरासत में लिया है, लेकिन उसे अदालतों में उनके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे। भारतीय पक्ष को जो जानकारियां मिली हैं, वे समय आने पर सार्वजनिक हो सकती हैं। इस पर भारतीय अधिकारियों को विचार करना चाहिए। इससे कनाडाई आरोपों की हवा निकालने में मदद मिलेगी।

ब्रैम्पटन हिंसा के बाद इस मामले में कनाडा की पोल खोली ही जानी चाहिए। चूंकि कनाडा ने पूरी तरह भारत विरोधी रवैया अख्तियार कर लिया है तो वह अपने संगी-साथियों द्वारा भारत को अवहेल करने वाला बिमर्श तैयार करने में जुटा है। इसमें वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबार उसके मददगार बन रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कूटनीति का तकाजा यही कहता है कि भारत अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करे और पूरी दुनिया विशेषकर ग्लोबल साउथ के उन देशों के समक्ष यह दर्शाए कि वह एक जिम्मेदार देश है और उसके प्रति कनाडा के आरोप पूरी तरह झूठे एवं भ्रामक हैं। ब्रैम्पटन हिंस कनाडा के दोहरे चरित्र को उजागर करने का उदाहरण बननी चाहिए। हालांकि इस मामले में कनाडा को मिलने वाले उन आइ-5 देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा) के रुख को लेकर सतर्क रहना होगा, जो आपस में खुफिया जानकारियां साझा करने के साथ एक-दूसरे की ढाल बनते हैं। अमेरिका में भले ही सत्ता परिवर्तन हो गया हो, लेकिन इस मामले में उसके नजरिये में मामूली सा फर्क देखने को मिलेगा।

कई मुद्दों पर कनाडा का रवैया पाखंड से भरा हुआ है। जैसे 1985 के कनिष्क विमान हादसे को लेकर उसका दृष्टिकोण नस्लीय रहा। यह भी देखा जाए कि कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में दूसरे देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं संप्रभुता के लिए चुनौती पैदा करने की गुंजाइश नहीं दी जा सकती। भारत को इन सभी पहलुओं को एक कूटनीतिक अभियान के जरिये वैश्विक समुदाय के सामने रखना चाहिए। भारत कनाडा के आरोपों से उपजी कूटनीतिक चुनौतियों को अनदेखा नहीं कर सकता और ब्रैम्पटन हिंस के बाद भी टूडो का भारत के प्रति नजरिया नहीं बदलने वाला। भारत को कांरेबाई दिशा में बढ़ना चाहिए। भले ही ब्रैम्पटन हिंसा को कनाडा की सभी पार्टियों ने एक सुर में निंदा की हो, लेकिन टूडो के आरोप सभी दलों को एकजुट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जरिये वह यही साबित करने में जुटे हैं कि कनाडाई नागरिकों के सामने अपने ही देश में दबी हुई की कथित गतिविधियों से खतरा पैदा हो गया है।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)
response@jagran.com

मदरसा शिक्षा में सुधार की राह खुली

डा. हरवंश दीक्षित

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कई भ्रम दूर करने व मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाला है

लखनऊ के एक मदरसे में पढ़ाई करते छात्र। प्रेट्र

उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2004 पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम फैसलों से अलग है। ऐसा बहुत कम होता है कि अदालत के किसी निर्णय से दोनों पक्षकार संतुष्ट हों, लेकिन इस मामले में ऐसा ही देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ के निर्णय में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट, 2004 को संवैधानिक ठहराया, किंतु कामिल (स्नातक) और फाजिल (परास्नातक) डिग्री देने से संबंधित प्रविधानों को यूजीसी एक्ट 1956 के विरुद्ध होने के कारण असंवैधानिक घोषित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में यह मुकदमा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ अपील के रूप में आया था, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट, 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 22 मार्च, 2024 के अपने फैसले में कहा था कि मदरसा बोर्ड की स्थापना संविधान के पंथनिरपेक्ष ढांचे, अनुच्छेद 21(क) में उल्लिखित अधिकार और सबको समान शिक्षा पाने के मूल अधिकार का उल्लंघन है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा गया कि उच्च न्यायालय में में अल्पसंख्यकों को मिले मूल अधिकार की अनदेखी की गई है।

सर्वोच्च न्यायालय के सामने तीन प्रश्न थे। पहला यह कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और उनके संचालन के अधिकार का अर्थ और उसकी सीमा क्या है। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या यह कानून पंथनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है और तीसरा यह कि अनुच्छेद 21(क) में दिए गए शिक्षा के मूल अधिकार और अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित और प्रशासित करने के अधिकार के बीच क्या अंतर्संबंध है? उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट, 2004 के माध्यम से मदरसा बोर्ड स्थापित किया गया था। इसके अधीन मदरसों को पांचवीं (तहतानियां), आठवीं (फौकानियां), दसवीं (मुंशी-मौलवी), बारहवीं (आलिम), स्नातक (कामिल) तथा परास्नातक (फाजिल) डिग्री देने का अधिकार दिया गया था। मदरसा बोर्ड का तर्क था कि संविधान के अनुच्छेद 30(1) में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं के संचालन का अधिकार है और संविधान निर्माताओं की मंशा थी कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा और संस्कृति की संरक्षित करने का अधिकार होना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय ने टीएमए पई फाउंडेशन (2002), इस्लामिक अकादमी आफ एजुकेशन (2003) तथा पीए इनामदार (2005) जैसे कई मुकदमों में यह कहा था कि अनुच्छेद 30(1) के तहत अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने और एवं संचालन का अधिकार है, किंतु यह अधिकार असीम नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की स्पष्ट मान्यता रही है कि संस्थाओं के लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने तथा शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए नियमों को इन संस्थाओं को भी मानना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्ववर्ती निर्णयों की भांति उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट, 2004 के मामले में भी यही कहा कि अल्पसंख्यक समाज को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार अनुच्छेद 30(1) द्वारा दिया गया है। इसी के चलते उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय का वह हिस्सा निरस्त कर दिया, जिसमें मदरसा बोर्ड को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि अल्पसंख्यक समाज अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित कर सकते हैं, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सरकार या उसके द्वारा स्थापित नियामक संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियम अल्पसंख्यक संस्थाओं पर भी बाध्यकारी होंगे। यूपी मदरसा बोर्ड द्वारा दी जाने वाली डिग्री की मान्यता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शिक्षण संस्था खोलने के अधिकार और डिग्री की मान्यता को अलग-अलग देखा जाना चाहिए। अनुच्छेद 30(1) अल्पसंख्यक समाज को शिक्षण संस्थाएं खोलने का अधिकार देता है, किंतु इसके अंतर्गत संस्थाओं की डिग्री को मान्यता मिलने का अधिकार शामिल नहीं है। डिग्री की मान्यता के संबंध में न्यायालय ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली डिग्री का नियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इसके द्वारा व्यापक नियम बनाए गए हैं। चूंकि मदरसा बोर्ड विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के तहत मान्यता प्राप्त नहीं, इसलिए उसके द्वारा दी जाने वाली कामिल तथा फाजिल की डिग्री विधिसम्मत नहीं। पांचवीं, आठवीं, दसवीं तथा बारहवीं के समकक्ष जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे अवैध नहीं हैं, किंतु शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सरकार उनका भी नियमन कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मदरसा शिक्षा से जुड़े कई भ्रम दूर करेगा व मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने में मदद करेगा। मदरसा संचालित करने के अधिकार को मान्यता मिलने से अल्पसंख्यक समाज को संविधान के अनुच्छेद 30(1) में दिए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा तो की गई है, किंतु यह भी स्पष्ट किया गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को अन्य छात्रों की तरह स्तरीय शिक्षा पाने का हक है और इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार नियम बना सकेगी। स्नातक और परास्नातक डिग्री देने के अधिकार को भी स्पष्ट करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इसे यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुरूप ही चलाया जा सकता है।

(लेखक उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एवं विधिवेत्ता हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

अध्यात्म की शक्ति

भौतिकता और अध्यात्म के संतुलन वाला जीवन ही श्रेष्ठ होता है। भौतिक वस्तुओं का उपयोग एवं उनका संग्रहण जीवन को सुचारु रूप से चलाने में सहायक हो सकता है, परंतु यह जीवन को सरस नहीं बन सकता। भोग वैराग्य की ही राह में बढ़ाया गया एक कदम है। अधिकांशतः देखा जाता है कि समस्त भोगों के उपरांत भी मन में जो रीतापन रहता है वह किसी भी भौतिक साधन से भरा नहीं जा सकता। भौतिकता में डूबा हुआ व्यक्ति भी अंत में वही अनुभव करता है कि सब कुछ आजमा कर देख लिया, परंतु तृप्ति नहीं मिली। जो दूर से स्वर्ण दिख रहा था, हाथ में आते ही मिट्टी हो जाता है।

एक यूनानी कथा है राजा मिडास की। मिडास को यह वरदान प्राप्त हो गया था कि वह जिस भी वस्तु को स्पर्श करेगा वह स्वर्ण में परिवर्तित हो जाएगी। प्रारंभ में वह बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु जैसे ही उसने भोजन को छुआ वह स्वर्ण हो गया, जल को होंठ से लगाया वह भी स्वर्ण हो गया। हमारी स्थिति भी राजा मिडास की तरह ही है। भौतिक साधनों के अंबार पर बैठकर हम स्वयं को सम्राट से कम नहीं समझते, परंतु भीतर हमारा मन चोला उतार कर भिक्षुक होने के लिए तड़पने लगता है।

अध्यात्म का अर्थ धार्मिक होना का दिखावा करना, पुण्य के लोभ से दान-दक्षिणा देना, तंत्र-मंत्र में पारंगत होना नहीं है, अपितु यह ज्ञान प्राप्त कर लेना कि सभी भीग अनित्य हैं एवं इनका त्याग करके ही नित्य को पाया जा सकता है। भोग हो परंतु उसमें आसक्ति न हो, दूसरे का हिस्सा छीनने की प्रवृत्ति न हो। त्याग, सेवा भाव एवं संचय से अधिक वितरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगे तो समझना चाहिए अध्यात्म ने अपनी शरण में ले लिया है। ब्रह्म ने स्वयं को जड़ एवं चेतन दो रूपों में विभक्त करके सृष्टि को ढाला है। इसी जड़ और चेतन का सामंजस्य जीवन में बिठाकर अपने भीतर के ब्रह्म को खोजा जा सकता है।

दिर्वकल तोमर सिंह

नारी शक्ति से विकसित होगा भारत

सुप्रीता मिश्रा

विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्र सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए निरंतर समर्पित है

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपये की 'नमो ड्रोन दीदी' योजना को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 के दौरान चयनित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन मुहैया कराने का है, जो किराए पर किसानों को कृषि के लिए ड्रोन सेवाएं उपलब्ध कराएंगी। ड्रोन के माध्यम से खेतों में तरल उर्वरकों और कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीद पर 80 प्रतिशत (अधिकतम आठ लाख रुपये) तक की सब्सिडी दी जाएगी। ड्रोन उड़ाने वाली दीदियों को 15 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत अगले दो वर्षों के भीतर 14,500 ड्रोन खेतों के ऊपर उड़ान भरेंगे। इससे स्वयं सहायता समूहों को स्थायी व्यवसाय और आजीविका मिलेगी।

वस्तुतः प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2023 को महिला स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये करने के उद्देश्य से 'लखपति दीदी योजना' की शुरुआत की थी। मोदी सरकार ने महिला उत्थान पर विशेष ध्यान दिया है। महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस कड़ी में महिला किसानों को सशक्त बनाने एवं रोजगार सृजन के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से हाल ही में 'श्वेत क्रांति-2.0' की शुरुआत की गई। इससे सहकारी डेयरी समितियां अगले पांच वर्ष के भीतर प्रतिदिन एक हजार लाख किलो दूध की खरीद करने लगेंगी। महिला किसानों की मेहनत का एक-एक दाना सुरक्षित हो सके इसके लिए केंद्र सरकार ने पंचायत स्तर पर हर घंटे का मौसम अपडेट, देश भर की ग्राम पंचायतों के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवा भी शुरू की है।

किसान और मजदूर महिलाएं खेती जगत में अपना परचम लहरा रही हैं। वह खेतों में पतियों के साथ काम में हाथ बंटा रही हैं। ट्रैक्टर चलाना, खेतों में खाद और पानी देना, बीज रोपने जैसे काम वह कई बार अकेले ही कर लेती हैं। खेतों में काम करके घर की आमदनी बढ़ाने वाली ये महिलाएं पुरुष किसानों से कमतर नहीं हैं, लेकिन इस आमदनी को उनके हिस्से में नहीं जोड़ा जाता। वहीं, भारत के डेयरी क्षेत्र की असली कर्णधार महिलाएं हैं। महिला सशक्तीकरण किसे भी देश के लिए आर्थिक और सामाजिक मोर्चे पर हालात बदलने वाला साबित होता है। इसलिए हमें महिला शक्ति को पहचानना होगा कि वे भी देश का अहम हिस्सा हैं, उनकी भागीदारी भी देश के लिए बहुत जरूरी है। महिलाओं को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें सुनहरे अवसर देने होंगे, ताकि वे भी देश के विकास में अहम योगदान निभा सकें। केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के प्रयास सराहनीय हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

विश्व को प्रभावित करने वाली जीत

'डोनाल्ड ट्रंप ने रचा नया इतिहास' शीर्षक से लिखे आलेख में हर्ष जी. पंत ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत का बहुआयामी विश्लेषण करते हुए यह ठीक ही कहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ ट्रंप की वापसी शेष विश्व के साथ अमेरिका की सहभागिता में व्यापक बदलाव का संकेत है। राष्ट्रपति चुनाव में अभूतपूर्व विजय प्राप्त करने वाले ट्रंप अप्रत्याशित फैसले करने वाले बिंदास छवि के नेता माने जाते हैं। वह किसके पक्ष में कब क्या फैसला ले लें, यह समझ पाना मुश्किल होता है। बावजूद इसके इस चुनाव से यह साबित हो गया है कि अमेरिका की जनता न केवल ट्रंप पर भरोसा करती है, अपितु उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नेता भी मानती है। शायद इसीलिए तमाम अटकलों के बाद भी अमेरिकी जनता ने ट्रंप के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग करके उनकी रिपब्लिकन पार्टी को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में पूर्ण बहुमत के साथ स्थापित किया है, ताकि राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप को अमेरिका के हित में कोई कड़ा फैसला लेने में विपक्ष के अनावश्यक अवरोध का सामना न करना पड़े। जहां तक भारत का प्रश्न है तो मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने अमेरिका के साथ हमेशा मित्रवत संबंध बनाए रखे हैं। अब ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका के साथ भारत के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। ट्रंप की प्रचंड जीत यूक्रेन-रूस और हमास-इजरायल युद्ध को भी नया मोड़ दे सकती है। यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका की सहभागिता में भी बदलाव आ सकता है।

डा. वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उ.प्र.)

मेलबाक्स

बीमा कंपनियों की मनमानी पर रोक

सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु होने पर अक्सर देखा जाता है कि बीमा कंपनियां विभिन्न प्रकार के बहाने बनाती हैं। इसमें से एक मुख्य बहाना होता था कि चालक जो गाड़ी चला रहा था, उसे चलाने के लिए वह अधिकृत नहीं था। अधिकांश मामलों में बीमा कंपनी इस बहाने से भुगतान करने से इन्कार कर देती थीं, पर अब इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने फैसला सुनाया है कि हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) लाइसेंस रखने वाले 7.5 टन भार तक के परिवहन वाहन चला सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले से बीमा कंपनी को बड़ा झटका लगा है। अब वे कानूनी एवं तकनीकी दलीलें देकर दावा खारिज नहीं कर पाएंगी। संविधान पीठ ने इस मामले में पूर्व में तीन जजों द्वारा दी गई व्यवस्था पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सभी कारें, वैन, हल्के ट्रक एवं माइक्रो ट्रक हल्के वाहन की श्रेणी में आ जाएंगी। जिससे एलएमवी लाइसेंसधारक इन गाड़ियों को चलाने के लिए योग्य हो गए हैं, चाहे वह निजी हों या व्यवसायिक। भारत में 2023 में 1.7 लाख लोग सड़क दुर्घटना में काल का शिकार हुए थे। यह मानना गलत होगा कि यह सभी दुर्घटनाएं एलएमवी लाइसेंस धारकों द्वारा परिवहन वाहन चलाने के कारण हुई हैं।

धर्मेंद्र नाथ रस्तोगी, गाजियाबाद

डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता

अमेरिका में राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप की जिस प्रकार से वापसी हुई है, वह अमेरिकी नागरिकों के अपने लोकप्रिय नेता के प्रति प्यार, आशीर्वाद और विश्वास को भी दर्शाता है। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस प्रकार से बेखौफ और निर्भीकता का परिचय देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बयान दिया, उससे अमेरिका के सात स्विंग राज्यों में अमेरिकी भारतीय नागरिकों का पुरजोर समर्थन मिला। एक्स और टेस्ला के मालिक, विश्व प्रसिद्ध उद्योगपति एलन मस्क ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के लिए तन, मन, धन से जीतोड़ मेहनत की, जो निश्चित ही डोनाल्ड ट्रंप की विजय में ट्रंपकार्ड साबित हुए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका का विकास और देश सर्वोपरि श्रेणी में आते हैं। वहीं, भारत के पीएम नरेन्द्र मोदी का भी सर्वोच्च नारा 'नेशन फर्स्ट' का ही है। ट्रंप व मोदी की प्रगाढ़ दोस्ती के चर्चे विश्वविख्यात हैं।

दीपक गौतम, सोनीपत, हरियाणा

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण साइज अधिकतम 8 आइ.एस.ओ. मेजरने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

200 से अधिक विश्वविद्यालयों (भारत के अलावा अन्य देशों) में हिंदी पढ़ाई जाती है, जबकि 150 से अधिक देशों में हिंदी बोली जाती है। गूगल के अनुसार, भारत में अंग्रेजी भाषा में कंटेंट के उपयोग की गति 19 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि हिंदी में यह 94 प्रतिशत है।

आजकल

भारतीय भाषाओं की समृद्धि को नई दिशा

कैलाश विश्नोई
उच्च शिक्षा मामलों के जानकार

भारत के विकास और सांस्कृतिक एकता के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं को सशक्त करना आवश्यक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते दिनों नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में हिंदी को वैश्विक स्तर पर सबसे समृद्ध भाषा बनाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश तैयार किया जा रहा है और अगले पांच वर्षों में यह विश्व का सबसे बड़ा शब्दकोश होगा। यह योजना एक दूरदर्शी कदम है। इस पहल से हिंदी भाषी समुदाय और हिंदी सीखने वालों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा

वैश्विक बनती हिंदी भाषा : दक्षिण कोरिया के बुसान विश्वविद्यालय में भी हिंदी भाषा की पढ़ाई होती है। फाइल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हिंदी और भारतीय भाषाओं का विकास एक लंबा सफर तय कर रहा है। राजभाषा सम्मेलन, अनुवाद कार्यों में तकनीकी प्रयोग और शास्त्रीय भाषाओं को सम्मान देने जैसे कदमों ने न केवल भाषाओं को संरक्षित किया है, बल्कि उन्हें विश्व मंच पर पहचान भी दिलाई है। इन पहलों के माध्यम से देशभर के हिंदी भारतीय भाषाओं के महत्व को समझने लगे हैं, जिससे भारत की भाषाई धरोहर को संरक्षण और संवर्धन प्राप्त हो रहा है। सरकार द्वारा तकनीक के प्रयोग से भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना एक और क्रांतिकारी कदम है। यह अनुभाग अनुवाद के कार्यों को सुगम बनाएगा और एक ऐसी व्यवस्था को जन्म देगा, जिससे भारतीय भाषाओं में संवाद बढ़ेगा। यह न केवल हिंदी, बल्कि अन्य भाषाओं के लिए भी उपयोगी साबित होगा और विविध भाषाओं में संवाद को बढ़ावा देगा।

सरकारी प्रयास : देश के विभिन्न हिस्सों में राजभाषा सम्मेलन आयोजित करने की पहल से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के महत्व को समझने एवं स्वीकारने में मदद मिलेगी। ऐसे सम्मेलन भाषाई जागरूकता बढ़ाने के साथ ही भाषा को समृद्धने और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा का मंच प्रदान करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पांच भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है, जिससे भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया है, जहां कुल 11 भाषाओं को यह दर्जा प्राप्त है। यह कदम भारतीय भाषाओं की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपन्नता को प्रदर्शित करता है।

डिजिटल माध्यम और तकनीकी प्रगति के साथ हिंदी का उपयोग व्यापक रूप से बढ़ रहा है। सरकार की इस दिशा में पहल ने हिंदी को डिजिटल स्पेस में मजबूती से स्थापित किया है, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं की इंटरनेट पर अधिक सामर्थ्य उपलब्ध हो रही है। उदाहरण के लिए, सरकारी वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लिकेशन अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, शैक्षिक संस्थानों में मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इससे विभिन्न भारतीय भाषाओं को संरक्षित करने और उनकी समृद्धि को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे आने वाली पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और भाषाई विविधता से परिचित कराना सरल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद से 3500 से अधिक विद्यालयों में मातृभाषा आधारित शिक्षा का आरंभ हुआ है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या, जो 2014 में छह थी, अब बढ़कर 11 हो गई है। इससे भाषाई धरोहरों की सुरक्षा के लिए सरकार की गंभीरता का संकेत मिलता है और साथ ही इन भाषाओं में अध्ययन और शोध कार्यों को भी बढ़ावा मिल रहा है।

इसके अलावा संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओड़िया जैसे शास्त्रीय भाषाओं के प्राचीन ग्रंथों और साहित्य का पुनरुद्धार करके उन्हें पाठ्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। यह पहल भारतीय साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए आवश्यक है और वर्तमान पीढ़ी को अपने ऐतिहासिक साहित्य से जोड़ने का प्रयास है। कह सकते हैं कि भारत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं का सशक्तीकरण न केवल सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध कर रहा है, बल्कि रोजगार, तकनीकी विकास और शिक्षा के क्षेत्र में नए अवसर भी प्रदान कर रहा है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत 22 भारतीय भाषाओं में सरकारी पोर्टल्स उपलब्ध कराए गए हैं, जो अधिक से अधिक लोगों को सरकारी सेवाओं से जोड़ने में सहायक हैं। इस पहल से क्षेत्रीय भाषाओं में जानकारी की पहुंच बढ़ रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंच पाता है।

रोजगार सृजन : भारतीय भाषाओं का संवर्धन रोजगार के नए अवसरों का माध्यम बन रहा है। हिंदी और अन्य भाषाओं का संरक्षण न केवल सांस्कृतिक समृद्धि के लिए आवश्यक है, बल्कि यह देश के विभिन्न उद्योगों में रोजगार सृजन का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। भारतीय भाषाओं में अनुवाद, शिक्षा, मीडिया, मनोरंजन और प्रशासनिक क्षेत्रों में बढ़ते रोजगार के अवसरों से भारतीय युवाओं को नई दिशा और अवसर प्राप्त हो रहे हैं। भारत में बहुभाषी समाज के कारण अनुवाद का कार्य एक प्रमुख उद्योग बन चुका है। हिंदी शब्दसिंधु शब्दकोश और तकनीकी अनुवाद की पहल से कई नए अनुवादक और भाषा विशेषज्ञों की आवश्यकता उत्पन्न हो रही है। सरकारी दस्तावेज, वेब सामग्री और अन्य तकनीकी दस्तावेजों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए कुशल अनुवादकों की मांग तेजी से बढ़ी है।

भारत में बढ़ती डिजिटल साक्षरता और भारतीय भाषाओं में सामग्री की बढ़ती मांग को देखते हुए कई ई-लर्निंग प्लेटफार्म भारतीय भाषाओं में कोर्स सामग्री उपलब्ध कराने लगे हैं। यह शिक्षकों, अनुवादकों और सामग्री निर्माताओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ा रहा है। भारतीय भाषाओं में शैक्षिक सामग्री की बढ़ती मांग से अनेक शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यों का सृजन हो रहा है। साहित्यिक समृद्धि के दृष्टिकोण से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में लेखन के लिए नए लेखकों और संपादकों की मांग तेजी से बढ़ रही है। हिंदी शब्दसिंधु शब्दकोश जैसे प्रयासों से लेखकों को अपने लेखन में सही शब्दों के प्रयोग में मदद मिलेगी, जिससे साहित्य और प्रकाशन के क्षेत्र में सुधार और अवसर मिलेंगे।

आगे की राह : भारत में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के सशक्तीकरण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन इस दिशा में सतत प्रयास और भी आवश्यक है। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं का समावेश बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि युवा पीढ़ी अपनी मातृभाषा के महत्व को समझे और वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना सके। इसके अलावा तकनीकी संसाधनों का विस्तार करते हुए एआइ और मशीन लर्निंग के माध्यम से हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के अनुवाद को और सरल बनाया जा सकता है, जिससे यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा कर सके।

हिंदी के वैश्विक विस्तार की राह में चुनौतियां

हिंदी के वैश्वीकरण में कुछ चुनौतियां भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी चुनौती इसका विविधता से भरा स्वरूप है। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की विभिन्न बोलियां और रूप प्रचलित हैं। यह क्षेत्रीय विविधता हिंदी के प्रसार में बाधा नहीं, बल्कि इसके समृद्धि का संकेत हो सकती है, लेकिन इसे एक वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए एक सर्वमान्य मानकीकृत रूप की आवश्यकता है। इसके अलावा, हिंदी के लिए एक वैश्विक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली का निर्माण किया जाना भी आवश्यक है, ताकि विदेश में हिंदी सीखने और पढ़ाने की सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकें।

हिंदी के वैश्विक विकास के संदर्भ में एक अन्य चुनौती तकनीकी नवाचारों और अनुवाद सुविधाओं की कमी है। जबकि हिंदी में साहित्य और सांस्कृतिक धरोहर का असीमित खजाना मौजूद है, इसे आधुनिक वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी साधनों और अनुवाद प्रौद्योगिकी का विकास आवश्यक है। इसके लिए सरकार और तकनीकी कंपनियों के बीच सहयोग की भी आवश्यकता है, ताकि हिंदी को विभिन्न वैश्विक भाषाओं के साथ संवाद के स्तर पर खड़ा किया जा सके।

हिंदी का अंतरराष्ट्रीय भाषा के रूप में विकास भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा। यह भाषा न केवल संवाद का माध्यम बनेगी, बल्कि यह भारतीय समाज और संस्कृति के वैश्विक प्रचार-प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हिंदी के माध्यम से भारत का संस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव बढ़ेगा, जिससे देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी सुदृढ़ होगी। आज के डिजिटल युग में हिंदी का प्रभाव वैश्विक स्तर पर बढ़ रहा है। इंटरनेट मीडिया, वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स पर हिंदी में सामग्री की उपलब्धता से हिंदी भाषी लोगों की संचार की जरूरतें पूरी हो रही हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, हिंदी विश्व के 150 से ज्यादा देशों में बोली जाती है। दिलचस्प बात यह है कि हिंदी विश्व के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई भी जाती है। पूरे विश्व की बात करें तो लगभग एक अरब लोग हिंदी बोलते, लिखते और समझते हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग ने हिंदी भाषा के भविष्य के संबंध में भी नई राहें खिड़ाई हैं। तकनीकी विकास के इस युग में हिंदी का स्थान भी मजबूत हुआ है। गूगल, फेसबुक और एक्स जैसे प्लेटफार्म्स पर हिंदी उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की उपलब्धता और मांग बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार, भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं का एक बड़ा हिस्सा हिंदी में सामग्री पढ़ता और साझा करता है। वर्ष 2021 में हिंदी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 60 करोड़ से अधिक हो गई थी, और यह संख्या अगले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ने की संभावना है। गूगल के अनुसार, भारत में अंग्रेजी भाषा में जहां विषयवस्तु निर्माण की गति 19 प्रतिशत है तो हिंदी के लिए यह आंकड़ा 94 प्रतिशत है।

अतः हिंदी को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने की दिशा में सरकार और समाज का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। सरकार को यह पहल हिंदी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। हिंदी का वैश्विक मंच पर उदय न केवल एक भाषाई परिवर्तन है, बल्कि यह एक संस्कृतिक-सामाजिक परिवर्तन का भी संकेत है। यह एक नई दिशा की ओर संकेत करता है, जिसमें हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक पहचान का प्रतीक बनेगी। आने वाले वर्षों में हिंदी निस्संदेह वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति की मजबूती से दर्ज कराएगी और भारत को एक सशक्त सांस्कृतिक और भाषाई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। (कैलाश विश्नोई)

खरी-खरी

प्रयोगवादी होने के परिणाम

भूकेन्द्र सत्तैर

प्रयोग बिना विज्ञान विषय की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि विज्ञान थ्योरी कम, प्रैक्टिकल अधिक वाला विशेष ज्ञान है। किशोरवय विद्यार्थी सोशल साइंस में भले बॅक मार क्रिकेट टूर्नामेंट का मैच देखने चला आए, लेकिन साइंस के परिवाद में झक और मन मारकर बैठना ही पड़ता है। खासकर तब जब प्रयोगशाला में प्रयोग करवाए जा रहे हों।

वैसे प्रयोग अब केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रहे, ये साहित्य, राजनीति, खेल... हर क्षेत्र में किए जा रहे हैं। साहित्य में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन 'अज्ञेय' को प्रयोगवाद का जनक माना गया है, क्योंकि उन्होंने भाषा के स्तर पर कविता में अनेक प्रयोग किए। इसी क्रम में मुक्तिबोध भी कविता में नए प्रयोग करते नजर आए।

हमारे देश की राजनीति वंशवादी रही है, माने पिता, पुत्र, पोता से धोता तक भैया जी जिंदाबाद। लेकिन बीते कुछ वर्षों से इधर भी प्रयोग देखने को मिले हैं। नेता पुत्रों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। यह बात और है कि कई भतीजे चाचाओं को चा... की चूं बाई चपलक चूं बाई बुलवा चुके हैं। जवानी की धड़ी हो नहीं, बुढ़ापे की छड़ी तक छुड़ाकर ले भागे हैं। अब राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा, यूं कहें कि बनने नहीं दिया जा रहा, राजा वही बन रहा है जिसमें योग्यता होती है। सियासी काबिलियत क्या होती है सबको पता है।

आखिर में बात करते हैं क्रिकेट की। भारत के राष्ट्रीय खेल बन बैठे क्रिकेट में बीते कुछ समय से निस नए प्रयोग हो रहे हैं। होना तो था कि तीनों फार्मेट की तीन अलग टीमें तैयार की जाएं, लेकिन लगता है एक फटाफट फार्मेट की टीम सभी फार्मेटों में आजमाई जा रही हैं, जैसे कच्ची पगडंडी हो या पक्की सड़क टाप गियर में गाड़ी डालकर बस तू दौड़ाए जा। वैसे जबसे आइपीएल आया, खिलाड़ी ड्यूटी से ज्यादा ओवर टाइम पर ध्यान देने लगे हैं। फटाफट क्रिकेट फटाफट नगदीकरण। राष्ट्रीय भावना पर खेल भावना जैसे हावी हो गई हैं। बहरहाल, प्रयोगवादी होना अच्छा है, लेकिन गौरवशाली परंपरा अक्षुण्ण रहे इसका भी ध्यान रहे।

पोस्ट

जाने-माने अमेरिकी उद्यमी एलन मस्क ने जो-जान से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में अभियान चलाया, लेकिन अमेरिका में कोई भी यह नहीं कहेगा कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ एलन मस्क के लिए काम करते हैं।
अरविंद चोटिया@arvindchotia

कमला हैरिस भले ही बहुत महान नेता न हों, लेकिन अमेरिका के 235 वर्षों के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी महिला का राष्ट्रपति न बनना उस देश के बारे में बहुत कुछ कह देता है। सागर@sagarcasm

अमेरिकी चुनाव का एक सबक यह भी है कि हलीवुड सितारों और सेलेब्रिटियों का जमाना अब्बो लिए उतना मदहाश नहीं हो सकता, जितना तीन-चार प्रतिबद्ध लोगों का पिद्दल से प्रचार, जो आपका संदेश दूर-दूर तक पहुंचा दें। यही बात ब्रांड्स पर भी लागू होती है।
रिकी केज@rickykej

ध्रुव जुरेल टी-20 में फिनिशर की भूमिका में खेलते हैं तो रेड बॉल यानी टेस्ट क्रिकेट में वह बड़े मजबूत दावेदार नजर आते हैं, जो एकदिवसीय क्रिकेट पर भी छाप छोड़ने में सक्षम हैं। इतनी कम उम्र में उनकी रेंज बहुत व्यापक है। उम्मीद है कि वह अपने कौशल को निरंतर निखारते रहेंगे।
कार्तिक राज@kartcric

जागरण जनमत

क्या डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना भारत के लिहाज से अच्छा है?

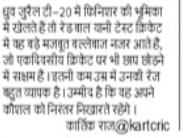

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल
क्या पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना करने से उसका जलाना रुकेगा?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

मुर्दा गड़ा उखाड़ने वाली उमर सरकार,
कोशिश करके देख लो होगी यह बेकार।
होगी यह वेकार समझ लो बबली-बंटी,
अब लौटेगी यार कभी ना ढ़ी सेवेटी।
अलग ले यह आघ वाली है जिसमें गूदी,
अब्दुल्ला जी आप उखाड़ो केवल मुर्दा!
– ओमप्रकाश तिवारी

शशि शेखर
संपादकीय प्रभारी, रांची

झारखंड डायरी

दोनों ओर से चुनावी घोषणाओं की बरसात

झारखंड में 13 और 20 नवंबर को दो चरणों में होने वाले 81 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव में मुख्यतः दो गठबंधनों के बीच ही मुकाबला होना अब तय है। 81 सीटों के लिए कुल 1211 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 1081 पुरुष, 128 महिला एवं दो प्रत्याशी ट्रांसजेंडर हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर चुनाव होना है। दोनों गठबंधन अपने घोषणा पत्रों के जरिए झारखंड की जनता के मन को बदलने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गत तीन नवंबर को रांची में इसे जारी किया था। इसमें कई लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं। इसमें हर जाति- हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी करते हुए अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर करेंगे। उनका आशय रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों से था।

इतना ही नहीं, अमित शाह ने आश्वस्त किया कि झारखंड में भी यूसीसी (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू होगा, लेकिन इसके दायरे में यहां के आदिवासी नहीं आएंगे। उनकी रीति-रिवाज-परंपरा पर कोई आंच नहीं आएगी। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं के पचास लाख रुपये तक की संपत्ति की खरीद पर मात्र एक रुपये का स्टांप शुल्क लगेगा। उल्लेखनीय है कि पिछली खुद्दर सरकार ने इसे लागू किया था, लेकिन हेमंत सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया। इस योजना से मध्यमवर्गीय लोगों को बहुत राहत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े समुदाय को भी साधने की कोशिश की है। उसने वादा किया है कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण देगी। पिछड़े समुदाय के लोग इसकी लंबे समय से मांग कर रहे थे। हालांकि इस बात को हेमंत सोरेन ने भी दोहराया है। इसी तरह वृद्ध, विधवा एवं दिव्यांगों की पेंशन राशि 2500 रुपये प्रति माह करने की बात कही है। वहीं, हेमंत सरकार की मंईयां योजना की तर्ज पर भाजपा गोगो दीदी योजना से प्रतिमाह 2100 रुपये देने की घोषणा कर चुकी है। मालूम हो कि मंईयां योजना के तहत लाभार्थियों को एक हजार रुपया प्रतिमाह दिया जाता है, लेकिन जैसे ही भाजपा इसकी काट में गोगो दीदी योजना लेकर आई, हेमंत सरकार ने भी इसकी राशि 2500 रुपये प्रतिमाह तक करने की घोषणा कर दी और कहा कि दिसंबर से ही यह बढ़ी हुई राशि मिलेगी।

'तू डाल-डाल और मैं पात-पात' की तर्ज पर हेमंत सरकार ने अपने सहयोगी दलों के साथ पांच नवंबर को घोषणा पत्र जारी कर दिया। हेमंत सोरेन ने इसमें अपनी बहुत सी पुरानी बातें ही दोहराई कि वर्ष 1932 का खतियान और सरना धर्म कोड लागू करेंगे। ओबीसी आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करेंगे। 450 रुपये में रसोई गैस सिलिंडर देने का वादा भी है। हेमंत सोरेन कहते हैं कि हमारी गारंटी भारतीय जनता पार्टी की तरह जुमला नहीं है। सरना कोड आदिवासी भावनाओं से जुड़ा मामला है। हेमंत सोरेन पिछले पांच साल से इसे बार-बार उठाते और दोहराते रहे हैं, लेकिन भाजपा ने भी इस चुनावी समर में इस प्रकरण के निदान की बात कही है। असम के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि भाजपा की सरकार बनी तो सरना कोड का मसला मिल बैठकर हल कर लेंगे। माटी, बेटी और रोटी की रक्षा की बात भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में खुलकर कर रही है। भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है।

दोनों गठबंधन दलों के सामने चुनौती कम नहीं है। जोड़तोड़ से लेकर तोड़फोड़, सब जारी है। मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की जा रही है। भाजपा के सामने आदिवासी मतदाता भी चुनौती हैं। इसलिए अपना घोषणा पत्र जारी करते समय धरती आबा बिरसा मुंडा को याद रखा। उसने भगवान बिरसा मुंडा समेत आदिवासी नायकों के स्मारक बनाने की घोषणा की है। इसी तरह भगवती काली देव और देवघर के श्रावणी मेले को विश्व स्तरीय बनाने की भी बात कही है। उसने आदिवासी के साथ दलित, पिछड़े, किसान, महिला पर भी फोकस किया जो जीत के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। दोनों प्रमुख गठबंधनों के घोषणा पत्रों के केंद्र में महिला, आदिवासी, दलित, किसान और पिछड़े हैं। योजनाओं के केंद्र में भी यहीं हैं। देखना यह है कि झारखंड की जनता किस गठबंधन पर अपना विश्वास जताती है। इसके लिए हमें 23 नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा।

रांची में भाजपा का संकल्प पत्र जारी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह (बीच में) एवं अन्य नेता। फाइल

हिमाचल प्रदेश डायरी

जमीन पर ही रहे उड़ता हिमाचल

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

वह हल्के बादलों वाली एक सुबह थी। एक खुले क्षेत्र में धांग के पौधे थे, जिनकी पत्तियां एक युवा हाथों में मल रहा था। पहले ये दृश्य धूमपान के दृश्यों की तरह आम होते थे, परंतु अब कभी-कभार दिखते हैं, इसलिए मैं रुका। यह जानते हुए भी कि वह क्या कर रहा है, उसे पूछा कि क्या कर रहे हो? तुरंत यह कि उसके चेहरे पर झेंप नहीं थी, निर्लज्ज हंसी थी। उसने कहा, 'जुगाड़ कर रहा हूं सर और क्या? प्लीज करने दें।' मैंने उसे डांट कर भगा दिया। हाल में सुनने में आया कि वह नहीं रहा। सुनते हैं, पत्नी और बच्चे हैं समय का चाबुक झेलने के लिए। काश... किसी ने उसे बीमार मान कर उपचार का प्रयास किया होता...।

कौंध जाते हैं वे शीर्षक, जो कहते हैं कि अमुक स्थान से अमुक व्यक्ति चिट्टे के साथ गिरफ्तार... किसी संस्था संचालक के घर से प्रतिबंधित दवाएं मिलीं... ड्रग तस्करी के मामले में दंपती गिरफ्तार... नशे के अत्यधिक सेवन से युवक की मौत। और पंजाब से सटे क्षेत्र से तो ऐसी सूचनाएं भी आती हैं कि युवक या युवती से चिट्टा बरामद... जो गुप्त में छुपा रखा था। मानव शरीर के अपमान और ढुलयोग की पराकाष्ठा संभवतः यही है। नशा तस्करों की संपत्ति जब्त की जा रही है, करोड़ों रुपये बरामद हो चुके हैं। नशे की आपूर्ति की बंद या बाधित करने के प्रयास तो हो रहे हैं, किंतु मांग में कमी आए, ऐसे प्रयास अब भी अपर्याप्त हैं।

संभवतः यही सोच कर प्रदेश के राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल की अध्यक्षता में राजभवन में नशा उन्मूलन को समर्पित कार्यशाला का आयोजन हुआ। साथ ये पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह। सहमति यह बनी कि पंचायतें युवाओं को नशे की दलदल में धंसने से रोकने का दायित्व निभाएं। ऐसा देखने में आया है कि राज्यपाल पहले भी इस विषय पर अपनी गंभीरता प्रकट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री का भी यह सरोकार है। अब सरकार का पंचायती राज विभाग भी इस दायित्व को निभाने के लिए आगे आया है, तो यह अच्छी बात है। जहां समाजिक स्तर पर कुएं में ही भांग पड़ी हो, वहां स्वच्छ पानी की कुछ बूंदें भी सहारा होती हैं... तिनके का ही सही। लेकिन पंचायतें का यह तिनका निष्ठा से कार्य करे तो मजबूत शाखा सिद्ध हो सकता है। दोनों राजनीतिक दल भले ही इस समय को, स्वयं को सैने का दूसरे को पत्थर का सबित करने वाला समझें, किंतु सामाजिक स्तर पर उस ताप को समझें जिससे झुलस कर कोई पिता पुलिस को सूचना देता है कि मेरा पुत्र चिट्टे का धंधा करता है। उस माता के आंसुओं को नदी निश्चित रूप से सूख चुकी होगी जो संयत स्वर में पुलिस को फोन करती है कि मेरे बेटे को कोई नशा देने आया है, आप इन दोनों को गिरफ्तार कर लें। जब अभिभावक भी इस विभीषिका को समझते हुए स्वयं आगे आ रहे हैं तो पंचायतों को सुधारात्मक भूमिका निभाने में संकोच क्यों हो? यह विषय मत जुटाने या गंवाने का नहीं है, उन पौधों को पेड़ बनने तक निगरानी में रखने का है जिनसे देश प्राणवायु की अपेक्षा करता है। उस बुढ़ापे को सपर्श देने का है, जो इस दुख में झुलस जाता है कि उसकी लाठी को नशे का दीमक खा रहा है।

सब जानते हैं कि नशे की समस्या दो कोणों से देखी जाती है। आपूर्ति को रोकना होता है और मांग को भी। आपूर्ति को रोकने के लिए किए गए प्रयास विधानसभा में भी गूंजते हैं। राज्य में जनवरी 2023 से लेकर 31 जुलाई, 2024 तक नशे की ओवरडोज से 11 लोग मरे हैं। इस दौरान, नशे के करीब तीन हजार मामले दर्ज हुए। और नशे की अर्थव्यवस्था का डरावना गणित देखें कि केवल सात मामलों में 14 लोगों की 11 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की गई है। मौत के ये वे मामले हैं जो सरकारी कागजों तक पहुंचे। कितने ऐसे होंगे जो 'गलती से जहरीली दवा पीने' की श्रेणी में होंगे या किसी भी श्रेणी में नहीं होंगे।

लोकलाज का भय : हिमाचल प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हाल ही में विधानसभा में कहा था कि प्रदेश में भी नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय खुलना चाहिए। बिलकुल। बात रखी जानी चाहिए। निश्चित रूप से ये सब आपूर्ति रोकने के उपाय हैं जो जारी रहें, किंतु मांग भी रोकी जाए। इसके लिए पंचायतों के साथ ग्रामसभाओं और समाज की पहली इकाई व्यक्ति की सहभागिता भी आवश्यक है। खेलने के स्थल हों, घरों में उचित और पारदर्शी संवाद हो, नशे से बीमार लोगों के पुनर्वास के लिए अधिकाधिक प्रयास हों, दुकानों में चल रहे पुनर्वास केंद्र उर्फ यातना शिविर बंद हों, नियमित निगरानी हो। समाज और अभिभावकों का ध्यान ठीक स्थान पर रहे तो किसी इंजीनियर को पटवारी बनाने की नौबत न आए और ऐसा भी न हो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के न्यू मीडिया विषय में एक भी छात्र शोध परीक्षा को उत्तीर्ण न कर पाए।

देखना यह है कि पंचायती राज संस्थाएं अपने नए दायित्व को कितनी गंभीरता के साथ निभाती हैं। सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि पंचायतों को सरकारी विभागों की कितनी सहायता मिल पाती है। उड़ते हिमाचल प्रदेश की जमीन पर ही रहना होगा।

शिमला स्थित राजभवन में कुल्लार को नशीले पदार्थों से निजात देने पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर कार्यशाला में राज्यपाल शिवप्रताप शुक्ल एवं उनमन जनप्रतिनिधि। फाइल

****